

476

विशेष न्यायालय विधेयक, 1978

1 दिसंबर, 1978

[न्यायमूर्तिगण वाई. वी. चंद्रचूड़, सी. जे., पी. एन. भगवती, वी. आर. कृष्णा अय्यर, आर. एस. सारकारिया, एन. एल. अंतवालिया, एस. मुर्तजा फजल अली और पी. एन. सिंहल]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 143 - का दायरा।

विशेष न्यायालय विधेयक-यदि संसद के पास विधेयक को अधिनियमित करने की शक्ति है-क्या इसका कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन करता है।

संसद में एक विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य द्वारा पेश किए गए विशेष अदालत विधेयक 1978 के मसौदे में पर्याप्त संख्या में अदालतों का निर्माण करने का प्रयास किया गया है जिन्हें विशेष अदालत कहा जा सकता है। विधेयक में प्रावधान है कि एक विशेष अदालत ऐसे मामलों का संज्ञान लेगी या उन पर मुकदमा चलाएगी जो उसके समक्ष स्थापित किए गए हैं या उसमें प्रदान किए गए तरीके से उसे हस्तांतरित किए गए हैं। यदि केंद्र सरकार की राय है कि उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पद धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा आपातकाल की अवधि के दौरान कथित रूप से किए गए अपराध की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है

भारत में और यह कि उक्त अपराध से अधिनियम के तहत निपटा जाना चाहिए, यह हर उस मामले में उस आशय की घोषणा करेगा जिसमें उसकी राय है। केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है, विधेयक के खंड (7) में प्रावधान है कि एक विशेष गणना की अध्यक्षता भारत में उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश या एक व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसने भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया है। खंड 10 (1) में प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक विशेष अदालत के किसी भी निर्णय या आदेश से तथ्य और कानून दोनों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया। 143 (1) इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कि क्या विशेष न्यायालय विधेयक 1978 या इसके कोई भी प्रावधान, यदि अधिनियमित किए जाते हैं, तो संवैधानिक रूप से अमान्य होंगे।

संदर्भ की स्थिरता के बारे में प्रारंभिक आपत्तियां इस आधार पर उठाई गईं कि (i) संदर्भ एक काल्पनिक और सट्टा चरित्र का था और अस्पष्ट, सामान्य और सर्वव्यापी था; (ii) चूंकि संसद ने विधेयक को अपने नियंत्रण में ले लिया था, इसलिए विधेयक की संवैधानिकता पर निर्णय लेना उसका अनन्य कार्य है और यदि न्यायालय उस प्रश्न को अपने विचार और रिपोर्ट के लिए

वापस ले लेता है, तो यह संसद के कार्यों और विशेषाधिकारों का अतिक्रमण होगा, (iii) यदि संदर्भ पर विचार किया जाता है तो यह अनुच्छेद के हितकारी प्रावधान का स्थान ले लेगा। 32 (iv) इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार के बावजूद संसद के लिए विधेयक पर चर्चा करने और संशोधन के साथ या उसके बिना इसे पारित करने या न करने के लिए खुला रहेगा, और (v) संदर्भ ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रश्न उठाए जिनका न्यायालय को उत्तर देने से बचना चाहिए।

पकड़ना: [प्रति बहुमत-Y। वी. चंद्रचूड़, सी. जे., पी. एन. भगवती, आर. एस. सरकारिया और एस. मुर्तजा फजल अली, जे. जे.]

1. (क) यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रश्न जिस पर इस न्यायालय की राय अनुच्छेद के तहत मांगी गई है। 143 (1) वास्तव में यह उत्पन्न हुआ होगा कि राष्ट्रपति संदर्भ देने के लिए सक्षम है यदि वह संतुष्ट है कि प्रश्न में आरई है:

उत्पन्न हुआ या उत्पन्न होने की संभावना है। अनुच्छेद के तहत न्यायालय का सादा कर्तव्य और कार्य। 143 (1) जिस प्रश्न पर निर्देश दिया गया है, उस पर विचार करना और राष्ट्रपति को अपनी राय देना है, बशर्ते कि प्रश्न पर निर्णय लेने में सक्षम हो और यह निर्णय लेने के लिए न्यायालय की शक्तियों के भीतर आता हो। यदि किसी भी कारण से न्यायालय इस प्रश्न का उत्तर देना उचित या संभव नहीं समझता है तो वह इसका उत्तर देने में बाधाओं को इंगित करके संदर्भ को वापस करने का हकदार होगा। इस न्यायालय का किसी संदर्भ का उत्तर देने से इनकार करने का अधिकार केवल उपयोग किए गए विभिन्न वाक्यांशों से नहीं निकलता है।, " खंड (1) में "और खंड (2) में" होगा "। खंड (2) के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में भी, न्यायालय बिना उत्तर दिए संदर्भ को वापस करने के लिए उचित हो सकता है, यदि वह एक वैध संदर्भ पाता है।

इसका कारण यह है कि प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है। [502 सी-एफ]

(ख) यह नहीं कहा जा सकता है कि संदर्भ काल्पनिक या अटकलबाजी का है।

चरित्र इस आधार पर कि विधेयक अभी तक एक अधिनियम नहीं बना है। अनुच्छेद के तहत प्रत्येक संदर्भ का संग्रह। 143 एक संदर्भ या शर्तों का निरंतर अस्तित्व होना चाहिए जिसके आधार पर कानून या तथ्य का प्रश्न उत्पन्न होता है या उत्पन्न होने की संभावना है। लेकिन परिवर्तन की संभावना, यहां तक कि एक मौलिक परिवर्तन की संभावना, अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती है। 143 अटकलबाजी या काल्पनिक। वर्तमान मामले में विधेयक के अस्तित्व के बारे में कोई अटकलें नहीं हैं और इसकी सामग्री के बारे में कुछ भी काल्पनिक नहीं है जैसा कि वे आज हैं। इस विधेयक में भविष्य में बदलाव हो सकते हैं लेकिन अनुच्छेद सहित संविधान में भी बदलाव हो सकते हैं। 143 , जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने

इस न्यायालय को निर्देश दिया है। पहली संभावना संदर्भ को अटकलबाजी या काल्पनिक नहीं बना सकती है क्योंकि बाद की संभावना इसे ऐसा बना सकती है। विशेष अदालत विधेयक किसी के भी देखने और देखने के लिए रक्त और मांस में है।

जाँच करें। यह उस संदर्भ को कायम रखता है, जो राष्ट्रपति की संतुष्टि पर आधारित है कि विधेयक की संवैधानिक वैधता के संबंध में एक प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है और यह प्रश्न ऐसी प्रकृति और सार्वजनिक महत्व का है कि इस पर इस न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है। [503 बी-ई]

(ग) एक संदर्भ जो विशिष्टता के साथ आधार को निर्दिष्ट नहीं करता है या

जिन आधारों पर संविधान के तहत विधेयक या इसके किसी भी प्रावधान पर हमला किया जा सकता है, उनका जवाब देना मुश्किल है क्योंकि यह उस विशिष्ट बिंदु या बिंदु का कोई संकेत नहीं देता है जिस पर न्यायालय की राय मांगी जाती है। यह उचित या वांछनीय नहीं है कि इस न्यायालय से किसी विधेयक या अधिनियम की संवैधानिकता की बारी-बारी से जांच शुरू करने के लिए कहा जाए। इस तरह के पाठ्यक्रम के लिए संविधान के तहत सभी उचित रूप से कल्पना की जा सकने वाली चुनौतियों के संबंध में उन्मूलन की प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है। अनुच्छेद के तहत एक संदर्भ का जवाब देते समय इस न्यायालय से इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। 143 , यदि विधेयक कानून बन जाता है तो उसकी वैधता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के किस प्रावधान का उपयोग किए जाने की सबसे अधिक संभावना है। अटकलबाजी या काल्पनिक प्रश्न व्यर्थ हैं और यह सिद्धांत के विपरीत, असुविधाजनक और अव्यवहारिक है कि ऐसे प्रश्नों पर राय दी जानी चाहिए। जब भी अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय को कोई निर्देश दिया जाता है। 143 संविधान के अनुसार, न्यायालय की राय के लिए विशिष्ट प्रश्न तैयार करने का ध्यान रखा जाना चाहिए। तत्काल संदर्भ में विशिष्ट प्रश्नों को संदर्भ की शर्तों के भीतर समझे जाने पर विचार करना संभव है, लेकिन यह जोखिम कि एक अस्पष्ट और सामान्य संदर्भ को बिना उत्तर दिए वापस किया जा सकता है, वास्तविक है और उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए जिनका कर्तव्य संदर्भ तैयार करना है। 1505 ई-जी, 507 बी]

(घ) यह तर्क कि चूँकि संसद ने विधेयक को अपने अधिकार में ले लिया है।

* * * * ई के प्रावधानों की संवैधानिकता पर निर्णय लेने के लिए अनन्य कार्य विधेयक के तहत शक्तियों के विभाजन की योजना के बारे में जागरूकता की पूर्ण कमी को दर्शाता है संविधान, न्यायालय का संबंध है, न कि काल्पनिक सिद्धांतों के आधार पर व्यक्तिगत भविष्यवाणियाँ, लेकिन संविधान और दर्शन की योजना के साथ सोफिया इसे अंतर्निहित करता है। सिद्धांत दृढ़ता से और बुद्धिमानी से कॉन में अंतर्निहित है। कथन कि विधि की नीति और इसे पारित करने की समीचीनता मामले हैं विधायिका के लिए निर्णय लेने के लिए कब, कानूनों की व्याख्या और

संबंधित प्रश्न उनकी वैधता विशेष सलाहकार या न्यायनिर्णायक कार्यों के अंतर्गत आती है न्यायालय [507 डी-ई]

(ई) इस तर्क में समान रूप से कोई बल नहीं है कि यदि न्यायालय वापस ले लेता है विधेयक के विचाराधीन रहने के दौरान इसके विचार के लिए विधेयक की वैधता का सवाल संसद के समक्ष विचार करते हुए, न्यायालय संसद के कार्यों और विशेषाधिकारों का अतिक्रमण करेगा। राष्ट्रपति ने एक संदर्भ दिया है अनुच्छेद के तहत। 143 (1) और न्यायालय विचार करने के लिए एक संवैधानिक दायित्व के तहत है

राष्ट्रपति को निर्देश और प्रतिवेदन। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय द्वारा संसद के किसी विशेष कार्य या विशेषाधिकार का अतिक्रमण किया गया है। यह प्रश्न कि क्या विधेयक के प्रावधान किसी संवैधानिक अनिवार्यता से ग्रस्त हैं, इस न्यायालय के वैध अधिकार क्षेत्र में आता है। संसद में हो सकती है चर्चा

और विधेयक पर बहस करते हैं लेकिन किसी कानून की वैधता पर अंतिम निर्णय लेना पड़ता है न्यायालय का हो, न कि संसद का। किसी भी पाठ के अभाव में या यह दिखाने वाला प्राधिकरण कि ब्रिटिश संसद के विशेषाधिकार क्या हैं

न्यायालय के समक्ष जिस प्रकार का मामला है, यह कहना असंभव है कि संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यह तर्क कि विधेयक की संवैधानिक वैधता पर विचार करना व्यर्थ होगा क्योंकि न्यायालय जो भी विचार ले सकता है, वह अभी भी संसद के लिए विधेयक पर चर्चा करने के लिए खुला रहेगा।

और इसे पास करना या न करना, अवास्तविक आधार पर आगे बढ़ता है। हालाँकि इस न्यायालय की राय न तो संसद को आगे बढ़ने से रोक सकती है।

विधेयक और न ही इसे छोड़ने से, यह नहीं कहा जा सकता है कि भले ही न्यायालय मान ले

यह विधेयक असंवैधानिक होने के कारण संसद उन दोषों को दूर किए बिना इसे पारित करने के लिए आगे बढ़ेगी जिनसे यह पीड़ित है। [508 एफ-एच; 510 बी]

(च) यह तर्क कि संदर्भ विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक प्रश्न उठाता है

बिना किसी बल के। विधेयक की नीति और प्रस्तावक का उद्देश्य उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित सुनिश्चित करना हो सकता है।

आपातकाल की अवधि से संबंधित कुछ अपराध करने का आरोप। हालाँकि, राष्ट्रपति ने न्यायालय से उन्हें इस बारे में सलाह देने के लिए नहीं कहा है कि

विधेयक को पारित करने की वांछनीयता या इसमें अंतर्निहित नीति की दृढ़ता।

यह प्रश्न कि क्या विधेयक या इसके कोई भी प्रावधान संवैधानिक रूप से अमान्य हैं, राजनीतिक प्रकृति का प्रश्न नहीं है जिससे न्यायालय को खुद को रोकना चाहिए।

जवाब देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इस बारे में राय के लिए संदर्भित प्रश्न

न्यायालय विशुद्ध रूप से कानूनी और संवैधानिक मुद्दों को उठाता है जो इस न्यायालय का निर्णय लेने का अधिकार और कार्य है। [510 डी-एफ]

विधेयक के खंड 2,6 और 10 (1) विधायी क्षमता के भीतर हैं।

संसद से। [522 एच]

2. (क) प्रदान करने के लिए संसद की विधायी क्षमता को चुनौती 246 (2) समवर्ती सूची की प्रविष्टि 11 ए के साथ पढ़ें, संसद ने स्पष्ट रूप से कहा है संविधान और संगठन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, कि कहने का मतलब है, स्पीशिया का निर्माण और स्थापना: अदालतें। विधेयक का खंड 2, इसलिए यह संसद की अधिनियमित करने की क्षमता के भीतर है। सीएल द्वारा। 10 (1) संसद के पास स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करने की क्षमता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ भी निहित एक अपील 479

तथ्य और विधि दोनों पर किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से उच्चतम न्यायालय को अधिकार के रूप में निहित होगा। एक कानून जो सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करता है, स्पष्ट रूप से उस न्यायालय के "अधिकार क्षेत्र और शक्तियों" के संबंध में एक कानून है। [517 सी-डी; 521 ए-बी]

(ख) यह तर्क कि संविधान ने एक के लिए प्रचुर मात्रा में प्रावधान किया है

न्यायालयों के पदानुक्रम में, संसद को एक न्यायालय या न्यायालयों का एक वर्ग बनाने की अनुमति नहीं है जो उस योजना के भीतर नहीं आता है या उस योजना में फिट नहीं होता है। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विशेष अदालतें बनाने की संसद की शक्ति पर इस तरह की सीमा लागू करने को उचित ठहराए। प्रविष्टि 11 ए के शब्द पर्याप्त रूप से व्यापक हैं जो संसद को न केवल उसी प्रकार और पदनाम के न्यायालयों की स्थापना करने में सक्षम बनाते हैं, जैसा कि प्रासंगिक पक्ष में संदर्भित किया गया है, बल्कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संबंध में प्रविष्टि में उल्लिखित सीमा के अधीन नए या विशेष न्यायालयों का गठन और आयोजन करने में सक्षम बनाते हैं। [524 ए एंड डी]

(ग) यह कहना सही नहीं है कि इस तथ्य के कारण कि विशेष न्यायालय

उच्च न्यायालयों का संवैधानिक दर्जा नहीं होगा और न ही वे अनुच्छेद के अर्थ के भीतर जिला न्यायालय हैं। 235, विशेष न्यायालयों के निर्माण की गणना न्यायिक स्वतंत्रता के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को नुकसान पहुँचाने या नष्ट करने के लिए की जाती है। [524 एफ]

3. (क) विशेष न्यायालय विधेयक द्वारा प्रदान किया गया वर्गीकरण वैध है।

और इसके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं ली जा सकती है। [537 ई]

(ख) आपातकाल की घोषणा का विषय नहीं है और न ही हो सकता है -

राष्ट्र के जीवन में सामान्य घटना। आपातकाल की अवधि के दौरान किए गए कथित अपराध अपने आप में एक वर्ग का गठन करते हैं और इसी तरह जिन व्यक्तियों पर उन अपराधों को करने के लिए अपने द्वारा आयोजित उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों का उपयोग करने का आरोप लगाया जाता है। यह न्यायालय आरोपों की सच्चाई या अन्यथा से संबंधित नहीं है, इसके सामने संकीर्ण प्रश्न यह है कि क्या, पहली बार में, वर्गीकरण कुछ गुणों या विशेषताओं पर आधारित है जो एक साथ समूहबद्ध सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं और न कि अन्य लोगों में जो छूट गए हैं। उस प्रश्न का उत्तर केवल एक और एक ही हो सकता है, अर्थात्, भारत में उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा आपातकाल के दौरान किए गए कथित अपराध एक वर्ग में अलग हैं। आपातकाल के आवरण ने एक अनूठा अवसर प्रदान किया

कानून के शासन को नष्ट करने और समाज पर राजनीतिक अपराधों को अंजाम देने के लिए ऐसे पदों के धारक। उस समूह से बाहर रह गए अन्य लोगों के पास न तो साधन थे और न ही ऐसा करने का अवसर, क्योंकि उनके पास आने वाले अधिकार की कमी थी

आधिकारिक पद से। इस प्रकार जिन व्यक्तियों को विशेष न्यायालयों के समक्ष मुकदमे के लिए विधेयक द्वारा अलग किया जाता है, उनमें समान विशेषताएं होती हैं और जो लोग उस समूह का पक्ष लेते हैं, उनके पास वे नहीं होते हैं। [538 बी; 540 ए-डी]

(ग) समूह के बाहर होने वाले अपराध मूल रूप से अलग प्रकार के होते हैं और आम तौर पर एक अलग प्रेरणा है। सुप का कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता है। मानव स्वतंत्रता का दबाव जब आपातकाल लागू नहीं होता है। द.सूप लोगों की स्वतंत्रता का दबाव सार्वजनिक होने पर अपराधों को आसानी से करने में मदद करता है। आलोचना को दबा दिया जाता है, पहचान का कोई डर नहीं होता है। जिन अपराधों का आरोप लगाया जाता है आपातकाल के दौरान प्रतिबद्ध होने के लिए उनके डिजाइन में तिरछे हैं और अपने उद्देश्य में चयनात्मक। इन्हें आम तौर पर पकड़ने और स्थायी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। राजनीतिक शक्ति; और वे व्यापक रूप से राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ निर्देशित हैं। द.एक उच्च सार्वजनिक पद का धारक जो रिश्वत लेता है वह खुद को समृद्ध करने के लिए ऐसा करता है। हालाँकि, यह सबसे अधिक निंदा

का पात्र है, लेकिन इस तरह के अपराध बुने नहीं जाते हैं राजनीतिक प्रेरणा के ताना-बाना से बाहर। समान कानून [1979] 2 एस. सी. आर. होना चाहिए।

एक ही स्थिति में सभी पर लागू होता है और विधायिका नुकसान या बुराई की डिग्री को पहचानने के लिए स्वतंत्र है। सार्वजनिक जीवन में शुद्धता हर समय और सभी स्थितियों में एक वांछित लक्ष्य है। लेकिन, यह न्यायालय एक अति विधायिका के रूप में नहीं बैठ सकता है और इस आधार पर वर्गीकरण को रद्द नहीं कर सकता है कि अन्य को इस आधार पर शामिल किया जाए कि उन्हें अच्छूता छोड़ दिया जाए, जब तक कि संवैधानिक प्रतिबंधों का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

[540 ई-एच]

(घ) यदि वर्गीकरण वैध है और इसका आधार विधेयक के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध रखता है, तो अनुच्छेद के तहत किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता है। 14 . वर्गीकरण में अनिवार्य रूप से उन लोगों को अधीन किया जाता है जो इसके भीतर नियमों और प्रक्रियाओं के एक अलग समूह के अधीन आते हैं, जो आमतौर पर सामान्य परीक्षणों पर लागू होने वाली प्रक्रिया की तुलना में अधिक निराशाजनक हो सकते हैं। लगभग सभी निर्णयों में, उन प्रश्नों पर जो विचार के लिए उत्पन्न होते हैं, विशेष कानूनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया स्पष्ट रूप से सामान्य परीक्षणों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया की तुलना में अधिक कठिन थी। लेकिन एक बार जब दोहरे परीक्षण के अनुप्रयोग द्वारा एक वर्गीकरण को बरकरार रखा जाता है, तो कठोर उपचार या नुकसानदेह प्रक्रिया के अधीनता अपनी प्रासंगिकता खो देती है, जिसका कारण अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए है। 14 , असमान लोग असमान व्यवहार की शिकायत नहीं कर सकते। वर्गीकरण का तात्पर्य अनिवार्य रूप से वर्गीकृत व्यक्तियों और उन लोगों के बीच भेदभाव है जो उस वर्ग के सदस्य नहीं हैं। यह एक वर्गीकरण का सार है कि वर्ग पर आम जनता पर पड़ने वाले कर्तव्यों और बोझों से अलग कर्तव्य और बोझ डाले जाते हैं। वर्गीकरण का विचार ही असमानता का है, इसलिए यह बिना कहे चला जाता है कि असमानता का मात्र तथ्य किसी भी तरह से संवैधानिकता के मामले को निर्धारित नहीं करता है। विशेष न्यायालय के समक्ष अभियुक्त पर रखे गए विधेयक के कुछ प्रावधानों में उन अभियुक्तों की तुलना में कुछ नुकसान हैं जिन्हें सामान्य न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए रखा जाता है।

अदालतें, जैसे कि कुछ अन्य प्रावधान उन्हें कुछ लाभ देते हैं जो

दूसरों को अस्वीकार कर दिया जाता है। [542 ई-एच]

प्रदेश, [1953] एस. सी. आर. 1188; केदार नाथ बाजोरिया बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य, [1954] एस. सी. आर. 30; असगराली नजराली सिंगापोरावालिया बनाम। राज्य बॉम्बे का, [1957] एस. सी. आर. 678; संदर्भित।

(ई) आपातकाल की अवधि के दौरान अपराध करने वाले व्यक्तियों का उन लोगों के साथ समूह बनाना, जिन पर आपातकाल की घोषणा से पहले कुछ अपराधियों की जांच करने का आरोप है, एक ही वर्ग में, उन व्यक्तियों को एक साथ जोड़ने के समान है जिनके पास समान गुण या विशेषताएँ नहीं हैं। विधायिका के लिए यह सोचना निर्विवाद रूप से तर्कसंगत है कि आपातकाल की अवधि के दौरान मानव स्वतंत्रता के दमन ने उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को गंभीर अपराध करने का अवसर प्रदान किया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने के लिए किए गए थे। आपातकाल की अवधि के दौरान किए गए कथित अपराधों को सुई जेनरिस के रूप में माना जा सकता है। हालाँकि, आपातकाल की घोषणा से पहले की गतिविधियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वे कार्य सार्वजनिक आलोचना के लिए खुले थे और घूँघटा से असुरक्षित थे।

आपातकाल। एक वर्गीकरण की वैधता का परीक्षण व्यापक रूप से किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब शुल्क कम समावेशिता का हो।

अपनी गतिविधियों की अवधि के संबंध में अपनी स्थिति के संदर्भ में व्यापक रूप से भिन्न विशेषताओं वाले व्यक्तियों को किसी भी उचित आधार पर एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। 25 जून से 27 फरवरी, 1975 तक आपातकाल की पूर्व-तिथि पूरी तरह से अवैज्ञानिक है और अपराधियों की जांच के मामले में एक कथित खोज से उत्पन्न तर्कहीन विचारों से उत्पन्न होती है। 27 फरवरी से 25 जून, 1975 की अवधि के संबंध में अपराधों और अपराधियों को उसी वर्ग में शामिल करना, जिनकी कथित गैरकानूनी गतिविधियों में आपातकाल की अवधि शामिल थी, बहुत ही कृत्रिम है।

1

कायम रखने के लिए। [545 सी-एच]

(च) इस सवाल का जवाब कि क्या, जिन पर आरोप लगाया गया है

आपातकाल से पहले किए गए अपराधों को उसी श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि जिन व्यक्तियों पर आपातकाल की अवधि के दौरान अपराध करने का आरोप है, उन्हें नकारात्मक होना चाहिए। [546 सी]

(छ) सी. एल. द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण। 4 (1) विधेयक के लिए वैध है

जिस सीमा तक केंद्र सरकार को आपातकाल की अवधि के दौरान उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा किए गए कथित अपराधों के संबंध में घोषणा करने का अधिकार है। यह वर्गीकरण अब तक अमान्य है क्योंकि इसमें 27 फरवरी से 25 जून, 1975 के बीच ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध शामिल हैं। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान

वर्गीकरण के तहत उन अपराधों और अपराधियों के संबंध में कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। [546 डी]

(ज) जहाँ तक उन लोगों का संबंध है जो उचित रूप से एक साथ समूहीकृत हैं, क्योंकि वर्गीकरण

यह वैध है, अनुच्छेद 14 के प्रयोजनों के लिए यह विचार करना अनावश्यक है कि क्या विधेयक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया से अधिक कठिन है। विशेष प्रक्रिया की कठोरता अनुच्छेद के तहत उत्पन्न होने वाले विचार में अप्रासंगिक होगी। 14 , इस कारण से कि वर्गीकरण मान्य है (इंगित सीमा तक)। लेकिन जहाँ तक कोई विशेष प्रावधान आकर्षित होता है, विधेयक को संविधान के अन्य प्रावधानों की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। [546 एफ; 547 डी]

4. (क) विधेयक में किसी एक से मामलों के हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।

विशेष न्यायालय से दूसरे को। इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति विशेष न्यायालयों में लोगों के विश्वास को कम कर सकती है। जिस तरह से एक न्यायाधीश स्वयं का आचरण करता है, वह पक्षपात का खुलासा कर सकता है; या एक न्यायाधीश वास्तव में पक्षपाती नहीं हो सकता है और फिर भी अभियुक्त को क्षीण परिस्थितियों के कारण एक उचित आशंका हो सकती है कि उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। एक आरोपी को मजबूर करना किसी न्यायालय की अधिकारिता के समक्ष प्रस्तुत होना, जो वास्तव में पक्षपाती है या जिसे यथोचित रूप से पक्षपाती माना जाता है, प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन है और निष्पक्षता से इनकार है। एक अन्य मामले में समीचीनता या सुविधा के लिए किसी मामले के हस्तांतरण की आवश्यकता हो सकती है, भले ही कोई पूर्वाग्रह शामिल न हो। [549 डी-ई]

(ख) उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश कोई अपवाद नहीं हैं। यद्यपि निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाज में सम्मान और सम्मान के पद पर आसीन हैं, फिर भी कोई भी संवैधानिक स्थिति के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है। 217 उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को एक विशेष आयु प्राप्त करने तक कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश सरकार की इच्छा के दौरान विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपना पद संभालेगा। आनंद सिद्धांत न्यायिक स्वतंत्रता का विध्वंसक है। विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो शक्ति और स्वतंत्रता का प्रदर्शन करते हैं, को [1979] 2 एस. सी. आर. द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।

482

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार और उसे जब चाहे उसकी नियुक्ति को समाप्त करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। इस निवेदन में कोई बल नहीं है कि यदि नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जानी है, तो नियुक्ति की समाप्ति के लिए भी इसी तरह के परामर्श की आवश्यकता होगी। द. परामर्श करने का दायित्व आवश्यक रूप से एक कार्यकारी पर रोक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है जो एक असुविधाजनक पदधारी को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। [549 एच; 550 बी-ई]

(ग) विधेयक का खंड 7 अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। 21 संविधान की हद तक

कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। [550 ई]

(घ) एक और दुर्बलता जिससे विधेयक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

पीड़ित है कि एकमात्र दायित्व है जो क्ल। 7 केंद्रीय सरकार पर थोपा गया

विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करते समय परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, न ही वास्तव में सरकार के दृष्टिकोण से अभियुक्त के दृष्टिकोण और समाज की अपेक्षाओं और संवेदनशीलताओं के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि निष्पक्ष और अप्रदूषित न्याय के नाम पर, विशेष न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया, न केवल अभियुक्त बल्कि पूरे समुदाय के विश्वास को प्रेरित करे। न्याय के प्रशासन का एक सामाजिक आयाम है और बड़े पैमाने पर समाज का निष्पक्ष और समान रूप से दिए गए न्याय में हिस्सा है। [550 एच; 551 ए-बी]

5. तथ्य यह है कि मुकदमा किसी न्यायाधीश से कम व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना है

उच्च न्यायालय और इस न्यायालय में अपील करने का अधिकार विधेयक के मुख्य सुरक्षा उपाय हैं। [552 एच]

6. यह प्रश्न कि क्या इस न्यायालय द्वारा दी गई राय

अनुच्छेद के तहत अपने सलाहकार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग। 143 (1) संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद के अर्थ में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के रूप में बाध्यकारी है। 141 संविधान के, भविष्य के अवसर पर अधिक पूरी तरह से विचार करना पड़ सकता है लेकिन

यह आशा की जानी चाहिए कि इस संदर्भ में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को निर्धारित करने में जो समय लगा है, वह व्यर्थ नहीं गया होगा। यद्यपि इस न्यायालय के लिए यह हमेशा खुला है कि वह अपने द्वारा पहले से तय किए गए प्रश्न की पुनः जांच करे और यदि आवश्यक हो तो भारत के क्षेत्र के अन्य सभी न्यायालयों के संबंध में उसके द्वारा पहले लिए गए दृष्टिकोण पर शासन करे, उन्हें इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से बाध्य होना चाहिए, यहां तक कि इसके तहत अपनी सलाहकार अधिकारिता का प्रयोग करते हुए भी।

अनुच्छेद . 143 (1) संविधान से। सेंट जेवियर्स कॉलेज में यह बताया गया था कि भले ही सलाहकार अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में दी गई राय बाध्यकारी न हो, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण होने का हकदार है। यह अजीब बात होगी कि दो निजी पक्षों के बीच विवाद में कानून के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इस देश के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होना चाहिए, लेकिन सलाहकार राय किसी को भी बाध्य नहीं करनी चाहिए, भले ही, तत्काल मामले की तरह, यह सभी इच्छुक पक्षों को नोटिस जारी करने के बाद, सभी संबंधित लोगों को सुनने के बाद, जो सुनना चाहते थे, और संदर्भ में उठाए गए प्रश्नों पर पूर्ण विचार करने के बाद दी जाती है। लगभग सब कुछ जो संभवतः विधेयक के पक्ष और विपक्ष में आग्रह किया जा सकता था, इस न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया था और यह सोचना कि इसकी राय निरर्थकता में एक अभ्यास है, बहुत निराशाजनक है। [553 डी-जी]

संपदा शुल्क विधेयक, [1944] एफ. सी. आर. 317,320,332,341; यू. पी. विधायी

असेंबली, [1965] 1 एससीआर 413,446-47; सेंट जेवियर्स कॉलेज, [1975] 1

एससीआर 173,201-202; अटॉर्नी-ऑटारियो के लिए जनरल बनाम। अटॉर्नी-जनरल आरई:

विशेष अदालतों का बिल

483

कनाडा के लिए, [1912] एसी 571,589; राम किशोर सेन बनाम। भारत संघ,

ए. आई. आर. 1965 कैल. 282 ; छबीलदास मेहता बनाम । विधान सभा

गुजरात राज्य, 1970 द्वितीय गुजरात विधि रिपोर्टर 729; का प्रांत मद्रास बनाम. मेसर्स बोद्दु पाइदन्ना, [1942] एफ. सी. आर. 90; मध्य प्रांत

मामला, [1939] एफ. सी. आर. 18; एच. एम. स्केरवई द्वारा भारत का संवैधानिक कानून,

2 एन. डी. ई. एन. खण्ड. II, पृष्ठ 1415, पैरा 25.68, संदर्भित ।

विधेयक के तहत मामलों की सुनवाई करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों को निवेश करना,

इन परिस्थितियों में हर दृष्टिकोण से सबसे अच्छा समाधान मिलता है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, अपने विवेकाधिकार पर, अपने न्यायालयों के न्यायाधीशों को पक्षपातपूर्ण मामले सौंपेंगे और आवंटित करेंगे। देरी से बचने और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, विधेयक के तहत किसी मामले या मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कोई अन्य काम नहीं सौंपा जा सकता है। यह केंद्र सरकार द्वारा एक पक्षीय मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधीश के नामांकन को रद्द कर देगा। [554 सी-डी]

संदर्भ के उत्तर इस प्रकार हैं:

(1) संसद के पास विशेष न्यायालयों के निर्माण के लिए विधायी क्षमता है और

यह उपबंध करने के लिए कि किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के अधिकार के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। इसलिए, विधेयक के खंड 2 और 10 (1) संसद की विधायी क्षमता के भीतर हैं; [554 जी-एच]

(2) विधेयक के क्ल, 4 (1) में दिए गए वर्गीकरण के लिए मान्य है -

जिस हद तक केंद्र सरकार को भारत में उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा आपातकाल की अवधि के दौरान किए गए कथित अपराधों के संबंध में घोषणा करने का अधिकार है। जिन व्यक्तियों पर आपातकाल की घोषणा से पहले अपराध करने का आरोप है, उन्हें वैध रूप से उन लोगों के साथ वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, जिन पर आपातकाल की अवधि के दौरान अपराध करने का आरोप है। इसलिए, केंद्र सरकार के लिए सी. एल. के तहत घोषणा करना उचित नहीं है। 4 (1) जिन व्यक्तियों पर 27 फरवरी, 1975 और 25 जून, 1975 के बीच अपराध करने का आरोप है, उनके संबंध में विधेयक। [555 ए-सी]

(3) संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए विधेयक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

जिसकी घोषणा केंद्र सरकार द्वारा सी. एल. के तहत वैध रूप से की जा सकती है। 4 (1)
निम्नलिखित मामलों को छोड़कर विधेयक न्यायसंगत और निष्पक्ष है:

(क) सी. एल. में प्रावधान। 7 विधेयक, जिसके तहत एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश

उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) सी. एल. में प्रावधान। 7 , जिसके तहत एक न्यायाधीश की नियुक्ति

केंद्र सरकार परामर्श में विशेष न्यायालय बना सकती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ लेकिन उनकी सहमति के बिना;

और

(ग) एक विशेष मामले से मामले के हस्तांतरण के लिए प्रावधान का अभाव

अदालत से दूसरे को।

(घ) यह विधेयक अन्य सभी मामलों में वैध और संवैधानिक है। [555 डी-ई]

कृष्णा अय्यर, जे। (सहमत)

1. भ्रष्टाचार और दमन-विकास प्रक्रियाओं का अपहरण, और

लंबी दौड़। राष्ट्रीय प्रगति में कमी का मतलब है लोगों की निरंतरता को कम करना।

सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक साधनों का उपयोग करना। और इसलिए, पता लगाने के लिए और [1979] 2 एस. सी. आर.

484

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन भारी-भरकम अपराधियों को, जो अक्सर सार्वजनिक नैतिक भार उठाने और बहुआयामी घोषणापत्रों द्वारा लोगों को गुमराह करते हैं, कम समय के लिए छोड़ देना एक तत्काल विधायी

मिशन है जो आंशिक रूप से विचाराधीन विधेयक द्वारा शुरू किया गया है। ऐसे अति-अपराधियों को शीर्ष पदों पर दंडित करना, कानूनी पलायन मार्गों और विलंबकारी रणनीतियों को बंद करना और उन्हें तेज गति से और जल्द से जल्द अंतिम रूप से न्याय के दायरे में लाना, अतीत में आयोगों और समितियों द्वारा एक व्यर्थ की इच्छा है और यह कानून के शासन की गतिशीलता का एक आयाम है। यह विधेयक लोगों की इस निराशावादी भावना के विपरीत नई जमीन तोड़ता है कि सभी उच्च-शक्ति वाले निवेश, रिपोर्ट और सिफारिशें विधायी और न्यायिक निरर्थकता में समाप्त होती हैं, कि ये सभी बहादुर अभ्यास केवल ध्वनि और रोष हैं जो कुछ भी नहीं दर्शाते हैं। [557 ए-बी]

2. (क) इस प्रकृति का एक अधिनियम, जिसमें प्रमुख परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है

अनुच्छेद के साथ टकराव को रोकने के लिए मुख्य न्यायाधीश। 21 और अनुच्छेद के साथ आने के लिए व्यापक कवरेज के साथ। 14 , बहुत देर हो चुकी है। [577 जी-एच]

(ख) ये अपराधी संवैधानिक विधेयक को एक अलग वर्ग के रूप में पूरी तरह से भरते हैं।

जो उच्च न्यायिक एजेंसियों द्वारा त्वरित अभियोजन और अंतिम सजा का हकदार है यदि तीसरी दुनिया के देशों में जनता के बीच संवैधानिक व्यवस्था और सामान्य विकास में गिरावट की विश्वसनीयता की बहाली को बनाए रखा जाना है। विधेयक की प्रस्तावना इस अभिविन्यास का खुलासा करती है। [558 सी]

(ग) इस विधान में एक उचित वर्गीकरण निहित है, लेकिन यह है

खतरनाक रूप से कम समावेशी होने के करीब और इसलिए, असमान। क्योंकि यह एक स्पष्ट रूप से व्यापक सिद्धांत का एक संक्षिप्त प्रक्षेपण है कि उच्च अपराधी से अपराधिक कानून द्वारा त्वरित गति से निपटा जाएगा ताकि आम आदमी को पता चल सके कि जब निजी लाभ या व्यक्तिगत बदले के लिए सार्वजनिक शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है तो कानून का शासन उन्हें तेजी से नीचे गिरा देगा और कानून के अनुसार त्वरित न्याय के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थानों में लोगों का विश्वास बहाल करेगा। यह इस मायने में है कि बड़ी प्रशासनिक शक्तियों वाले बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर त्वरित प्रेषण के साथ मुकदमा चलाया जाएगा और यदि वे दोषी हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। सभी अपराधिक मामलों में शीघ्र सुनवाई और शीघ्र सजा की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन, कच्चे यथार्थवाद से पता चलता है कि धीमी गति से न्याय की घटती स्थिति में त्वरित सुनवाई और त्वरित सजा के लिए एक विशेष मामला होता है जहां अपराधी प्रशासनिक पिरामिड के शीर्ष पर बैठता है। [558 एच; 559 ए-सी]

(घ) विधेयक नैतिक रूप से विफल होना चाहिए यदि यह गैर-आपातकालीन अपराधियों को छूट देता है

जिनका आयोग पूर्व में प्रतिवेदन देता है, वे गवाह होते हैं। इस व्यापक स्थिति में, आपातकाल एक महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और विधेयक 27 फरवरी, 1975 के ऑपरेशन से पहले इसे लगभग मान्यता देता है, जब कोई 'आपातकाल' नहीं था। [559 जी]

1

3. आपराधिक अदालतों की प्रक्रिया विलंबकारी है, इस पर अपील की जाती है।

अपील और संशोधन और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, अभियोजन की त्वरित समाप्ति को चौंका देने वाला और रोकने वाला, न्यायिक प्रक्रिया की बुनियादी आवश्यकताओं की उपेक्षा करके प्रशासन द्वारा स्वयं देरी में योगदान की बात नहीं करना। V.V.I.P. अभियुक्त को नियमित रूप से विलंबित कानूनी प्रक्रिया से निपटने के लिए छोड़ना एक अपरिहार्य बुराई के रूप में अंतहीन देरी के सामने आत्मसमर्पण करना है। इसलिए, न्यायालय को पूर्ण प्रक्रियात्मक समानता के बारे में आशावादी नहीं होना चाहिए और विशेष स्थितियों द्वारा मजबूर प्रक्रियाओं को नया बनाने में रचनात्मक होना चाहिए। [559 एच]

4. (क) अनुच्छेद का मुहावरा। 14 त्रुटिहीन है। अभियुक्त की शक्ति की स्थिति

आपराधिक, कथित अपराध की प्रकृति बनाम जनता का विश्वास और त्वरित मुकदमेबाजी की अंतिमता की अनिवार्य आवश्यकता, बताने वाले कारक हैं। हर अंतर एक अंतर नहीं है। 'जनता के अपराधों की त्वरित सुनवाई

प्रकृति

आरई में उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिबद्ध:

विशेष अदालतों का बिल

485

ऐसे अपराधों से जुड़े देश और अन्य '

बात का दिल। [560 डी]

(ख) उस शांत दौर के दौरान, कई लोगों को चौकाने वाले व्यवहार का सामना करना पड़ा। में विधेयक की प्रस्तावना के शब्द, नागरिक स्वतंत्रता को वापस ले लिया गया था हद तक, लोगों के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, सख्त सीएन प्रेस में सेवा दी गई और न्यायिक शक्तियों को काफी हद तक कम कर दिया गया। [560 एफ]

मूर्ति मैच वर्क्स आदि। द अस्स्टेट। केंद्रीय कलेक्टर

उत्पाद शुल्क, आदि, [1974] 3 एस. सी. आर. 121 130 पर, संदर्भित।

(ग) उद्देश्य और कारण न्यायालय का मार्गदर्शन करने वाली सूचनात्मक सामग्री हैं।

एक विधान के उद्देश्य और अंतर की सांठगांठ, यदि कोई हो, के बारे में

अंत को देखते हुए। आपातकाल अवधि के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है

विशिष्ट चिह्न। स्पष्ट संकेत यह है कि सार्वजनिक प्राधिकरण का सभी दुरुपयोग उच्च पदस्थ लोक पुरुष, के मामले में थकाऊ देरी के बिना दंडित किया जाएगा

शीर्ष इकोलन्स। [561 एफ]

मोहम्मद शुजात अली और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य।, [1975] 1

477 पर एससीआर 449; गुजरात राज्य और ए. एन. आर. वी. श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड,

अहमदाबाद, [1974] 3 एससीआर 760 782 पर; संदर्भित।

(घ) नागरिक स्वतंत्रताओं को दबा दिया गया, प्रेस सेंसरशिप को कम कर दिया गया

और न्यायिक शक्तियों में कटौती की गई। भले ही स्वतंत्रता में कटौती नहीं की गई थी,

प्रेस को बंद नहीं किया गया है या अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं की गई है, आपराधिक मुकदमे और अपील

और संशोधनों ने अपनी अंतहीन देरी की होगी। यह फॉरेंसिक है

देरी जिसे समाप्त किया जाना है और जिसका बुराइयों से कोई लेना-देना नहीं है

आपातकाल। आपराधिक अभियोजन के लिए कोई सीमा कानून नहीं है। [564 एफ; 565 बी]

(ई) उच्च शक्ति वाले सार्वजनिक और राजनीतिक अपराधी कोई विशिष्ट विशेषता नहीं हैं।

आपातकाल की लेकिन लंबे समय से चल रही धारा रही है और बोली का प्रवाह उचित है इसलिए, एक भ्रष्ट निरंतरता को बेहतर औचित्य के बिना विभाजित नहीं किया जा सकता है।

[565 ई-एफ]

(च) तो सवाल यह है कि क्या रखने के लिए कोई संवैधानिक तर्क है।

उच्च जनता में त्वरित न्याय गैर-आपातकालीन अपराधियों की पहुंच से बाहर होना

या राजनीतिक कार्यालय। ऐसा विधेयक, क्या यह कॉर्पस न्यायशास्त्र में एक स्थायी जोड़ था और जनता के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए एक अधिकार क्षेत्र के रूप में उपलब्ध है, यदि

कार्यालय में एक मंत्री के खिलाफ भी प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था, एक शुरू करने के लिए

उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन, एक पूर्ण सुधार होगा

सत्ता के पिरामिडों में भ्रष्टाचार की बुराई को फैलाने के लिए। [565 जी-एच]

(छ) संवैधानिक सिद्धांतों पर, इस अस्थायी स्थिति को बनाए रखना संभव है।

एक ऐसा उपाय जो एक घातक अवधि के दौरान अपराधों और अपराधियों को अलग करता है

बाकी जो समान भयावह संपत्तियों को साझा करते हैं। जब एक मोक्षदायक विकल्प

उपलब्ध है, न्यायालय को इसका विकल्प चुनना चाहिए जब हमला अनुच्छेद के तहत हो।

14 ,

बशर्ते कि विकल्पों द्वारा वांछित तथ्य की धारणाएं प्रशंसनीय हों, मूर्खतापूर्ण नहीं। आपात स्थिति की शरीर रचना को प्रस्तावना में एक्स-रे के रूप में दर्शाया गया है,

सभी काली छायाएँ हैं। आदेश देने या रोकने के लिए अवैधता कहने के लिए कोई अदालत नहीं

अनुचित तरीके से यातना देना या चुनौती देना। यदि यह स्वाभाविक रूप से एक संभावित खतरा है

एक खतरनाक स्थिति विकसित होती है, और एक बार असहनीय शक्ति,

इस तरह के दुरुपयोग का उद्घाटन और वृद्धि एक बाध्यकारी निरंतरता बन जाती है।

संवैधानिक अत्याचार सभ्य लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। उस में

लोगों की घबराहट की स्थिति, अदालत में जाने और मुकदमा चलाने का अधिकार

भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के लिए अधिकार में एक निरंकुश व्यक्ति भ्रमपूर्ण है।

अगर [1979] 2 एस. सी. आर.

486

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आप उच्च पदों पर अपराधों के खिलाफ बोलते हैं, यदि आप अदालत में शिकायत करते हैं

सत्ता का दुरुपयोग, आपको शीघ्र हिरासत और गुप्त यातना के साथ स्वागत किया जा सकता है,

न्यायिक राहत को समाप्त कर दिया गया है और प्रेस प्रचार को समाप्त कर दिया गया है, अगर ये भयावह हैं

माना जा रहा था कि आपातकाल के बीच एक हानिकारक सांठगांठ हो सकती है

मौसम और इस विधेयक के दायरे में आने वाले भयावह अपराध। यह इस प्रकार है कि एक संबंध

अंतर और वस्तु के बीच का अनुमान लगाने के लिए पुनरावर्तित नहीं है।

[567 ए-बी]

(ज) आपातकालीन ज्यादतियों के डरावने परिदृश्य का गैर-कार्रवाई के साथ संबंध था अधिकार और भ्रष्टाचार में वृद्धि के खिलाफ उच्च स्तर के व्यक्तियों के खिलाफ और दमन जब दुर्व्यवहार पर न्यायिक जाँच सो गई थी। [568 ए-बी]

(i) आपातकाल से पहले और उसके दौरान अपराधों का ताना-बाना समान है।

भ्रष्ट कार्यों का गहन चरण और खुदाई की अक्षमता पुराने अपराध।
अम्बिका मिल्स (ऊपर) वर्गीकरण के लिए न्यायिक औचित्य है।

यह। [570 सी!]

5. (क) विधेयक खतरनाक रूप से असंवैधानिकता के करीब है (अनुच्छेद। 14) में कुछ मामलों में, लेकिन निश्चित रूप से व्यावहारिक सिद्धांतों के उपयोग से बचाया जाता है अति राजनीतिक अपराधियों के साथ दृढ़ता से और तुरंत निपटने के लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि ये 'अच्छूत' और 'अप्राप्य' सत्ता चलाने वाले भयावह हो गए हैं फिर भी विकासशील देशों में विकास के निरंतर साथी। [570 ई]

चगनलाल मगनलाल (पी) लिमिटेड बनाम। ग्रेटर का नगर निगम

बॉम्बे और ओआरएस।, [1975] 1 एस. सी. आर. 1, संदर्भित।

(ख) प्रक्रिया की बुनियादी निष्पक्षता आवश्यक है। एक के साथ एक वैध वर्गीकरण बोधगम्य अंतर और वस्तु के साथ बुद्धिमान संबंध की आवश्यकता है। इसके भीतर वर्ग के लिए अधिक बोझिल प्रक्रिया का उपयोग करने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए एक और दूसरे के लिए काफी अलग सीएनई। इस क्षेत्र में मनमानी यह अनुच्छेद का भी उल्लंघन करता है। 14. [571 डी]

(ग) यह मानते हुए कि विधेयक के तहत और सामान्य संहिता के तहत सुविधाएं समान रूप से निष्पक्ष हैं, क्या सरकार एक या दूसरे का संकेत दे सकती थी साधारण अदालत या विशेष अदालत ड्राँ लॉट या पहले के आधार पर उनके नाम का अक्षर, उनकी खाल का रंग या अर्थहीन की तरह? नहीं। द.

अनुच्छेद का ज्ञान। 14 इस तरह की सनक बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्गीकृत करें या नष्ट करें, यह है संविधान के तहत अपरिवर्तनीय समानता से वैध छूट का उत्कृष्ट परीक्षण।

[571 ई-एफ]

(घ) संदर्भ द्वारा उठाई गई समस्याओं का निश्चित समाधान, लगातार विधेयक के वर्तमान उद्देश्य के साथ, उच्च न्यायालय को संरक्षक बनाना है नया अधिकार क्षेत्र। [571 जी]

अंतवालिया, जे. (बहुमत से सहमत)

1. संघीय न्यायालय द्वारा उत्तर दिए गए पहले के संदर्भों में से एक या इस न्यायालय द्वारा एक पूर्ववर्ती को किसके समान या समान पाया जाना है इस विशेष संदर्भ में हुआ। विधि अपनाने में कोई बुराई नहीं है। न्यायालय से कुछ सुझाव देना जो संभावित को समाप्त कर सकता है किसी विधेयक के अधिकारों पर संवैधानिक हमला। यह आवश्यक नहीं हो सकता है या यहाँ तक कि अनुच्छेद के तहत सभी संदर्भों में इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने की भी सलाह दी जाती है। 143 में से संविधान। लेकिन अगर कुछ में ऐसा करना समीचीन हो जाता है, जैसे कि पल में यदि सरकार को लगता है कि वह ऐसा करने के लिए सहमत हो सकती है, तो यह विधेयक से किसी भी तकनीकी कमी को दूर करने के लिए सार्वजनिक समय और धन की बहुत बचत करता है। यह विधेयक अपने आप में कोई कानून नहीं है। संसद द्वारा पारित होने पर यह एक कानून होगा।

आरई: विशेष अदालतों का बिल

487

लेकिन विधेयक के स्तर पर भी जब इस न्यायालय की राय मांगी जाती है, तो किसी दिए गए मामले में कुछ सुझाव देना और फिर सरकार द्वारा स्वीकार किए गए सुझावों की स्वीकृति के आधार

पर संदर्भ का जवाब देना काफी उचित लगता है। अन्यथा, इस न्यायालय के लिए संदर्भ का उत्तर देना असंगत है क्योंकि यह उपबंध को ध्यान में रखे बिना है।

सरकार की ओर से किए गए बयानों की तुलना में-ए-के-सुझाव

अदालत। यह स्पष्ट है कि उत्तर संख्या 3 में बहुमत की राय में बताई गई तीनों दुर्बलताएं सरकार द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किए जाने के बाद गायब हो जाती हैं।

कि न्यायालय द्वारा दिए गए तीन सुझाव बनाम कथित तीन

3 (बी) और 3 (सी) नामक दुर्बलताओं को विधेयक से हटा दिया जाएगा।

[572 डी-ए!]

2. एक विशेष न्यायालय से मामले के हस्तांतरण के लिए प्रावधान का अभाव

दूसरे के लिए, प्रक्रिया को अन्यायपूर्ण या मनमाना बनाता है। लेकिन कथित दुर्बलताएँ, 3 (क) और (ख) प्रक्रिया को अन्यायपूर्ण या मनमाना न बनाएँ। वहाँ कोई नहीं है

उत्तर 3 में उल्लिखित तीन दुर्बलताओं (ए), (बी) और (सी) में से किसी के संबंध में प्रक्रिया के अन्यायपूर्ण या मनमाना होने का प्रश्न

भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझावों की स्वीकृति न्यायालय संदर्भ की सुनवाई के दौरान। संदर्भ,

इसलिए, उन रियायतों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया है और अदालत अब है संशोधित संदर्भ का उत्तर देना आवश्यक है जिसका अर्थ है संदर्भ जैसे कि

प्रस्तावित विधेयक में सरकार द्वारा दी गई तीन रियायतें शामिल हैं।

मन में। इस प्रकार विधेयक में निर्धारित प्रक्रिया निस्संदेह न्यायसंगत हो जाती है।

और निष्पक्ष और अब किसी भी अर्थ में मनमाना नहीं रहता है। [573 सी-डी]

सिंहल, जे। (असहमति)

विधेयक के खंड 5 और 7 असंवैधानिक और अमान्य हैं। [573 एच]

1. (क) उद्देश्यों और कारणों के विवरण में दिया गया कारण

साधारण आपराधिक न्यायालयों को अपराधों के वर्ग की सुनवाई से बाहर रखने के लिए विधेयक इसमें काम की भीड़ का उल्लेख किया गया है न कि उनकी निम्न स्थिति या

उन मामलों से निपटने की क्षमता। विधेयक का उद्देश्य यह रहा होगा कि सामान्य के समान श्रेणी के अतिरिक्त न्यायालयों के निर्माण द्वारा सेवा प्रदान की गई अपराधिक न्यायालयों और किसी भी प्रक्रियात्मक परिवर्तन का निर्माण जो हो सकता है मुकदमे में टालने योग्य देरी को बाहर करने के लिए उस संदर्भ में आवश्यक माना गया।

[574 एफ]

(ख) अगर ऐसी अतिरिक्त अदालतें होतीं तो कुछ भी असामान्य नहीं होता।

कार्य करना और विचारित अभियोजनों को शीघ्रता से समाप्त करना। कि कानून के तहत अनुमति थी। भले ही कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तन थे मौजूदा

कानून से। विधेयक में जिन विशेष न्यायालयों की परिकल्पना की गई है, वे हैं - जिसका अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य में नहीं दिया गया है।

अन्य कानून, और वास्तव में अपराधिक कानून के लिए अज्ञात हैं

देश।

[574 जी]

(ग) संविधान में विचार किया गया है कि सभी दीवानी और अपराधिक अदालतें

राज्य, उच्च न्यायालय के अलावा, अधीनस्थ न्यायालयों के अलावा और कोई नहीं होगा।

जिस पर उच्च न्यायालय पूर्ण अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेगा।

और कि उन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में होंगे

उच्च न्यायालय और कोई अन्य प्राधिकरण नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि

दीवानी और अपराधिक मामलों से निपटने वाले प्रत्येक न्यायालय का विचाराधीनता।

[576 डी]

(घ) दीवानी और अपराधिक अदालतें बनाने या स्थापित करने की अनुमति हो सकती है।

अनुच्छेद 236 में व्यक्त किए गए पदनामों के अलावा अन्य पदनाम वाला राज्य, या कोई अस्तित्व में है।

सिविल और दंड प्रक्रिया संहिताओं में पदनाम, लेकिन यह बहुत दूर है

[1979] 2 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

488

यह कहने से कि इसके अलावा अन्य न्यायालयों के उत्तराधिकार स्थापित करने की अनुमति है जिसकी परिकल्पना संविधान में की गई है। [576 ई]

2. (क) संविधान ने इसके लिए पर्याप्त और प्रभावी प्रावधान किया है -

एक मजबूत, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक प्रशासन की स्थापना

दीवानी और आपराधिक न्यायालयों के आवश्यक पूरक के साथ देश। यह है।

संसद या राज्य विधानमंडल के लिए इसकी अनदेखी करने या इसे दरकिनार करने की अनुमति नहीं है।

एक नागरिक की स्थापना के लिए प्रावधान करके संविधान की योजना या

किसी राज्य में उच्च न्यायालय के समानांतर या किसी अतिरिक्त न्यायालय के माध्यम से आपराधिक न्यायालय या अतिरिक्त या दूसरा उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के अलावा कोई अन्य न्यायालय

उच्च न्यायालय। इस तरह का कोई भी प्रयास असंवैधानिक होगा और हड़ताल करेगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जिसे इस तरह से प्रतिष्ठित किया गया है

संविधान और इतने सावधानी से वर्षों से देखभाल की गई। [576 जी]

(ख) संविधान में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है और

राज्यों में अन्य न्यायिक अधिकारी। इस न्यायालय ने कई मामलों में घोषित किया कि यह उच्च न्यायालय है जो नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक है राज्य न्यायपालिका पर जो वास्तव में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का जीवन रक्त है प्रशासन और किसी भी वास्तविक न्यायिक इमारत की नींव। द कॉन शासन ने मजिस्ट्रेटों के अस्तित्व या निरंतरता पर भी विचार नहीं किया है जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण से बाहर हैं, वे वांछनीय हैं। यह इससे परे है संदेह है कि संविधान आपराधिक अदालत की स्थापना की अनुमति नहीं देता है जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अदालत की स्थिति जो अधीनस्थ नहीं है उच्च न्यायालय से संबंधित है और इसी तरह के न्यायालय की स्थापना की अनुमति नहीं देता है। उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के समानांतर न्यायालय। [577 सी; 578 ए-बी]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। नृपेंद्र नाथ बागची, [1966] 1 एससीआर

771, चंद्र मोहन और अन्य, वी। यू. पी. और अन्य का राज्य।, [1967] 1 एससीआर 77; असम राज्य आदि। रंगा मोहम्मद और ओआरएस।, [1967] आई.

एस. सी. आर. 454; उड़ीसा राज्य बनाम। सुधांशु शेखर मिश्रा और अन्य।, [1968] 2 एस. सी. आर. 154; असम और अन्र राज्य। वी. एस. एन. सेन और अन्र. , [1972] 2

एससीआर 251; शमशेर सिंह और अन्र। वी. पंजाब राज्य [1975] 1 एससीआर 814;

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, आदि। [1975]) एस. सी. आर. 365; हरियाणा राज्य बनाम इंंदर प्रकाश आनंद, ए. आई. आर.

1976 एससी 1841: आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और अन्य। वी. एल. वी. ए. दीक्षितुलु और ओआरएस।, [1979] 1 एस. सी. आर. 26, संदर्भित।

(ग) न तो एस। 6 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और न ही एस। 6 में से

आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 इस तर्क को सही ठहराता है कि विशेष अदालतें विधेयक में परिकल्पित प्रकृति की योजना के तहत बनाई जाएगी

संविधान। हालांकि एस। 6 दंड प्रक्रिया संहिता में कहा गया है कि इसमें वर्णित आपराधिक न्यायालयों के पांच वर्ग उच्च न्यायालय और उन न्यायालयों के अतिरिक्त होंगे जो किसी भी कानून के तहत गठित किए जा सकते हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह उच्च न्यायालय या आपराधिक न्यायालयों के समानांतर या उसी आधार पर न्यायालयों के गठन का प्रावधान करता है जो उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ नहीं हैं। इसी तरह, एस के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश। 6 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं और संविधान द्वारा परिकल्पित न्यायपालिका की स्वतंत्रता की योजना में उपयुक्त हैं। [578 ई-एफ]

(घ) विशेष न्यायालयों के निर्माण को उचित ठहराने का प्रयास

संविधान के भाग XIVA, जो प्रशासनिक तृतीय न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है, को कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ऐसे न्यायाधिकरण भारतीय दंड संहिता में निर्दिष्ट अपराधों के मुकदमों के लिए नहीं हैं। इन्हें अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण, [579 डी] आरई कहा जा सकता है:

विशेष अदालतों का बिल

489

(ड) विधेयक के खंड 2 द्वारा अनुध्यात विशेष न्यायालयों को

उच्च न्यायालयों के समान आधार पर और कम से कम कहने के लिए, कम या निम्न न्यायालय होंगे। [579 ई]

(च) विधेयक के खंड 7 में प्रावधान है कि एक विशेष अदालत की अध्यक्षता की जाएगी।

उच्च न्यायालय के "वर्तमान न्यायाधीश" द्वारा, लेकिन यह अनुज्ञेय या उचित नहीं होगा

ऐसा करना क्योंकि वह न्यायालय उच्च न्यायालय से कमतर और निम्नतर है। सभी संभावनाओं में,

उच्च न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीश विशेष न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीशों के रूप में सेवा करने से इनकार कर देंगे, और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत वे कर सकते हैं।

वहाँ सेवा करने के लिए मजबूर किया जाए, या उनकी इच्छा के विरुद्ध आदेश दिया जाए। यह होगी संभावना

विधेयक के प्रावधानों को अव्यवहारिक बनाना। किसी भी तरह से, संभावना है कि

उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश पीठासीन न्यायाधीशों के रूप में सेवा करने के लिए सहमत नहीं हो सकते हैं

विशेष अदालतें वास्तविक हैं और उनका इनकार ही न्यायिक प्रशासन को शर्मिंदा करेगा

विधेयक के खंड 7 के लिए न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रावधान है।

इंडा के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उनके नामांकन के लिए, [579 एफ-एच]

3. (क) कानून के समक्ष समानता, या वर्तमान कानून के संदर्भ में बोलना।

अधिकार, आपराधिक न्याय में समानता, सभी लोकतांत्रिक लोगों का सार्वभौमिक लक्ष्य है

सरकार के रूप, क्योंकि कोई भी कभी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि सभी व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है

अपराध, कानून में, न्याय के बार में एक ही आधार पर खड़ा होना चाहिए। कि

अभियोजन पक्ष और अभियुक्त के बीच। यही संविधान में है प्रत्येक नागरिक के लिए सावधानीपूर्वक, निश्चित रूप से और पूरी तरह से प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 के अनुसार,

स्वयं, इसे बाहर लाने के लिए पर्याप्त है। [580 सी-डी]

(ख) अनुच्छेद की गारंटी को पूरा करने के लिए। 21 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए कानून निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होना चाहिए, और नहीं काल्पनिक, दमनकारी या मनमाना। खंड 5,7 और 8 को एक साथ लिया जाए तो

विधेयक में अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए केवल विशेष अदालतों की अध्यक्षता करने का प्रावधान है

केंद्र सरकार और खंड 4,5 और 7 द्वारा नामित न्यायाधीश द्वारा

विशेष अदालत को नामित करने की शक्ति निहित करें जिसमें एक अभियुक्त होना है उस सरकार में विशेष रूप से प्रयास किया गया। यह विधेयक केंद्रीय सरकार को सक्षम बनाता है

यह तय करने के लिए कि अभियुक्तों में से किस पर मुकदमा चलाया जाएगा

न्यायाधीशों। इस प्रकार अगर केंद्र सरकार द्वारा कई विशेष अदालतें बनाई जाती हैं

दिल्ली और इन सभी की अध्यक्षता केंद्र द्वारा नामित न्यायाधीश करते हैं।

सरकार, किसी विशेष मामले के लिए न्यायाधीश को नामित करने की शक्ति

दिल्ली में केंद्र सरकार निहित होगी। इस तरह की प्रक्रिया नहीं हो सकती

अनुच्छेद के अर्थ के भीतर निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित कहा जाता है। 21 और राशियाँ

न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर अतिक्रमण। [581 जी; 582 डी-एफ]

(ग) केंद्र सरकार या राज्य सरकार का प्रश्न।

सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नामित करना

एक विशेष मामला उत्पन्न नहीं होता है और न ही हो सकता है। इसलिए भी न्यायाधीशों के संबंध में और

अधीनस्थ न्यायालयों के मजिस्ट्रेटों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है,

उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए प्रासंगिक कानूनों में। यह परमीस नहीं है कार्यपालिका के लिए किसी विशेष न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करना

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी विशेष आरोपी के मुकदमे पर।

यह उचित, न्यायसंगत और उचित है और अभियुक्त को किसी भी संभावित अत्याचार से मुक्त करता है।

सायन। [583 ए-बी. आई.

(घ) इसके अलावा विशेष अदालतों के समक्ष मुकदमों के मामले में,

हालांकि, एक उत्तराधिकारी सरकार के आदेश को संदेह के साथ देखा जाता है

संदेह है कि मुकदमा राजनीतिक विचारों से प्रेरित है, कि यह न्यायसंगत और निष्पक्ष नहीं होगा या यह कि यह अन्याय की ओर ले जाएगा, छिपी हुई होगी

13-978 एससीआई/78 ईएसटीएआर 8

**

[1979] 2 एस सी आर ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

490 .

अभियुक्त के मन में। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी संबंधित,

मुकदमे का आदेश देने में इरादे और एक निष्पक्ष और सीधे आगे के लिए प्रदान किया था प्रक्रिया, और न्यायाधीशों में सबसे स्वच्छ, एक खुले और निडर में मुकदमे के लिए

तरीके से। [583 सी एंड ई]

(ई) यदि मुकदमे के परिणाम को लोगों के साथ दोषसिद्धि के रूप में रखना है

समग्र रूप से, और इसका उद्देश्य उन्हें उन व्यक्तियों के वास्तविक चरित्र से परिचित कराना है जिन्होंने लोकतांत्रिक संस्थानों के अस्तित्व के लिए अपराध किए हैं और राजनीतिक जीवन की स्वच्छता जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया है, यह उन लोगों के हित में है जो निम्नलिखित घोषणा करते हैं।

खंड 4 अभियुक्त सहित सभी को यह समझाने के लिए कि मुकदमा उद्देश्य से शानदार नहीं है और इसका सामना करने वालों को सामान्य कानून के तहत किसी अन्य अभियुक्त द्वारा सामान्य मुकदमे में लिए गए जोखिम से अधिक जोखिम के लिए उजागर नहीं करता है। मानव गरिमा संविधान में निहित एक अवधारणा है और यह खजाना है

यह हमारे सभी साथी नागरिकों की अमूल्य संपत्ति और ठोस आशा होनी चाहिए, जिसमें वे भी शामिल हैं जिन्हें उनके खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ता है। [583 एफ-एच)

(च) एक महत्वपूर्ण विधेयक को हड़पने के लिए वर्तमान विधेयक में किए गए प्रयास की तरह

न्यायिक शक्ति और इसे कार्यपालिका में निहित करना न्यायपालिका के स्वतंत्र होने का एक गंभीर मार्ग है और इसके गंभीर परिणाम होते हैं। इससे पहले, इसे शुरुआत में ही नीचे रखा जाना चाहिए क्योंकि यह अन्यथा एक ऐसी संभावना को जन्म दे सकता है जिसकी कल्पना करना बहुत ही वीभत्स है और जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

कानून की मंजूरी। [584 एच]

लियानाज और ओआरएस। वी. रेजिना [1966] 1 सभी। ई. आर. 650 का उल्लेख किया गया।

1978 का सलाहकार न्यायपालिका विशेष संदर्भ सं. 1

(अनुच्छेद के तहत। 143 (1) भारत के संविधान)।

एस. वी. गुप्ते, महान्यायवादी, आर. एन. सचथी और आर. बी. दातार

भारत के महान्यायवादी के लिए।

एस. एन. कक्कर, सोल। जनरल।, आर. एन. सचथे और एस. मार्कण्डया

भारत संघ।

के. डी. चटर्जी, अधिवक्ता। जनरल। (बिहार), अधिवक्ता के लिए यू. पी. सिंह।

जनरल। (बिहार)।

ए. के. मलिक, अधिवक्ता। जनरल।, (जे एंड के), अल्ताफ अहमद और वृज बिहारी

ए. जी. के लिए सिंह।,, जे एंड के।

आर. एन. बायरा रेड्डी, अधिवक्ता। जनरल।, एस. एस. रे और ए. के. सेन. एन. नेत्तर,

ए. जी. कर्नाटक के लिए जे. एस. सिन्हा और श्रीमती अल्वा मार्गरेट।

अब्दुल खादर, अधिवक्ता। जनरल।, ए. जी. के लिए केरल और के. एम. के. नायर,

(केरल)।

आर. एस. भोंसले, अधिवक्ता। जनरल।, (महाराष्ट्र), वी. सी. कोतवाल और

ए. जी. महाराष्ट्र के लिए एम. एन. शर्मा ।

बी. एम. पटनायक, अधिवक्ता । जनरल । , (उड़ीसा), सुश्री उमा मेहता और आर. के.

ए. जी., (उड़ीसा) के लिए मेहता ।

आरई: विशेष अदालतों का बिल

491

आर. के. रस्तोगी, अधिवक्ता । जनरल । (राजस्थान), एस. एम. जैन और एम. आई. खान,

ए. जी., राजस्थान के लिए ।

वी. पी. रमन, अधिवक्ता । जनरल । (तमिलनाडु) और ए. वी. रंगम, के लिए

ए. जी. ,, तमिलनाडु ।

ओ. पी. राणा, ए. जी. के लिए (यू. पी.)

एस. के. आचार्य, अधिवक्ता । जनरल । (पश्चिम बंगाल), सुकुमार बसु और

जी. एस. चटर्जी, ए. जी., पश्चिम बंगाल के लिए ।

एफ. आर. मृदुल, एच. के. पट्ट, विजेंद्र जैन, अरुणाश्वर गुप्ता, विवेक

सेठी और विजय बहल, मध्यस्थ (श्री वी. सी. शुक्ला) के लिए ।

जे. एस. वासू और ओ. पी. शर्मा, मध्यस्थ के लिए (ज्ञानी जैल)

सिंह) ।

एम. सी. भंडारे और ओ. पी. शरीना, मध्यस्थ के लिए (हरिदेव)

जोशी) ।

इंटर के लिए ए. के. सेन, बिशंबर लाल और सुश्री मनीषा गुप्ता

वेनर (धीरेंद्र ब्रह्मचारी) ।

एम. सी. भंडारे, श्रीमती सुनंदा भंडारे, आर. नागरत्नम, वजीर सिंह और सुश्री मालिनी पोदुवाल, हस्तक्षेप करने वालों के लिए (बंसी लाल, शिव) कुमार अग्रवाल और सुरिंदर सिंह)।

ए. एस. बोबडे, एम. आर. बारोट, श्रीमती सुनंदा भंडारे, आर. नागरथ नाम, वजीर सिंह, सुश्री मालिनी पोदुवाल और आर. एन. मित्तल, हस्तक्षेपकर्ता (सी. एम. स्टीफन)।

फ्रैंक एनोथनी, श्रीमती एस. भंडारे, एम. आर. बारोट, आर. एन. मित्तल, आर. नागरत्नम और सुश्री मालिनी पोदुवाल, मध्यस्थ (कनिला) के लिए पति त्रिपाठी)।

पी. शिव शंकर और बी. गोबर्धन, मध्यस्थ के लिए (परनब) मुखर्जी)।

डी. डी. चावला और एन. एस. दास बहल, मध्यस्थ (आर. के.) के लिए। धवन)।

शिव पूजन सिंह, मध्यस्थ के लिए (जगमोहन और पी. एस. भिंडर)।

एम. सी. भंडारे, एन. नेत्तर, जे. एस. सिन्हा और श्रीमती अल्वा मार्गरेट हस्तक्षेपकर्ता (देव राज उर्स) के लिए।

ए. एन. कारखानीस, मध्यस्थ (नारायण दत्त तिवारी) के लिए।

ए. एस. बोबडे, जे. एन. मिश्रा, वी. सी. महाजन, राम लाल, डी. गोबर्धन, हस्तक्षेप करने वालों (जगन्नाथ मिश्रा और राम लाल) के लिए।

ए. जी. नूरानी, रानी जेठमलानी और एच. एन. हिंगोरानी हस्तक्षेपकर्ता (राम जेठमलानी)।

पी. शिवशंकर, फ्रैंक एंथनी, पी. पी. राव और जी. एन. राव,

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हस्तक्षेप करने वाले।

[[1979 1979]] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

492

एप्पली के लिए एस. एस. रे, पी. एन. रामलिंगम और ए. टी. एम. संपत
कैन्ट इंटरवेनर (जम्मू और कश्मीर राज्य और महाधिवक्ता, हरियाणा के लिए)।

एस. सी. मोहंता, अधिवक्ता। जनरल (हरियाणा), नौबत सिंह (डिप्टी कमिश्नर)। एड.
जनरल.) , हरियाणा के महाधिवक्ता की ओर से आर. एन. सचथे और गिरीश चंद्र।

चंद्रचूड़, सी. जे. ने भगवती की ओर से राय दी,

सरकारिया और फजल अली, जे. जे. और खुद भी। कृष्ण अय्यर, उन्तवालिया और शिंगल, जे.
जे.। अलग-अलग राय दी।

चंद्रचूड़, सी. जे.-1 अगस्त, 1978 को भारत के राष्ट्रपति

उन्होंने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत इस
न्यायालय का संदर्भ दिया कि क्या "विशेष न्यायालय विधेयक, 1978" या इसके किसी भी
प्रावधान को यदि अधिनियमित किया जाता है, तो वह संवैधानिक रूप से अमान्य होगा। संदर्भ
का पूरा पाठ इस प्रकार है:

" जहाँ कुछ जांच आयोग नियुक्त किए गए थे

जांच आयोगों के तहत केंद्र सरकार द्वारा

अधिनियम, 1952 (1952 का केंद्रीय अधिनियम 60) ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

जो इंगित करता है कि यह मानने का कारण है कि विभिन्न
उच्च पद धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपराध किए गए हैं

संचालन की अवधि के दौरान राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यालय

25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा,
और उस घोषणा से तुरंत पहले की अवधि;

और जहाँ ऐसे अपराधों की जाँच की जाती है

कानून के अनुसार बनाया जा रहा है और होने की संभावना है
जल्द ही प्रसन्न;

और जहाँ सुझाव दिए गए हैं कि

जिन व्यक्तियों के संबंध में जाँच से पता चलता है कि

प्रथम दृष्टया मामला बना दिया गया है और मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
उस उद्देश्य के लिए गठित विशेष न्यायालयों में तेजी से;

और जहाँ एक प्रस्ताव बनाया गया है कि कानून

एक पर्याप्त के निर्माण के लिए अधिनियम बनाया जाना चाहिए

ऐसे अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की संख्या
विधेयक की तर्ज पर, जिसकी एक प्रति यहाँ संलग्न की गई है

(इसके बाद "विधेयक" के रूप में संदर्भित);

और जहाँ संदेह व्यक्त किए गए हैं

विधेयक की संवैधानिक वैधता और इसके पक्ष को देखते हुए

दर्शन;

और जहाँ संवैधानिक होने की संभावना है

विधेयक के प्रावधानों की वैधता, यदि अधिनियमित की जाती है, और कोई भी

1

उसके तहत की गई कार्रवाई, जिसे अदालतों में चुनौती दी जा रही है

लंबी और परिहार्य मुकदमेबाजी शामिल है; 186

विशेष अदालतों का बिल

49

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

और यहाँ जो कुछ हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए

इससे पहले कहा गया था, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बाद में निर्धारित कानून का प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना है और यह ऐसी प्रकृति का और इतना सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है।

अब, इसलिए, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

संविधान के अनुच्छेद 143 के खंड (1) द्वारा, मैं, भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, एतद्वारा निम्नलिखित प्रश्न को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विचार करने और रिपोर्ट करने के लिए संदर्भित करता हूँ, अर्थात् -

सवाल

(1) चाहे वह विधेयक हो या उसका कोई प्रावधान, यदि -

अधिनियमित, संवैधानिक रूप से अमान्य होगा?

नई दिल्ली,

अगस्त, 1978 का पहला दिन

भारत के राष्ट्रपति "

संदर्भ आदेश के साथ संलग्न विधेयक की एक प्रति है

जो इस प्रकार चलता है:

" विशेष न्यायालय विधेयक, 1978

ए.

बिल

अपराधों के एक निश्चित वर्ग के मुकदमे के लिए प्रावधान करना

और चूंकि उक्त अपराधों में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना राज्य का संवैधानिक, कानूनी और नैतिक दायित्व है;

और क्योंकि काम की भीड़ और अन्य कारणों से सामान्य आपराधिक न्यायालयों से उन अभियोजनों को त्वरित अवधि में लाने की उचित रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती है; और चूंकि संसदीय लोकतंत्र और भारत के संविधान द्वारा या उसके तहत बनाए गए संस्थानों के कामकाज के लिए यह अनिवार्य है कि उपरोक्त पाठों में निर्दिष्ट अपराधों के आयोग का न्यायिक रूप से अत्यधिक प्रेषण के साथ निर्धारण किया जाना चाहिए;

और जहाँ उक्त उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि -

भारत में किसी उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति की अध्यक्षता में अतिरिक्त न्यायालयों का निर्माण करना; और क्योंकि कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तन करना समीचीन है जिसके द्वारा मुकदमे के लिए व्यक्तियों के अपराध या निर्दोषता के अंतिम निर्धारण में टालने योग्य देरी को निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार में हस्तक्षेप किए बिना समाप्त कर दिया जाता है;

भारत गणराज्य के उनतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए -

1. (1) इस अधिनियम को विशेष न्यायालय अधिनियम कहा जा सकता है।

1978 .

(2) यह तुरंत लागू हो जाएगा।

2. केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा पर्याप्त संख्या में न्यायालयों का निर्माण करेगी जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जाएगा।

3. एक विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा या उन पर विचार करेगा जो उसके समक्ष स्थापित किए गए हैं या उसे हस्तांतरित किए गए हैं - इसके बाद प्रदान किया गया।

4. (1) यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी अपराध के होने का प्रथम दृष्टया सबूत है तो विशेष अदालतों का बिल

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

भारत में उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पद धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तावना में उल्लिखित अवधि के दौरान कथित रूप से किया गया था और यह कि यहाँ की प्रस्तावना में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त अपराध से अधिनियम के तहत निपटा जाना चाहिए, केंद्र सरकार प्रत्येक मामले में उस आशय की घोषणा करेगी जिसमें उसकी राय उपरोक्त है।

(2) इस तरह की घोषणा पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा।

5. ऐसी घोषणा किए जाने पर ऐसे अपराध के संबंध में कोई भी अभियोजन केवल केंद्र सरकार द्वारा नामित विशेष न्यायालय में शुरू किया जाएगा और भारत के किसी भी न्यायालय में लंबित ऐसे अपराध के संबंध में कोई भी प्रतिभूति पक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित विशेष न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगा।

6. यदि किसी अपराध के संबंध में घोषणा की तारीख को ऐसे अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष में किसी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन, चाहे वह लंबित हो या निपटाया गया हो, स्वयं किसी अपील या संशोधन के न्यायालय में लंबित है, तो वह निपटान के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगा।

7. एक विशेष न्यायालय की अध्यक्षता भारत में उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश या एक व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसने भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया है।

8. एक विशेष न्यायालय को उस अपराध में संबंधित किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की अधिकारिता होगी, जिसके संबंध में धारा 4 के तहत प्रधान, साजिशकर्ता या उकसाने वाले और अन्य सभी अपराधों और अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में घोषणा की जाती है, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार एक मुकदमे में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है।

9. एक विशेष न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई में निम्नलिखित मामलों की सुनवाई के लिए उक्त संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा -

मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामले और इस अधिनियम में अन्यथा पक्षकार को छोड़कर उक्त संहिता द्वारा शासित होंगे।

10. (1) उक्त संहिता में कुछ भी होने के बावजूद, किसी भी निर्णय या आदेश के अधिकार के रूप में एक अपील होगी -

तथ्य और कानून दोनों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक विशेष न्यायालय।

[1979] 2 एससीआर।

496

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) उपरोक्त के अलावा, कोई अपील या संशोधन नहीं होगा।

किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से अदालत "।

1 अगस्त को संदर्भ प्राप्त होने के बाद एक नोटिस जारी किया गया था

2 तारीख को महान्यायवादी को अदालत में पेश होने के लिए

चौथा मामले में निर्देश लेने के लिए। 4 अगस्त को,

महान्यायवादी को सुनकर न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया कि:

(1) संदर्भ की सूचना भारत संघ को दी जाए और

राज्यों के महाधिवक्ता जिनसे उन्हें 4 सितंबर, 1978 से पहले अपनी लिखित जानकारी जमा करने की आवश्यकता होती है; (2) पाँच में नोटिस प्रकाशित किए जाएं।

बॉम्बे, नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बैंगलोर में समाचार पत्र विधेयक के पारित होने से प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों को आमंत्रित करना

कार्यवाहियों में उपस्थित होने या हस्तक्षेप करने की अनुमति के लिए आवेदन करें; (3) हस्तक्षेप करने वालों को अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वे मौखिक रूप से सुने जाने के हकदार नहीं होंगे, जब तक कि न्यायालय ऐसा करना उचित और उचित नहीं समझता है; (4) संबंधित पक्ष आगे के निर्देश लेने के लिए 21 अगस्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे; और (5) कि निर्देश की सुनवाई सभी संबंधितों की उचित सुविधा के अधीन 11 सितंबर, 1978 को शुरू होगी।

इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा 4 तारीख को नोटिस जारी किए गए थे।

अगस्त स्वयं भारत संघ और 22 राज्यों के महा अधिवक्ताओं के लिए। इसके तुरंत बाद समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किए गए। 21 अगस्त तक, न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त किए गए थे जिसमें कहा गया था कि आवेदकों को या तो पक्षकारों के रूप में संदर्भ में शामिल किया जाना चाहिए या वैकल्पिक रूप से उन्हें कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 21 अगस्त को, न्यायालय ने सभी इच्छुक पक्षों को सुनने के बाद एक आदेश

पारित किया कि वह किसी को भी संदर्भ के लिए एक औपचारिक पक्ष के रूप में शामिल करना आवश्यक नहीं मानता है। द.

हालाँकि, न्यायालय ने 18 व्यक्तियों और 2 राज्य सरकारों को कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। वे अठारह हैं: सर्वश्री वी. सी. शुक्ला, ज्ञानी जैल सिंह, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, बंसी लाल, हरिदेव जोशी, प्रणव मुखर्जी, आर. के. धवन, जगमोहन, पी. एस. भिंडर, शिव कुमार अग्रवाल, सुरिंदर सिंह, देव राज उर्स, नारायण दत्त तिवारी, जगन्नाथ मिश्रा, राम लाल, राम जेठमलानी, सी. एम. स्टीफन और कमलापति त्रिपाठी। जिन दो राज्य सरकारों को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई थी, वे हैं कर्नाटक राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य। पक्षकार के रूप में शामिल किए जाने या हस्तक्षेप के लिए अन्य सभी के आवेदनों को खारिज कर दिया गया।

लिखित विवरण भारत संघ, अधिवक्ताओं द्वारा दायर किए गए थे।

जनरल, दोनों राज्य सरकारें और हस्तक्षेप करने वाले।

आरई: विशेष अदालतों का बिल

497

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

जम्मू और कश्मीर राज्य ने सुनवाई की तारीख पर शिकायत की कि उसके महाधिवक्ता ने अपने लिखित संक्षिप्त विवरण में एक रुख अपनाया है जो राष्ट्रपति द्वारा अदालत में फिर से भेजे गए प्रश्न पर राज्य सरकार के विचार को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसके बाद, जम्मू और कश्मीर राज्य को अपनी लिखित संक्षिप्त जानकारी दाखिल करने की अनुमति दी गई, जैसा कि उसे सलाह दी गई थी, और ऐसे अधिवक्ता के माध्यम से जो वह चाहता था। राज्य सरकार ने एक अन्य अधिवक्ता के माध्यम से अपना संक्षिप्त विवरण दाखिल किया।

सितंबर को संदर्भ की सुनवाई की शुरुआत में

19, कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं और कुछ महाधिवक्तों की ओर से पेश हुए वकील ने संदर्भ की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई और तर्क दिया कि विभिन्न कारणों से जिनका उनके द्वारा लिखित संक्षिप्त विवरणों में उल्लेख किया गया था, संदर्भ अक्षम और अमान्य था और इसलिए न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा अपने विचार और रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर देना चाहिए। चूंकि इसकी सराहना और निर्धारण और भारत संघ के मामले की समझ के लिए आवश्यक प्रारंभिक आपत्ति के रूप में, हमने उस आपत्ति पर विचार को तब तक के लिए

स्थगित कर दिया जब तक कि संदर्भ के समर्थन में तर्क समाप्त नहीं हो जाते। तदनुसार हमने सबसे पहले विद्वान अटॉर्नी जनरल, विद्वान सॉलिसिटर जनरल जो भारत संघ की ओर से पेश हुए, महाधिवक्ता जिन्होंने संदर्भ का समर्थन किया और श्री राम जेठमलानी, जो संदर्भ के सभी संभावित पहलुओं पर हस्तक्षेप करने वालों में से एक थे, को सुना। इसके बाद हमने दूसरे पक्ष को उसकी सभी दलीलों पर सुना, जिसमें प्रारंभिक आपत्ति भी शामिल थी कि संदर्भ बनाए रखने योग्य नहीं था। हम दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों के ऋणी हैं कि उन्होंने अपने लिखित विवरण और मौखिक तर्कों के माध्यम से सक्षम सहायता प्रदान की। लिखित संक्षिप्त विवरणों ने उनके संबंधित दृष्टिकोणों की एक स्पष्ट धारणा और समझ की सुविधा प्रदान की और परामर्श को, बिना अधिक अनुनय के, अपने मौखिक प्रस्तुतियों को उचित पक्ष में कम करने में सक्षम बनाया।

भागों।

हम इसे लेने से पहले प्रारंभिक आपत्ति का निपटारा करेंगे।

विचार के लिए अन्य बिंदु। संदर्भ की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति विभिन्न कारणों और परिस्थितियों पर आधारित है जिन्हें निम्नानुसार कहा जा सकता है:

श्री ए. के. सेन जो कर्नाटक राज्य के लिए उपस्थित होते हैं और

श्री धीरेंद्र ब्रह्मचारी तर्क देते हैं कि हमें अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि हम संदर्भ का उत्तर देने से इनकार कर दें क्योंकि यह एक काल्पनिक और काल्पनिक चरित्र का है और अस्पष्ट भी है। यह संदर्भ राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त, 1978 को दिया गया था, जो 4 अगस्त, 1978 को एक निजी सदस्य श्री राम जेठमलानी द्वारा लोकसभा में विशेष अदालत विधेयक पेश किए जाने से पहले ही था। विधेयक बन भी सकता है और नहीं भी।

एक कानून और भले ही यह विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, इसका एफ

[1979] 2 एस सी आर।

498

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसदीय बहस के दौरान प्रावधानों में मौलिक परिवर्तन हो सकते हैं। जहां तक अस्पष्टता का संबंध है, श्री सेन का तर्क है कि राष्ट्रपति ने एक व्यापक और सर्वव्यापी प्रश्न उठाया है कि

क्या विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाता है, तो कारणों या आधारों को निर्दिष्ट किए बिना संवैधानिक रूप से अमान्य हो जाएगा, जिसके आधार पर यह अमान्य हो सकता है। कोई कानून या तो विधायी क्षमता के अभाव में या इस कारण से संवैधानिक रूप से अमान्य हो सकता है कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। विद्वान वकील के अनुसार, संदर्भ में न केवल यह निर्दिष्ट किया गया है कि यदि यह एक अधिनियम बन जाता है तो इन दो कारणों में से कौन सा कारण विधेयक को अमान्य कर सकता है, बल्कि संदर्भ में उन मौलिक अधिकारों या अधिकारों का भी उल्लेख नहीं है जिनका उल्लंघन होने की संभावना है यदि विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है। रिलायंस को समर्थन में रखा गया था

कनाडा डोमिनियन के लिए अटॉर्नी जनरल में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर ये विवाद बनाम। ओंटारियो, क्यूबेक और नोवा स्कोटिया के प्रो विंस के लिए अटॉर्नी जनरल (1) के लिए अटॉर्नी जनरल

ओंटारियो बनाम। हैमिल्टन स्ट्रीट रेलवे कंपनी और अन्य (2)।

अल्बर्टा प्रांत के लिए महान्यायवादी बनाम। कनाडा के डोमिनियन के लिए अटॉर्नी जनरल (*)। कनाडा में वैमानिकी का विनियमन और नियंत्रण (1) और ओंटारियो और अन्य के लिए महान्यायवादी v. कनाडा और अन्य के लिए अटॉर्नी जनरल। (5) वकील ने संपदा शुल्क विधेयक (6) मामले में संघीय न्यायालय के निर्णय और केरल शिक्षा विधेयक (7) से संबंधित संदर्भों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया। बेरुबरी संघ और विनियम

एन्क्लेव्स (3), समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम विधेयक (ओ), यू. पी. विधान सभा

bly (1 0) और गुजरात विधान सभा (1) यह दर्शाती है कि जब

संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा कभी भी कोई संदर्भ दिया जाता है। संविधान, एक विशिष्ट प्रश्न या प्रश्न राय के लिए संदर्भित किए जाते हैं।

इस न्यायालय से। हमारा ध्यान अंततः एक निर्णय की ओर आकर्षित किया गया था

कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय (1) गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा धारा 55 के तहत कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए एक संदर्भ में

अल्बर्टा प्रांत की विधान सभा द्वारा पारित तीन विधेयकों की वैधता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम, 1927, जो राज्यपाल की खुशी के लिए आरक्षित थे।

(1) [1898] ए. सी. 700

(2) [1903] ए. सी. 524

(4) [1932] ए. सी. 54

(5) [1947] ए. सी. 127

- (6) [1944] एफ. सी. आर. 317
 (7) [1959] एस. सी. आर. 995
 (8) [1960] 3.सी. आर. 250
 (9) 1964] 3 एस. सी. आर 787
 (10) [1965] 1 एस. सी. आर. 413
 (11) [1975] 1 एस. सी. आर 504
 (12) [1938] कनाडा लॉ रिपोर्ट्स 100 (एस. सी.)

विशेष अदालतों का बिल

499

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

कर्नाटक राज्य के विद्वान महाधिवक्ता, जबकि

प्रारंभिक आपत्ति पर श्री सेन की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि हमें संदर्भ का जवाब देने से इनकार कर देना चाहिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी जा रही थी जैसे कि यह एक संयुक्त चयन समिति हो।

संसद का एक पद जिसे वह न तो भरने के लिए सुसज्जित है और न ही जिसे उसे स्वीकार करना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 143 (1), अनुच्छेद 143 (2) के एकदम विपरीत, "मई" शब्द का उपयोग करता है जो

इस न्यायालय के लिए विवेकाधिकार का एक व्यापक अंतर छोड़ता है कि किसी संदर्भ का उत्तर देना है या नहीं।

श्री वी. सी. शुक्ला की ओर से पेश श्री मृदुल ने इस पर आपत्ति जताई।

इस अतिरिक्त आधार पर कि राष्ट्रपति द्वारा अतीत में सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए सभी संदर्भ संस्थागत महत्व के थे, वर्तमान संदर्भ व्यक्तिगत महत्व के संदर्भ का एक अलग और अनूठा

मामला था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि संदर्भ का दोष राष्ट्रपति में निहित है जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रश्न पर इस न्यायालय की राय मांगता है जिसे

न्यायालय को अपनी राय व्यक्त करने से रोके।

श्री फ्रैंक एंथनी जो श्री कमलापति त्रिपाठी नेता के लिए दिखाई देते हैं

राज्यसभा में विपक्ष ने यह तर्क देते हुए अपना तर्क खोला कि विशेष न्यायालय विधेयक जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है और इसलिए संदर्भ अक्षम है। उन्होंने पूरी गंभीरता से कहा

कि यदि विधेयक के प्रस्तावक को उसके भौतिक अस्तित्व के संदर्भ में कुछ भी होता है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा और फिर इस न्यायालय के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हालाँकि, श्री एंथनी के सामने निष्पक्षता से यह कहा जाना चाहिए कि उन्होंने आशा व्यक्त की कि विधेयक का प्रस्तावक सौ साल तक जीवित रह सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने विधेयकों को वापस लेने से संबंधित लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 110 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो दर्शाता है कि किसी विधेयक का प्रभारी सदस्य, सामान्य रूप से, जब भी वह ऐसा करना चाहता है, विधेयक को वापस ले सकता है। वकील ने खुलासा किया कि जो विधेयक पेश किया गया था

एक "लोक अभियोजक" द्वारा अप्रत्यक्ष राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित था। वकील ने कहा कि हमारे पास लोकसभा से विधेयक को "उठाने" की कोई शक्ति नहीं है और इसकी संवैधानिक वैधता पर विचार करें।

श्री एम. सी. भंडारे जो श्री बंसीलाल और अन्य लोगों की ओर से पेश होते हैं

उन्होंने तर्क दिया कि हमें संदर्भ का जवाब देने से इनकार कर देना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति पर संदर्भ देने की जो अनिवार्यता प्रबल है, वह राजनीतिक है और संवैधानिक नहीं है। वकील ने आगे इस लेख पर जोर दिया

143 (1) इसे इस तरह से नहीं अपनाया जा सकता है जिससे संविधान के अनुच्छेद 32 को वस्तुतः निरस्त किया जा सके। वकील ने खूब ध्यान आकर्षित किया

फेलिक्स फ्रैंकफर्टर के एक लेख पर जो बाद में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो हार्वर्ड लॉ रिव्यू में उपस्थित हुए। लेखक इसमें कहता है कि यह अत्यंत था

[1979] 2 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

500

संवैधानिक विवादों के लिए सलाहकार राय के साधन के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए खतरनाक, कि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय कानून पर पुनर्विचार शक्तियों के साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं था, कि विधायिका को अपने रचनात्मक कार्य से वंचित नहीं किया जा सकता है और यदि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधता पर अपनी सलाहकार राय देने के लिए कहा जाता है, तो यह विधायी और लोकप्रिय जिम्मेदारी को कमजोर कर देगा। जेम्स ब्रैडली थायर की 'लाइफ ऑफ मार्शल' से इस प्रभाव के लिए एक अंश निकालने के बाद कि अदालतों के संदर्भ लोगों की राजनीतिक क्षमता को कम करते हैं और इसकी नैतिक जिम्मेदारी की भावना को कम करते हैं, विद्वान लेखक ने अपने लेख का समापन इस प्रकार किया:

यह याद रखना चाहिए कि सलाहकार राय केवल नहीं होती हैं।

सलाहकार राय। वे भूत हैं जो मारते हैं।

श्री शिव शंकर जो आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उपस्थित होते हैं

और श्री प्रणव मुखर्जी ने अपनी प्रारंभिक आपत्ति को इस आधार पर स्थापित किया कि चूंकि संसद ने विधेयक को अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए हमें संदर्भ का जवाब नहीं देना चाहिए।

श्री बोबडे जो श्री सी. एम. स्टीफन, नेता के लिए उपस्थित होते हैं

लोकसभा में विपक्ष और श्री जगन्नाथ मिश्रा की ओर से तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 105 (3) में हमारे मनोरंजन के खिलाफ एक संवैधानिक प्रतिबंध है

संदर्भ क्योंकि यह संसद की शक्ति और विशेषाधिकार है न कि इस न्यायालय की यह तय करने की कि क्या विधेयक को अधिनियम बनना चाहिए और क्या विधेयक के प्रावधान असंवैधानिक हैं।

श्री ओ. पी. शर्मा जो श्री जैल सिंह के लिए और श्री ओ. पी. शर्मा श्री जैल सिंह के लिए उपस्थित होते हैं।

हरिदेव जोशी ने इसी तरह का तर्क देते हुए कहा कि हमारी राय के बिना, संसद इसके प्रावधानों पर उचित चर्चा के बाद विधेयक को पारित करने में अपनी शक्ति के भीतर होगी और इसलिए हमें संदर्भ का जवाब नहीं देना चाहिए।

श्री जगमोहन की ओर से श्री शिव पूजन सिंह उपस्थित हुए और

श्री पी. एस. भिंडर ने तर्क दिया कि संदर्भ अक्षम है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 107 (1), 108 और 111 का उल्लंघन करता है। उनका तर्क है कि यदि हम संदर्भ का उत्तर देते हैं, तो संसद और वास्तव में स्वयं राष्ट्रपति की शक्तियों और विशेषाधिकारों को, जो संविधान के उपरोक्त प्रावधानों द्वारा प्रदत्त हैं, कम कर दिया गया होगा या उनका अतिक्रमण किया गया होगा।

जब भी इस विषय में हस्तक्षेप करने वालों की समान रुचि होती है

कार्यवाही का मामला अलग-अलग वकीलों के माध्यम से सामने आता है, उनके तर्कों में एक निश्चित मात्रा में अतिव्यापी है, जिससे बचा नहीं जा सकता है कि कैसे प्रत्येक वकील इस आश्वासन के साथ शुरू कर सकता है, और वास्तव में, कि वह एक बार फिर उसी आधार को कवर नहीं करेगा। आर. ई. मारना:

विशेष अदालतों का बिल

501

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

नया मार्ग जब इतने सारे लोग जो पहले ही एक ही क्षेत्र में चल चुके हैं, हासिल करने की तुलना में आसान सुनिश्चित है, हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे सामने के वकील ने समय सारिणी का पालन करने और इस सवाल पर कुछ नया प्रकाश डालने का पूरा प्रयास किया कि क्या संदर्भ वैध है और क्या हमें इसका जवाब देना चाहिए या नहीं।

प्रारंभिक पर अभिसरण करते हुए विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण करना

आपत्ति, निम्नलिखित विवाद हमारे विचार के लिए उभरते हैं: (1) कि संदर्भ काल्पनिक और चरित्र में सट्टा है;

(2) कि संदर्भ अस्पष्ट, सामान्य और सर्वव्यापी है; (3) कि तब से

संसद विधेयक को ज्वल कर लेती है, यह इसका अनन्य कार्य है

विधेयक की संवैधानिकता का उल्लेख करें और यदि हम अपने विचार और रिपोर्ट के लिए उस प्रश्न को वापस लेते हैं, तो हम उस पर अतिक्रमण करेंगे।

यदि मनोरंजन किया जाता है, तो वस्तुतः लाभकारी और हितकारी का स्थान ले लेगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधान; (5) यह हमारे लिए व्यर्थ है

विधेयक की संवैधानिकता पर विचार करें क्योंकि जो कुछ भी हो सकता है

हमारा विचार है कि यह संसद के लिए विधेयक पर चर्चा करने के लिए खुला रहेगा और संशोधन के साथ या उसके बिना इसे पारित करना या न करना; (6) पुनः

उग्रता विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक सवाल उठाती है जिससे हमें बचना चाहिए जवाब देने से; और (7) अभ्यास के नतीजों पर विचार करना।

सलाहकार अधिकारिता की, समीचीनता और औचित्य दोनों की मांग है कि बिना उत्तर दिए संदर्भ को वापस कर देना चाहिए। हम इन पर विचार करेंगे।

हमें

विवादों की श्रृंखला।

संविधान के अनुच्छेद 143 के खंड (1) के तहत -

राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को यह संदर्भ इस प्रकार दिया है -

निम्नलिखित है:

143 (1) यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि

कानून या तथ्य का प्रश्न उत्पन्न हुआ है, या होने की संभावना है

उत्पन्न होता है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसी सार्वजनिक है

उस पर सर्वोच्च न्यायालय का, वह संदर्भित कर सकता है

विचार के लिए उस न्यायालय से प्रश्न और

न्यायालय, ऐसी सुनवाई के बाद, जो वह उचित समझे, रिपोर्ट कर सकता

है।

राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय दें।

(2) राष्ट्रपति, किसी भी बात के बावजूद,

अनुच्छेद 131 का परंतुक इस प्रकार के विवाद का उल्लेख करता है

उच्चतम न्यायालय के उक्त परंतुक में उल्लिखित

राय के लिए और उच्चतम न्यायालय, इस तरह के बाद

सुनवाई जैसा वह उचित समझता है, राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करें

ए.

उस पर राय।

№ .

[1979] 2 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

502

अनुच्छेद 143 (1) को व्यापक शब्दों में जोड़ा गया है जो प्रदान करता है कि

कानून या तथ्य का कोई भी प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है

उच्चतम न्यायालय का विचार यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि

प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है और यदि प्रश्न इस प्रकार का है

ऐसी प्रकृति और सार्वजनिक महत्व की जो प्राप्त करना समीचीन हो।

के तहत किए गए छह सदस्यों में से किसी में भी इस न्यायालय को भेजा गया था

अनुच्छेद 143 (1), वह अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनः अधिकार देने का अधिकार देता है।

तथ्य के प्रश्नों पर भी उग्रता ने अन्य शर्तों को प्रदान किया

लेख संतुष्ट हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जिस प्रश्न पर

उच्चतम न्यायालय की राय मांगी गई है जो वास्तव में उत्पन्न हुई होगी।

राष्ट्रपति अनुच्छेद के तहत संदर्भ देने के लिए सक्षम है। 143 (1)
पूर्ववर्ती अवस्था में, अर्थात् उस अवस्था में जब राष्ट्रपति

संतुष्ट है कि सवाल उठने की संभावना है। संतुष्टि है कि क्या प्रश्न उत्पन्न
हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है और क्या यह ऐसा है

ऐसी प्रकृति और सार्वजनिक महत्व की जो प्राप्त करना समीचीन हो।

इस पर उच्चतम न्यायालय की राय अनिवार्य रूप से एक मामला है।

राष्ट्रपति को निर्णय लेना है। का सादा कर्तव्य और कार्य

संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह आदेश देना है कि

वह प्रश्न जिस पर राष्ट्रपति ने संदर्भ दिया है और

राष्ट्रपति को अपनी राय दें, बशर्ते कि सवाल यह हो

पर उच्चारण करने में सक्षम और की शक्ति के भीतर आता है फैसला अदालत को
करना है। यदि, प्रश्न के तरीके के कारण

तैयार किया गया है या किसी अन्य उचित कारण के लिए न्यायालय इसे मानता है

उस प्रश्न का उत्तर देना उचित या संभव नहीं है जिसका वह हकदार होगा

इसका उत्तर देने में बाधाओं को इंगित करके संदर्भ को वापस करें।

इस न्यायालय का किसी संदर्भ का उत्तर देने से इनकार करने का अधिकार केवल संविधान के
खंड (1) और (2) में उपयोग किए गए विभिन्न वाक्यांशों से नहीं निकलता है।

अनुच्छेद 143. इस अर्थ में कि खंड (1) में यह प्रावधान है कि न्यायालय " "
राष्ट्रपति को निर्दिष्ट प्रश्न पर अपनी राय दे सकते हैं।

जबकि खंड (2) में यह प्रावधान है कि न्यायालय राष्ट्रपति को इस प्रश्न पर अपनी राय
"बताएगा"। खंड (2) के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में भी, हालांकि वह प्रश्न इस संदर्भ में
उत्पन्न नहीं होता है, न्यायालय बिना उत्तर दिए संदर्भ को वापस करने में उचित हो सकता है यदि
वह किसी वैध कारण से पाता है कि प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है। इन प्रारंभिक टिप्पणियों के
साथ हम सेट किए गए विवादों पर विचार करेंगे।

ऊपर।

हम इस बात से सहमत होने में असमर्थ हैं कि संदर्भ इस आधार पर एक काल्पनिक या सट्टा चरित्र का है कि विधेयक अभी तक एक अधिनियम नहीं बना है। यह सच है कि विधेयक का प्रस्तावक विधेयक को वापस ले सकता है या विधेयक में मौलिक चरित्र आरई के व्यापक संशोधन किए जा सकते हैं:

विशेष अदालतों का बिल

503

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

इसे पारित करने से पहले, अगर इसे बिल्कुल भी पारित किया जाता है। लेकिन ये विचार उस अंक पर संदर्भ की वैधता को प्रभावित नहीं कर सकते हैं कि

संदर्भ एक काल्पनिक या सट्टा प्रकृति के सवाल उठाता है।

एक संदर्भ या शर्तों का निरंतर अस्तित्व जिसके आधार पर कानून या तथ्य का प्रश्न उत्पन्न होता है या उत्पन्न होने की संभावना है। राजनीतिक

उस जीवन के पहलू और पहलू को उचित रूप से क्षणिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लेकिन बदलाव की संभावना, यहां तक कि एक बुनियादी बदलाव की भी, हो सकती है

अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग न करें 143 अटकलबाजी या काल्पनिक। ठोस तथ्य यह है कि संसद

इसके समक्ष विशेष न्यायालय विधेयक नामक एक विधेयक है

एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह कि विधेयक में दस खंड हैं

जो कुछ अपराधों और अपराधियों के मुकदमे के लिए प्रावधान करता है। वहाँ

विधेयक में भविष्य में बदलाव हो सकते हैं लेकिन संविधान में भी बदलाव हो सकते हैं। स्वयं, अनुच्छेद 143 सहित, जिसके तहत राष्ट्रपति ने

इस न्यायालय का संदर्भ। पूर्व संभावना नहीं बना सकती है

बाद की संभावना से अधिक अटकलबाजी या काल्पनिक संदर्भ

सामर्थ्य इसे ऐसा बना सकता है। विशेष न्यायालय विधेयक मूल रूप से है और किसी को भी देखने और जांच करने के लिए रक्त। यह संदर्भ को बनाए रखता है, जो राष्ट्रपति की संतुष्टि पर आधारित है कि एक प्रश्न विधेयक की संवैधानिक वैधता के संबंध में उत्पन्न होने की संभावना है और यह कि सवाल ऐसी प्रकृति का है और इस तरह के सार्वजनिक महत्व का है कि इस पर इस न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है।

अतीत में हमारे संविधान के तहत तीन संदर्भ दिए गए थे, एक सुविचारित विधान के संबंध में और उस उपाय के संबंध में नहीं जो पहले से ही एक अधिनियम बन चुका था। एस्टेट शुल्क मामले (ऊपर) में, गवर्नर जनरल ने संघीय न्यायालय का संदर्भ दिया था

भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 233 (1) के तहत जो संविधान के अनुच्छेद 143 (1) से मेल खाती है, सिवाय इसके कि पूर्व प्रावधान के तहत गवर्नर जनरल की संघीय न्यायालय को संदर्भित करने की शक्ति कानून के प्रश्नों तक सीमित थी। सर पैट्रिक स्पेंस, सी. जे. ने बहुमत की राय देते हुए कहा कि इस तथ्य को कि भविष्य के विधान से संबंधित प्रश्नों को स्वयं संदर्भ के लिए एक वैध आपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, आंशिक रूप से क्योंकि धारा 214 ने गवर्नर जनरल को एक संदर्भ देने का अधिकार दिया, तब भी जब कानून के प्रश्न "उत्पन्न होने की संभावना" थी। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे उदाहरण न्यायालय के ध्यान में लाए गए थे जिनमें सुधार [1979] 2 एस. सी. आर. के तहत संदर्भ दिए गए थे।

504

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में प्रावधान पर विचार करना जब मामला एक विधेयक के चरण में था। केरल शिक्षा विधेयक मामले में, (उपर्युक्त) राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 (1) के तहत एक संदर्भ दिया गया था। किसी विधेयक के प्रावधानों की वैधता के संबंध में संविधान

जिसे राज्य विधान सभा द्वारा पारित किया गया था लेकिन जिसने यह एक अधिनियम नहीं बन गया क्योंकि राज्यपाल ने विधेयक को इसके लिए आरक्षित कर रखा था

राष्ट्रपति का विचार। दास, सी. जे., जिन्होंने बहुमत के लिए बात की (जे. वेंकरामा अय्यर ने संबंधित एक अन्य मुद्दे पर असहमति जताई विधेयक के खंड 20 की वैधता), जिसे इस दृष्टिकोण के अनुमोदन के लिए संदर्भित किया गया था

एस्टेट शुल्क विधेयक मामले में सर पैट्रिक स्पेंस सी. जे. द्वारा व्यक्त किया गया (ऊपर) और अपने तर्क को अपनाया कि तथ्य यह है कि संदर्भ था विधेयक के चरण में किया गया विचार के लिए कोई बाधा नहीं थी न्यायालय द्वारा अपनी राय के लिए भेजे गए प्रश्नों के लिए। में समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम विधेयक, (ऊपर) उप-धारा में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था।

(2) समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 20 और उप-धारा (1 ए) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3। सवाल यह है अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय की राय के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट 143 (1) क्या प्रस्तावित संशोधन असंगत होंगे संविधान के अनुच्छेद 289 के प्रावधानों के साथ।

कनाडा में, गवर्नर-जनरल इन काउंसिल ने एक प्रश्न भेजा सुप्रीम कोर्ट की धारा 55 के तहत कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय अधिनियम, 1927 किसी विधेयक की वैधता पर विचार करने के लिए जिसमें उपबंध किया गया है -

प्रिवी काउंसिल में अपीलों को समाप्त करने और पूर्व को निहित करने के लिए कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में भ्रामक अंतिम अधिकार क्षेत्र। नहीं।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि विधेयक पर पहले विचार किया जाना बाकी था

कनाडाई संसद जब संदर्भ दिया गया था, सुप्रीम

कनाडा के न्यायालय ने इस संदर्भ का मनोरंजन किया और जवाब दिया। याचिका में कहा गया है,

पि्रवी काउंसिल ने संदर्भ के गुण-दोष पर कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले की पुष्टि की। न ही कनाडाई

कि किसी विधेयक से संबंधित संदर्भ, न कि किसी अधिनियम से, वली को प्रभावित करता है संदर्भ की स्थिति। पि्रवी काउंसिल के फैसले की सूचना दी गई है

ओंटारियो और अन्य के लिए अटॉर्नी-जनरल बनाम। अटॉर्नी-कनाडा और अन्य के लिए जनरल।
(1)

एक और कनाडाई मामला है जिसे संदर्भित किया जा सकता है

तीन विधेयकों का मामला (2) जो केरल शिक्षा विधेयक (3) मामले के समान है। अल्बर्टा प्रांत की विधान सभा द्वारा पारित किए गए तीन विधेयकों को उपराज्यपाल द्वारा गवर्नर जनरल की खुशी के लिए आरक्षित रखा गया था।

(1) [1947] ए. सी. 127

(2) [1938] कनाडा लॉ रिपोर्ट्स, 100।

(3) [1959] एससीआर 995।

आरई: विशेष अदालतों का बिल

505

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

यह संदेह उत्पन्न होने पर कि क्या अल्बर्टा प्रांत के विधानमंडल के पास विधेयकों के प्रावधानों को लागू करने के लिए विधायी अधिकार क्षेत्र था, गवर्नर-जनरल इन काउंसिल ने इस सवाल पर कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया कि क्या विधेयक अल्बर्टा प्रांत के विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में थे। यह तथ्य कि विधेयक अभी तक अधिनियम नहीं बने थे, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ की वैधता को प्रभावित करने के रूप में नहीं माना गया था।

हम उचित समय पर उद्धृत कुछ अन्य निर्णयों पर चर्चा करेंगे।

हस्तक्षेप करने वालों द्वारा जिन्होंने प्रारंभिक आपत्ति उठाई

संदर्भ की रखरखाव क्षमता। लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उपरोक्त कारण,
कि संदर्भ में काल्पनिक या अटकलबाजी है

चरित्र और इसलिए, बिना उत्तर दिए वापस किया जाना चाहिए।

संदर्भ की रखरखाव के लिए दूसरी आपत्ति है

कि यह अस्पष्ट, सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति का है। सवाल यह है
राष्ट्रपति द्वारा इस न्यायालय को भेजा गया है

चाहे वह विधेयक हो या उसका कोई प्रावधान, यदि -

अधिनियमित, संवैधानिक रूप से अमान्य होगा?

यह सच है कि संदर्भ विशिष्टता के साथ निर्दिष्ट नहीं करता है

वह आधार या आधार जिसके आधार पर विधेयक या उसके कोई प्रावधान लागू हो सकते हैं।
संविधान के तहत हमले के लिए तैयार रहें। इसका उल्लेख नहीं है कि

की विधायी क्षमता के बारे में किसी भी संदेह पर विचार किया जाता है

संसद विधेयक को अधिनियमित करे या क्या यह आशंका है कि यह विधेयक है।
यदि अधिनियमित किया जाता है, तो किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा और यदि
ऐसा है, तो

विशेष मौलिक अधिकार या अधिकार। इतने व्यापक रूप में एक संदर्भ

और सामान्य शब्दों का उत्तर देना मुश्किल है क्योंकि यह कोई संकेत नहीं देता है

उस विशिष्ट बिंदु या बिंदु पर जिस पर न्यायालय की राय है

की तलाश की। यह उचित या वांछनीय नहीं है कि इस न्यायालय को बुलाया जाए।

की संवैधानिकता की एक घूमती हुई जांच शुरू करने पर

एक विधेयक या एक अधिनियम। इस तरह के पाठ्यक्रम को वस्तुतः अपनाने की आवश्यकता
है

सभी उचित रूप से कल्पनीय के संबंध में उन्मूलन की एक प्रक्रिया

संविधान के तहत चुनौती। यह हमसे अपेक्षित नहीं है जबकि

बैठने और खोज करने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत एक संदर्भ का जवाब देना, लेख

अनुच्छेद द्वारा, संविधान के किस प्रावधान में होने की सबसे अधिक संभावना है

यदि यह कानून बन जाता है तो विधेयक की वैधता पर जोर दिया। द.

न्यायालय को किसी चुनौती की कल्पना करने और उसे बचाने के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए या

काल्पनिक विचारों पर इसका वध करें। जैसा कि हैमिल्टन स्ट्रीट में देखा गया है

रेलवे कंपनी (1), काल्पनिक प्रश्नों पर सट्टा राय बेकार हैं और यह
सिद्धांत के विपरीत है, असुविधाजनक है और

इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों पर राय दी जानी चाहिए।

(1) [1903] ए. सी. 524,529।

14-978 एएफटी में एससीआई/78

[1979] 2 एस सी आर।

506

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हम, बहस के एक चरण में, इस पर बहुत अभ्यास कर रहे थे

उस संदर्भ की अनिर्धारित चौड़ाई जिस पर हम विचार कर रहे थे

गंभीर रूप से क्या परिस्थितियों में लौटने की सलाह नहीं दी गई थी

संदर्भ अनुत्तरित। लेकिन पक्षों द्वारा दायर लिखित विवरण।

और हमारे सामने दिए गए मौखिक तर्क अपनी पूर्णता के आधार पर हैं।

और क्षमता, आसपास के कानूनी विवादों को कम करने में मदद की

विधेयक और उन मुद्दों को स्पष्ट करना जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं।

हम अपनी राय को पहले विशेष रूप से उठाए गए बिंदुओं तक सीमित रखने का प्रस्ताव करते हैं। हमें इस स्तर पर यह इंगित करना सुविधाजनक होगा कि वे बिंदु क्या हैं।

हैं।

हमारे सामने पहला मुद्दा यह उठाया गया कि क्या संसद ने

विशेष अधिनियम में निहित प्रावधानों को लागू करने के लिए विधायी क्षमता

न्यायालय विधेयक। हमारे सामने उठाया गया दूसरा मुद्दा यह है कि क्या विधेयक

या इसके किसी भी प्रावधान से अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होता है।

और संविधान के 21. हम अपनी राय को सीमित करने का प्रस्ताव करते हैं

इन बिंदुओं।

डोमिनियन में प्रिंसीपल काउंसिल के निर्णयों पर भरोसा करना

कनाडा का (1) और वैमानिकी का विनियमन और नियंत्रण, (*) यह था

तर्क दिया कि संदर्भ एक ए. बी. पर इस न्यायालय की राय को अलग करता है

संक्षिप्त प्रश्न और इसलिए हमें इसका उत्तर देने से इनकार कर देना चाहिए। हम हैं।

इस निवेदन से सहमत होने के लिए तैयार नहीं है कि प्रश्न निर्दिष्ट किया गया है

क्योंकि हमारी राय भले ही व्यापक और सामान्य हो, लेकिन किसी भी मायने में अमूर्त है।

जिस प्रश्न का हमें उल्लेख किया गया है वह संवैधानिकता के संबंध में है।

विधेयक या उसके किसी भी प्रावधान का। विधेयक की संवैधानिक वैधता पर हमारी राय जिस हद तक मांगी जाती है, वह इस प्रकार है -

यह कहना संभव है कि हमें संदर्भित प्रश्न एक अमूर्त प्रकृति का है।

ऊपर उद्धृत दो मामलों में से पूर्व में, प्रिंसीपल काउंसिल ने पाया

संदर्भ कार्यवाही में यह निर्धारित करना असुविधाजनक है कि क्या

यह बिल्कुल "सार्वजनिक बंदरगाह" अभिव्यक्ति के दायरे में आता है। यह.

इसलिए इसके संबंध में प्रश्न को अमूर्त के रूप में वर्णित किया गया। प्रिंसीपल काउंसिल के सामने की परिस्थितियों में, यह असंभव था कि

"सार्वजनिक बंदरगाह" अभिव्यक्ति की एक विस्तृत परिभाषा का प्रयास करें।

जो सभी मामलों पर लागू होगा, क्योंकि यह सोचा गया था कि एक परिभाषा "भ्रामक और खतरनाक" साबित होने की संभावना थी। में

बाद के मामले में, प्रिंसीपल काउंसिल ने उस कठिनाई की सराहना की जो अदालत को उस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में अनुभव करनी चाहिए जो

कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की राय के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन फिर भी, प्रश्नों का उत्तर दिया गया क्योंकि वे उस तरह के नहीं थे जिनका संतोषजनक उत्तर देना संभव नहीं था।

(1) [1898] ए. सी. 700,711

(2) [1932] ए. सी. 54,66

आरई: विशेष अदालतों का बिल

507

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

हम आशा करते हैं कि भविष्य में जब भी इसका कोई संदर्भ दिया जाएगा

संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अदालत का ध्यान रखा जाएगा

न्यायालय की राय के लिए विशिष्ट प्रश्न तैयार करें। सौभाग्य से, तत्काल संदर्भ में विशिष्ट प्रश्नों पर विचार करना संभव हुआ है।

संदर्भ की शर्तों के भीतर समझा जा रहा है लेकिन

जोखिम है कि एक अस्पष्ट और सामान्य संदर्भ बिना उत्तर दिए वापस किया जा सकता है वास्तविक है और उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए जिनका कर्तव्य है

संदर्भ की रूपरेखा बनाएँ। यदि विधेयक उतना छोटा नहीं होता जितना वह है, तो यह

संदर्भ को समझने में कठिनाई हुई है

ऊपर हमारे द्वारा उल्लिखित दो बिंदु और जिनका हम प्रस्ताव करते हैं

तय कीजिए। एक लंबा विधेयक विशिष्ट बिंदुओं पर संदर्भ के अभाव में हमारे सामने एक जटिल कार्य प्रस्तुत करता, जिससे विधेयक के पक्ष में संवैधानिक चुनौती की प्रकृति को संक्षिप्त रूप से तैयार करना असंभव हो जाता।

तीसरा विवाद जागरूकता की कुल कमी को दर्शाता है

हमारे संविधान के तहत शक्तियों के विभाजन की योजना। पहला अंग

इस शीर्ष के तहत तर्क यह है कि चूंकि संसद को जब्त कर लिया गया है

विधेयक के प्रावधानों के संविधान पर निर्णय लेना विधेयक का अनन्य कार्य है। अन्यत्र की तरह यहाँ भी कुछ लोग हैं जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। विधान, तर्क देता है कि यह विधायिका है जिसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है और उसे होना चाहिए और विधायी व्याख्या कानून की अदालतों में हमले के लिए खुली नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम।

व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित काल्पनिक सिद्धांतों से संबंधित नहीं हैं

लेकिन हमारे संविधान की योजना और 'झूठ बोलने' के तहत दर्शन के साथ। हमारा संघीय या अर्ध-संघीय संविधान न्यायपालिका की स्थापना के लिए एक प्रचुर लिखित साधन प्रदान करता है

संघ और राज्य स्तर। अनुच्छेद 124, जो के अध्याय IV में आता है

"संघ न्यायपालिका" नामक संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। इसकी शक्तियाँ और कार्य हैं -

अनुच्छेद 32 (2), अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131 से 140 और अनुच्छेद में परिभाषित 143 संविधान से। इसी तरह, अनुच्छेद 214 के अधीन प्रदान करता है -

अनुच्छेद 232, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए।

अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अधीनस्थ सभी न्यायालय। ये प्रावधान यह दर्शाता है कि कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने की शक्ति

राशन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में निहित है और किसी अन्य निकाय में नहीं है। ब्रिटिश संसद, सर्वोच्च होने के नाते, कोई सवाल नहीं है

इंग्लैंड में उसके द्वारा पारित कानूनों की वैधता के संबंध में उत्पन्न हो सकता है। द.

हमारे संविधान के तहत स्थिति मौलिक रूप से अलग है क्योंकि,

भारतीय विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों की वैधता का परीक्षण किया जाना है 508

[1979] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधायी शक्तियों की योजना/वितरण के संबंध में और अन्य संवैधानिक सीमाओं जैसे कि

हमारे संविधान का अनुच्छेद 13। भारतीय न्यायपालिका का अधिकार

एक कानून को अमान्य घोषित करें यदि यह संविधान के साथ संघर्ष करता है यह केवल एक मौन धारणा नहीं है, बल्कि हमारे संविधान का एक स्पष्ट वचन है।

ट्यूशन। यह सिद्धांत दृढ़ता से और बुद्धिमानी से हमारे संविधान में अंतर्निहित है। विधान कि विधि की नीति और इसे पारित करने की समीचीनता

विधायिकाक लेल निर्णय करबाक लेल मामला, कानूनक व्याख्या आ उनकी वैधता के बारे में प्रश्न विशेष सलाहकार के अंतर्गत आते हैं या

न्यायालयों के न्यायिक कार्य। उस में न्यायालयों का कार्य होगा

आधा "महान दुरुपयोग" नहीं है जैसा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति के कुछ अमेरिकी आलोचकों ने इसे अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1856 में ड्रेड-स्कॉट (1) में अपना निर्णय देने के बाद कहा था। बल्कि। सच है

राष्ट्रपति लिंकन ने उस कार्य की प्रकृति का वर्णन किया है:

हम उतना ही विश्वास करते हैं जितना जज डगलस (शायद अधिक)

न्यायिक विभाग के प्रति आज्ञाकारिता और सम्मान में सरकार। हमें लगता है कि इसके फैसले संवैधानिक मुद्दों पर लिए गए हैं।

जब राज्य पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं, तो उन्हें न केवल पार्टी को नियंत्रित करना चाहिए कुलर मामलों का फैसला किया गया, लेकिन देश की सामान्य नीति,

केवल संविधान के संशोधनों से परेशान होने के अधीन

ट्यूशन जैसा कि उस उपकरण में ही प्रदान किया गया है। इससे भी ज्यादा

क्रांति होगी, लेकिन हमें लगता है कि ड्रेड स्कॉट का निर्णय है

गलत है। हम उस अदालत को जानते हैं जिसने इसे अक्सर बनाया है अपने स्वयं के निर्णयों को खारिज कर दिया, और हम वह करेंगे जो हम कर सकते हैं

इसे रद्द कर दें। हम इसका कोई विरोध नहीं करते हैं।

विवाद का दूसरा अंग यह है कि अगर हम वापस ले लेते हैं

हमारे विचार के लिए विधेयक की वैधता का प्रश्न जब तक कि विधेयक है

संसद के समक्ष विचार लंबित है, हम अतिक्रमण करेंगे संसद के कार्यों और विशेषाधिकारों पर। सबसे पहले

इसके स्थान पर, संदर्भ से निपटने में हम संसद के अभिग्रहण से किसी भी मामले को वापस नहीं ले रहे हैं, लोकसभा से बिल्ट को "उठाना" बहुत कम है, जैसा कि एक वकील ने तर्क दिया था। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 (1) द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय का संदर्भ दिया है और हम इसके अधीन हैं।

संदर्भ पर विचार करने और उस पर रिपोर्ट करने का न्यायिक दायित्व

राष्ट्रपति को जितना हो सके उतना अच्छा। दूसरा, यह समझना मुश्किल है कि संसद का कौन सा विशेष कार्य या विशेषाधिकार जानबूझकर है

या अनजाने में, विधेयक की संवैधानिक वैधता पर हमारे विचार से अतिक्रमण किया गया। जैसा कि हमने अभी कहा है, सवाल यह है कि क्या विधेयक के प्रावधान किसी भी संवैधानिक अयोग्यता से ग्रस्त हैं

(1) 15 वकीलों का संस्करण 691।

आरई: विशेष अदालतों का बिल

509

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

निर्णय लेने के लिए न्यायालयों के वैध क्षेत्र के भीतर। जब तक विधेयक विचाराधीन है, संसद निस्संदेह उस प्रश्न पर चर्चा और बहस कर सकती है, लेकिन कानून की वैधता पर अंतिम निर्णय अदालत का होना चाहिए, न कि संसद का। इसलिए, यदि हम विधेयक की वैधता पर जोर देते हैं तो हम किसी भी संसदीय विशेषाधिकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे। हमें यह भी उल्लेख करना चाहिए कि हालांकि यह तर्क दिया गया था कि संसद के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन कोई भी वकील यह निर्दिष्ट करने में सक्षम नहीं था कि संदर्भ पर हमारे विचार में कौन सा विशेष संसदीय विशेषाधिकार शामिल था। मई का

संसदीय अभ्यास का उल्लेख भी नहीं किया गया था। का अनुच्छेद 105 (3) जिस संविधान पर एक पारित निर्भरता रखी गई थी, वह प्रदान करता है कि

संसद के प्रत्येक सदन की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति

और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों में से, ऐसे होंगे -

जैसा कि समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित किया जा सकता है और जब तक इस तरह से परिभाषित नहीं किया जाता है, वे संयुक्त राज्य की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के होंगे।

राज्य, और

इसके सदस्यों और समितियों में,

की

शुरुआत

संविधान। किसी भी पाठ या प्राधिकरण के अभाव में

यह दर्शाते हुए कि ब्रिटिश संसद के विशेषाधिकार क्या हैं

हमारे सामने जिस तरह की बात है, यह मानना असंभव है कि वहाँ है

संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन। हम कोई पदार्थ भी नहीं देखते हैं।
में कि संसद की शक्तियों का कोई उल्लंघन हुआ है

इस तर्क

संविधान के अनुच्छेद 107 (1), 108 और 111 के तहत।

तब इस संदर्भ को अनुच्छेद 32 का वस्तुतः निरसन कहा जाता है।

संविधान का एक तर्क जिसे हम समान रूप से असमर्थनीय पाते हैं
अनुच्छेद 32 (1) सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है -

सक्षम हैं।

प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का रुख करें

संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लेख। कि

अधिकार उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनके मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जाता है।

पर। हमारे सामने कार्यवाही में सवाल यह है कि क्या विधेयक

संसद के समक्ष लंबित प्रावधानों में ये हैं -

एक संवैधानिक चुनौती के लिए खुला। यदि हम मानते हैं कि विधेयक वैध है,

संसद इसके साथ आगे बढ़ सकती है और, हम मानते हैं, कि अगर हम मान लेते हैं

कि विधेयक अमान्य है, संसद इस पर कोई समय नहीं खर्च करेगी

संवैधानिक रूप से अमान्य विधेयक पारित करना। अनुच्छेद के तहत कार्यवाही

32 (1) कार्यवाही से पूरी तरह से अलग प्रकृति का होना

संविधान के अनुच्छेद 143 (1) द्वारा प्रतिरूपित, न तो है

अनुच्छेद 32 का प्रतिस्थापन या निरसन, यदि हम
हमें संदर्भित प्रश्न।

राष्ट्रपति द्वारा

हस्तक्षेप करने वालों के लिए विद्वान वकील जो संदर्भ का विरोध करते हैं

इस संदर्भ पर हमले के तख्तों में से एक के रूप में आग्रह किया गया कि यह व्यर्थ है [1979]
2 एस. सी. आर.

510

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारे लिए विधेयक की संवैधानिक वैधता पर विचार करना क्योंकि क्या

हम जिस भी दृष्टिकोण को अपनाएँ, वह अभी भी संसद के लिए खुला रहेगा।

विधेयक को पारित करना और इसे अपनी इच्छानुसार पारित करना या न करना। यह तर्क

यह एक अवास्तविक आधार पर आगे बढ़ता है, इसकी धारणा यह है कि

संसद निष्पक्ष और उचित तरीके से कार्य नहीं करेगी। सच है कि

इस राय में हम जो कुछ भी कहते हैं, वह संसद को रोक नहीं सकता।

विधेयक के साथ आगे बढ़ना या इसे छोड़ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई अदालत ऐसा नहीं करेगी।

उसके समक्ष लंबित किसी विधेयक पर विचार करना। . लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते।
मान लीजिए, जो हमें उस प्रतिष्ठित निकाय के लिए अनुचित लगता है, वह भी

अगर हम मानते हैं कि विधेयक असंवैधानिक है, तो संसद इसका समर्थन करेगी।

जिन दोषों से इसे दिखाया गया है, उन्हें हटाए बिना इसे पारित करने के लिए बीज

पीड़ित होना। चूँकि विधेयक की संवैधानिकता एक ऐसा विषय है जो

अदालतों के अनन्य क्षेत्र के भीतर आता है, हम विश्वास करते हैं कि संसद वे
अदालत के फैसले पर ध्यान देने में विफल नहीं होंगे।

हम इस निवेदन को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि संदर्भ

यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक सवाल उठाता है। विधेयक की नीति और उद्देश्य प्रस्तावक का उद्देश्य उच्च पद धारण करने वाले व्यक्ति का त्वरित परीक्षण सुनिश्चित करना हो सकता है।

सार्वजनिक या राजनीतिक कार्यालय जिन पर कुछ अपराध करने का आरोप है

आपातकाल की अवधि से संबंधित अपराध। लेकिन राष्ट्रपति ने, हमें उसे पास करने की वांछनीयता के बारे में सलाह देने के लिए नहीं कहा है

विधेयक या उसमें अंतर्निहित नीति की दृढ़ता। क्या विशेष है

अदालतें स्थापित की जानी चाहिए या नहीं, क्या राजनीतिक अपराधियों को प्रदान किया जाए या नहीं, वे सभी मामले हैं जिन्हें एक का कहा जा सकता है राजनीतिक प्रकृति क्योंकि वे अंतर्निहित ज्ञान और नीति से संबंधित हैं

बिल। लेकिन यह सवाल कि क्या विधेयक या इसके कोई भी प्रावधान संवैधानिक रूप से अमान्य हैं, राजनीतिक प्रकृति का सवाल नहीं है।

जवाब देने से खुद को रोकना चाहिए। द्वारा निर्दिष्ट प्रश्न

राष्ट्रपति हमारी राय के लिए विशुद्ध रूप से कानूनी और संवैधानिक मुद्दों को उठाते हैं जो निर्णय लेने का हमारा अधिकार और कार्य है।

अंतिम प्रस्तुति जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, 7 वां, यह है कि

सलाहकार अधिकारिता के प्रयोग के परिणामों पर विचार करते हुए, हमें समीचीनता और औचित्य के हित में, संदर्भ का उत्तर देने से इनकार कर देना चाहिए। एस्टेट ड्यूटी बिल (1) में जफरुल्ला खान, जे. की असहमतिपूर्ण राय में संदर्भ क्षेत्राधिकार की आलोचना शामिल है जैसा कि संभवतः कल्पना की जा सकती है। विद्वान न्यायाधीश ने सलाहकार अधिकार क्षेत्र के इतिहास, विभिन्न देशों के कानूनों का उल्लेख किया है जो सलाहकार अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हैं, सलाहकार अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए उन देशों की अदालतों का दृष्टिकोण,

(1) [1944] एफ. सी. आर. 317,322।

आरई: विशेष अदालतों का बिल

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

प्रो. जैसे प्रख्यात लेखक। फेलिक्स फ्रैंकफर्टर (जो बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने) और प्रो. कार्लटन केम्प एलन, और प्रिंसीपल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के विभिन्न निर्णयों के लिए।

संक्षेप में, सलाहकार अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के खिलाफ की जा सकने वाली हर संभावित आलोचना को जे. जफरुल्ला खान ने अपनी असहमति वाली राय में देखा और किया है। लेकिन, ग्रंथों और अधिकारियों का उल्लेख करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि ब्रिटिश संसद के समक्ष जो कुछ भी था, उसके बावजूद, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में धारा 233 को शामिल करना बुद्धिमानी थी। अंततः, विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रस्ताव को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो कठिनाइयों को जन्म नहीं देता है, तो अदालत को उस पर निर्णय देना संभव हो सकता है और कहा कि इस संबंध में जो एक सावधानी बरती जा सकती है, वह विधेयक का एक मसौदा संदर्भ के साथ संलग्न करना था जिसे विधायिका के समक्ष रखने का प्रस्ताव किया गया था। चूंकि गवर्नर-जनरल ने जिस विधेयक पर संघीय न्यायालय को निर्देश दिया था, वह एक वित्तीय उपाय था, इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने सोचा कि निर्देश के साथ विधेयक की एक प्रति संलग्न करना अपरिहार्य था और विधेयक के अभाव में, निर्देश का उत्तर देना संभव नहीं था। विद्वान न्यायाधीश जिस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे, वह यह था कि न्यायालय को उपलब्ध कराई गई सामग्री की स्थिति में, न्यायालय को निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता था।

हमने अपनी चर्चा के दौरान बताया है कि

प्रारंभिक आपत्ति के विभिन्न पहलू यह हैं कि चूंकि राष्ट्रपति द्वारा हमारी राय के लिए संदर्भित प्रश्न विशुद्ध रूप से संवैधानिक मुद्दा उठाता है और चूंकि हमारे द्वारा उल्लिखित दो बिंदुओं पर विचार को सीमित करना संभव है, इसलिए संदर्भ का उत्तर देना न तो कठिन है और न ही अनुचित है। एस्टेट शुल्क विधेयक (1) में न्यायमूर्ति जफरुल्ला खान द्वारा बताई गई कठिनाई को हमें विशेष न्यायालय विधेयक की एक प्रति प्रदान करके इस संदर्भ में हटा दिया गया है जो संदर्भ के साथ संलग्न है। तब इसका कोई जवाब नहीं है कि यह विधेयक अंततः विधायिका से उस आकार में उभर सकता है जो हमारे द्वारा विचार किए गए आकार से बहुत अलग है। जैसा कि न्यायाधीश जफरुल्ला खान, (पृष्ठ 343) ने ऐसे मामले में कहा, अदालत की राय को हमेशा उसके समक्ष रखे गए प्रस्ताव के संदर्भ में पढ़ा जाएगा और इसके उस रूप के संदर्भ में पढ़ने का कोई खतरा नहीं होगा जो कानून अंततः लेता है। हम केवल इतना ही जोड़ेंगे कि संविधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद 143 को लागू करना उचित समझा है, इसलिए यह हमारे लिए नहीं है कि हम इस

आधार पर संदर्भ का जवाब देने से इनकार करें कि आमतौर पर सलाहकार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना अनुचित है। से संबंधित तर्क

सलाहकार क्षेत्राधिकार की अयोग्यता के बारे में संविधान के प्रतिष्ठित प्राचीन ग्रंथों को पता था और उनके द्वारा विचार और अस्वीकार किया गया माना जाना चाहिए। एक संदर्भ में उत्तर देने में कठिनाई

(1) [1944] एफ. सी. आर. 317,322।

[1979] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

512

प्रश्नों के दोषपूर्ण ढांचे के कारण दिए गए मामले में, डेटा की अपर्याप्तता या इस तरह की कोई अन्य बात है जो, जैसा कि हमने संकेत दिया है, इस संदर्भ में कोई दुर्गम कठिनाई प्रस्तुत नहीं करती है।

हम अमेरिकी फैसलों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

बेकर वी। कैर (1) और पॉवेल बनाम। मैककॉर्मेक () जिन्हें इस तर्क के समर्थन में उद्धृत किया गया था कि न्यायालय को संभावित प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। हम पहले ही यह बताते हुए उस विवाद का निपटारा कर चुके हैं कि इस मामले में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भ के बारे में कुछ भी काल्पनिक या अटकलबाजी नहीं है। लेकिन इसके अलावा, तीन मुख्य विचारों के कारण अमेरिकी निर्णयों का कोई उपयोग नहीं है: अमेरिकी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत राष्ट्रपति अपनी राय प्राप्त करने के लिए अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दे सकते हैं। दूसरा, अमेरिकी संविधान के तहत शक्तियों का एक कठोर पृथक्करण है; और तीसरा, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद III, धारा 2 (1) में यह प्रावधान है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्ति, जो उस अनुच्छेद की धारा 1 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, सभी "मामलों" और "उन विवादों तक विस्तारित होगी जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक पक्ष होगा; एक राज्य और दूसरे राज्य के नागरिकों के बीच दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों के लिए। विभिन्न राज्यों के नागरिकों और किसी राज्य या उसके नागरिकों और विदेशी राज्यों, नागरिकों या प्रजा के बीच। सलाहकार अधिकार क्षेत्र के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में जहां कोई तथाकथित संपत्ति नहीं है, पक्ष और पक्ष के बीच न तो कोई "मामला" है और न ही

कोई "विवाद" है। यही कारण है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार रखा है कि "यह नियम कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक विवादास्पद मामले के गुण-दोष पर विचार करने के लिए देर से अधिकार क्षेत्र का अभाव है, संवैधानिक आदेश की एक शाखा है कि न्यायिक शक्ति केवल मामलों या विवादों तक फैली हुई है; एक मामला तब विवादास्पद होता है जब प्रस्तुत किए गए मुद्दे अब जीवित नहीं होते हैं या पार्टियों में कानूनी रूप से संज्ञानात्मक रुचि की कमी होती है।

परिणाम "। (3)।

यह रखरखाव के लिए प्रारंभिक आपत्ति का निपटान करता है

संदर्भ से। ऊपर बताए गए कारणों से, हम उस आपत्ति को खारिज करते हैं और संदर्भ का जवाब देने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपनी राय को पहले उल्लिखित दो बिंदुओं तक सीमित करते हैं।

जिन दो प्रमुख प्रश्नों पर हम विचार करने का प्रस्ताव करते हैं, उनमें से

इस संदर्भ में, पहला विधेयक के कुछ प्रावधानों को अधिनियमित करने के लिए संसद की विधायी क्षमता से संबंधित है। विधायी क्षमता पर मुख्य तर्क श्री शिव शंकर द्वारा दिया गया था।

(1) 7 एल. एड., 2 डी, 663।

(2) 23 एल. एड., 2 डी, 491।

(3) 23 एल. एड., 2 डी, 491,493।

आरई: विशेष अदालतों का बिल

513

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से। चूंकि उस प्रश्न पर दूसरे वकील की दलीलें केवल उस तर्क के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं, इसलिए यह मुख्य तर्क को निर्धारित करने और उससे निपटने के लिए पर्याप्त होगा।

निहित मामलों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति पर हमला

विधेयक में तीन मुद्दे उठाए गए हैं: (1) क्या संसद द्वारा अधिनियमित विशेष न्यायालयों के निर्माण के लिए प्रावधान करने के लिए विधायी अधिकार है

विधेयक का खंड 2? (2) संसद के पास विधायी क्षमता है

उच्चतम न्यायालय को निर्णयों से अपीलीय शक्तियाँ प्रदान करना और विधेयक के खंड 10 (1) में दिए गए विशेष न्यायालयों के आदेश? और

(3) क्या यह संसद को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए सक्षम है

उच्चतम न्यायालय घोषणा की तारीख को किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों और संशोधनों पर विचार करेगा और निर्णय लेगा, जैसा कि विधेयक के खंड 6 में प्रावधान किया गया है?

संक्षेप में पुनर्कथन करने के लिए, विधेयक के खंड 2 में प्रावधान है कि केंद्रीय

सरकार अधिसूचना द्वारा पर्याप्त संख्या में न्यायालयों का निर्माण करेगी जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जाएगा। विधेयक के खंड 10 (1) में प्रावधान है कि

दंड प्रक्रिया संहिता में निहित किसी भी बात को स्वीकार करते हुए,

1973 एक अपील के किसी भी निर्णय या आदेश से अधिकार के रूप में निहित होगा

तथ्य और विधि दोनों पर सर्वोच्च न्यायालय का विशेष न्यायालय। विधेयक के खंड 6 द्वारा, यदि किसी के संबंध में घोषणा की तारीख को

अपराध, किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण

ऐसे अपराध के संबंध में अभियोजन स्वयं किसी भी न्यायालय में लंबित है।

अपील या पुनरीक्षण, उसी को निपटान के लिए स्थानांतरित किया जाएगा

उच्चतम न्यायालय,

श्री शिव शंकर का तर्क इस प्रकार है:

(क) अनुच्छेद 124 से 147 जो अध्याय 4 में आते हैं,

संविधान का भाग V, जिसे "द यूनिन जूडी" कहा जाता है

साथी में वर्ग की एक विस्तृत गणना होती है।

जिन मामलों पर उच्चतम न्यायालय का अधिकार है या

अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया जा सकता है। लेख 131 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्रदान करता है कार्यवाही, अनुच्छेद 135 इसकी अधिकारिता को बचाता है और शक्तियाँ, जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, किसी भी मामले के संबंध में जिसके प्रावधान अनुच्छेद 133 और 134 लागू नहीं होते हैं यदि अधिकारिता और उस मामले के संबंध में शक्तियों का उपयोग किया जा सकता था शुरुआत से तुरंत पहले संघीय न्यायालय किसी भी मौजूदा कानून के तहत संविधान का प्रावधान, अनुच्छेद 136 इसे अपने विवेकाधिकार में, [1979] 2s प्रदान करने का अधिकार देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी भी कारण या मामले में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति। सशस्त्र बलों से संबंधित किसी कानून द्वारा या उसके तहत गठित न्यायालय या न्यायाधिकरण के अलावा, अनुच्छेद 137 उसे अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 139 ए उसे कुछ परिस्थितियों में अपने निर्णय के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को वापस लेने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 142 (2) उसे अन्य बातों के साथ-साथ, अपने किसी भी प्रलोभन की जांच या सजा के संबंध में शक्ति प्रदान करता है और अंत में, अनुच्छेद 143 उसमें उल्लिखित मामलों में उसे सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, चाहे

अपीलीय या किसी अन्य प्रकार के मामले का विस्तार इन अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों में नहीं किया जा सकता है। इसलिए विधेयक का खंड 10, जो विशेष न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों से उच्चतम न्यायालय को अपीलीय शक्ति प्रदान करता है, असंवैधानिक है। अध्याय 4, भाग 5, संसद को विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को उस अध्याय के अन्य प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त अधिकारिता के

अलावा और अधिक अधिकारिता प्रदान करने के उद्देश्य से कानून पारित करने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 133 (3) में प्रावधान है कि अनुच्छेद में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश (दीवानी पक्ष में) के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी, जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं करती है। इस प्रकार संसद को एक पारित करने की शक्ति दी गई है कानून यह प्रावधान करता है कि दीवानी कार्यवाही में, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के फैसले, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। अनुच्छेद 134 (2) संसद को उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा से संबंधित अपीलों पर विचार करने और उनकी सुनवाई करने के लिए अनुच्छेद 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की तुलना में किसी भी "अतिरिक्त शक्तियों" को कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन करने का अधिकार देता है जो ऐसी कानून में निर्दिष्ट की जा सकती हैं। अनुच्छेद 138 (1) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय को इस तरह का और अधिकार क्षेत्र होगा।

और संघ सूची के किसी भी मामले के संबंध में शक्तियाँ जो संसद कानून द्वारा प्रदान करे।

आरई द्वारा: विशेष अदालतों का बिल

5

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

अनुच्छेद 138 (2), उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले के संबंध में ऐसी आगे की अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान करती है तो भारत सरकार और किसी भी राज्य की सरकार विशेष समझौते द्वारा प्रदान कर सकती है।

अनुच्छेद 139 संसद को कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 (2) में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 140 के तहत, संसद उच्चतम न्यायालय को ऐसी पूरक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए एक कानून बना सकती है जो संविधान के किसी भी प्रावधान से असंगत न हों, जो न्यायालय को संविधान द्वारा या उसके तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का

अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो।

ये प्रावधान उन मामलों और परिस्थितियों के संपूर्ण हैं जिनमें अतिरिक्त शक्तियाँ या न्यायपालिकाएँ हैं। शब्दकोष उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जा सकता है, संसद के पास विशेष न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय को अपील की शक्तियाँ प्रदान करने वाली कानून पारित करने की कोई क्षमता नहीं है, जो एक ऐसा मामला है जिसकी न तो परिकल्पना की गई है और न ही अध्याय IV के उपरोक्त प्रावधानों में से किसी के अंतर्गत आता है। इसलिए विधेयक का खंड 10 संसद की विधायी शक्ति से परे है।

यद्यपि संसद के पास सूची I में उल्लिखित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है, और विशेष रूप से, कि

अनुच्छेद 245 (1) में दी गई शक्ति संविधान के प्रावधानों के अधीन है। तदनुसार, पुरुषों के मामलों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति

उदाहरण के लिए, सूची I (संविधान, संगठन, अधिकारिता और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ) की प्रविष्टि 77 में, प्रविष्टि 95 (सूची I में किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियाँ), और प्रविष्टि 97 (कोई अन्य मामला जो सूची II या सूची III में सूचीबद्ध नहीं है) का प्रयोग संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ लगातार और उनके अधीन किया जाना चाहिए। सूची I और III में उल्लिखित मामलों पर कानून बनाने की अपनी शक्ति के आधार पर संसद द्वारा बनाया गया कानून वैध नहीं होगा, यदि यह किसी अन्य 516 का उल्लंघन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1979] 2 एस सी आर।

संविधान का प्रावधान, प्रावधान के अलावा मौलिक अधिकारों पर भाग III के सिद्धांत।

(घ) में निहित प्रावधानों की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए

अनुच्छेद 136 (1), इसके लिए खुला हो सकता है -

द.

संसद यह उपबंध करे कि उच्चतम न्यायालय,
अपने विवेकाधिकार में, किसी से भी अपील करने के लिए विशेष अनुमति

दे।

विशेष न्यायालय का निर्णय या आदेश। लेकिन तब से,

अनुच्छेद जो अध्याय IV, भाग V में आते हैं
संविधान, संसद किसी को नहीं दे सकती

व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार

विशेष न्यायालयों के निर्णयों या आदेशों से।

(ई) तर्क की समानता से, में निहित प्रावधान

लंबित अपीलों के हस्तांतरण के लिए विधेयक का खंड 6

संविधान के अध्याय IV, भाग V के प्रावधान।

संवैधानिक योजना में पूरी तरह से निहित है

अध्याय IV पुनरीक्षण के अभ्यास पर विचार नहीं करता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय अधिकारिता और वहाँ

खंड 6 द्वारा उस अधिकारिता को प्रदान करने से पहले

यह संसद की क्षमता से परे है। यदि संशोधन किया जाता है
उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने पर विचार किया जाता है

सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार क्षेत्र में आने वाले
विधेयक के अनुच्छेद 136 (1), खंड 6 के तहत न्यायालय

उस अनुच्छेद के प्रावधानों के खिलाफ अपराध क्योंकि

अधिकारिता के प्रयोग के लिए पूर्व-आवश्यकता

उस अनुच्छेद के तहत विशेष अवकाश का अनुदान है

सर्वोच्च न्यायालय।

विद्वान महान्यायवादी के जवाब का मुख्य मुद्दा और

विद्वान महान्यायवादी ने इन दलीलों के उत्तर में कहा है कि संविधान के अध्याय IV, भाग V के प्रावधान नहीं हैं

जिन विषयों में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता है या जिसमें संसद, कानून द्वारा, उसे अधिकारिता प्रदान कर सकती है, उन मामलों के वर्ग का संपूर्ण विवरण। यह तर्क दिया जाता है कि अध्याय IV के प्रावधान, सातवीं अनुसूची की सूची I और III के भीतर आने वाले मामलों पर कानून बनाने के लिए संसद को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति पर हावी नहीं हो सकते हैं। अर्थात्, संविधान के भाग 11 के अध्याय 1, जो 'विधायी शक्तियों के वितरण' से संबंधित है, को अपना पूर्ण प्रभाव रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और अध्याय 4, भाग 5 में निहित किसी भी चीज़ को उस शक्ति से अपमानजनक नहीं माना जा सकता है। उस अध्याय के प्रावधानों से कोई निहितार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते हैं ताकि विधायी क्षमता को निरस्त किया जा सके।

विशेष अदालतों का बिल

517

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

संघ के अंतर्गत आने वाले मामलों पर विधान बनाने के लिए संसद। और समवर्ती सूचियाँ। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से बढ़ाने की संसद की शक्ति निर्विवाद है, जब तक कि उस अधिकार क्षेत्र का निर्माण या प्रदान करने वाला कानून सूची I या सूची III में उल्लिखित मामलों के संबंध में है। विद्वान वकील अनुच्छेद 138 (1) के प्रावधानों पर भरोसा करते हैं और

के निर्माण के लिए संसद की क्षमता का समर्थन करने के रूप में विशेष न्यायालय।

प्रदान करने के लिए संसद की विधायी क्षमता को चुनौती

विशेष न्यायालयों के निर्माण के लिए सारहीन है। प्रविष्टि 11 ए समवर्ती सूची का संबंध "न्याय प्रशासन; संविधान" से है।

और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का संगठन अदालत "। अनुच्छेद 246 (2) के आधार पर संसद के पास स्पष्ट रूप से शक्ति है

संविधान और संगठन के संबंध में कानून बनाना, अर्थात् कहने के लिए, विशेष न्यायालयों का निर्माण और स्थापना। का खंड 2 इसलिए विधेयक संसद के अधिनियमित करने के अधिकार के भीतर है।

सूची III की प्रविष्टि 11 ए द्वारा कवर किए गए कानून का क्षेत्र मूल था। पूरी तरह से सूची II की प्रविष्टि 3 का एक हिस्सा। 42 वीं की धारा 57 (बी) (iii) द्वारा सुधार अधिनियम, 1976 जो 3 जनवरी, 1977 को लागू हुआ भाग को प्रविष्टि 3, सूची II से और धारा 57 के खंड (सी) द्वारा हटा दिया गया था, इसे सूची III में आइटम 11 ए के रूप में डाला गया था। यह स्थानांतरण इस तर्क को जन्म दिया है कि द्वारा प्रस्तुत विशेष संशोधन धारा 57 (बी) (iii) और (सी) अमान्य है क्योंकि यह एक बुनियादी विशेषता को नष्ट कर देती है। मूल रूप से अधिनियमित संविधान, अर्थात् संघवाद। हम हैं।

यह समझने में असमर्थ कि कैसे समवर्ती शक्ति प्रदान की गई संसद, राज्यों की अनन्य शक्ति के स्थान पर, कुछ न्यायालयों के संविधान और संगठन से रियासतों पर प्रभाव पड़ता है। जिस रूप में हमारे संविधान ने संघवाद को स्वीकार किया है और इसे हटा दिया। लेकिन तर्क के लिए यह मानते हुए कि निहित राज्यों में ऐसी शक्ति का होना संविधान की एक बुनियादी विशेषता थी, हमें संविधान को वैसा ही लेना होगा जैसा हम इसे इस उद्देश्य के लिए पाते हैं। संदर्भ। द्वारा संदर्भित प्रश्न का सबसे स्पष्ट निहितार्थ राष्ट्रपति यह है कि क्या, मौजूदा संवैधानिक के आधार पर प्रावधान, विधेयक या इसके कोई भी प्रावधान, यदि अधिनियमित किए जाते हैं, तो अमान्य होंगे।

इसलिए हम इस कार्यवाही में कोई तर्क नहीं दे सकते हैं कि -

संविधान के संशोधन द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक प्रावधान

यह अमान्य है।

यह देखने के बाद कि संसद के पास विधायी क्षमता है

विशेष न्यायालयों का निर्माण करें, जो तर्क की अगली शाखा है विचार
के लिए यह है कि क्या यह संसद को [1979] 2 एस. सी. आर. प्रदान करने के लिए सक्षम है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

518

उच्चतम न्यायालय पर अपीलीय अधिकारिता ताकि सक्षम या आवश्यक हो

यह विशेष न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों की अपीलों को सुनने के लिए है। द.

एक अन्य रूप में तर्क यह है कि यह सक्षम नहीं है

संसद एक वादी को अपील दायर करने का अधिकार प्रदान करेगी

विशेष न्यायालय के निर्णय या आदेश से उच्चतम न्यायालय।

यह तर्क दिया जाता है कि अपील के लिए प्रावधान उच्चतम स्तर पर हो सकता है

विशेष अवकाश देने की पूर्व शर्त के अधीन किया गया था

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए

ट्यूशन।

इस तर्क का आधार ही गलत है। तर्क

यह इस दलील पर आधारित है कि अध्याय IV के प्रावधान। इसका भाग V

संविधान संपूर्ण है और इसलिए, अब और न ही इससे बड़ा है।

परंतु की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारिता प्रदान की जा सकती है
उस अध्याय की अनुज्ञाएँ प्राधिकृत या वारंट करती हैं। स्वीकार करना असंभव है

इस तर्क के लिए कि इस तरह के कोई भी निहितार्थ उत्पन्न हो सकते हैं अध्याय IV के प्रावधान। यदि विवाद स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका परिणाम होगा

संविधान के अनुच्छेद 246 (1) और (2) द्वारा संसद को प्रदत्त विधायी शक्ति का वस्तुतः निरसन। इस तरह की

ऐसा निर्माण जो अन्य महत्वपूर्ण लाभों को भ्रामक या निरर्थक बनाता है संविधान के दृष्टिकोण से बचा जाना चाहिए, विशेष रूप से जब यह चाहता है

इसका औचित्य अध्याय IV में निहित लेखों के फासिकुलस से उत्पन्न होने वाले मात्र निहितार्थ से है। संविधान इस बात का समर्थन नहीं करता है कि अनुच्छेद 246 (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद और

(2) , संसद के पास विस्तार करने की कोई शक्ति या क्षमता नहीं होगी।

उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, मात्रात्मक या गुणात्मक रूप से, जिसके अनुसार और जिस हद तक इसकी अनुमति है

अध्याय IV भाग V के किसी भी प्रावधान के तहत ऐसा करना।

इसलिए उस अध्याय के प्रावधानों को संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ सामंजस्य और संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए, न कि

उसका अवमूल्यन।

श्री शिव शंकर या इस पहलू पर एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा गया था।

मामले से। उन्होंने पूछा: यदि संसद का गठन किया जाना है, तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति

इसमें उल्लिखित, अनुच्छेद 133 (3), 134 (2), 138 (1), 138 (2), 139 और अनुच्छेद 140 जैसे प्रावधानों के पीछे क्या उद्देश्य और उद्देश्य था? ये अनुच्छेद संसद को क्या करने का अधिकार देते हैं

संसद द्वारा अनुच्छेद 246 (1) और (2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग समान क्षमता और वैधता के साथ किया गया है। इसका कारण, विद्वान वकील के अनुसार, के निर्माताओं

संविधान ने सोचा कि संविधान में विशेष प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक है जो संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून पारित करने के लिए सशक्त या सक्षम बनाता है।

विशेष अदालतों का बिल

519

(चंद्रचूड़, सी. जे.)

उन विशेष प्रावधानों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित विशिष्ट मामलों और परिस्थितियों के लिए। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधान जिनके तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किया जा सकता है, उन्हें उन सामान्य प्रावधानों पर हावी होना चाहिए जिनके तहत संसद मामलों के संबंध में कानून पारित कर सकती है।

यह सातवीं अनुसूची की सूची I और III में सूचीबद्ध है।

हम इस तर्क को स्वीकार करना असंभव मानते हैं कि

विशिष्ट मामलों पर कानून पारित करने की शक्ति संसद के अधिकार को सीमित करती है।

केवल उन मामलों के लिए कानून पारित करने की शक्ति और इसकी शक्ति छीन लेती है

उन मामलों पर कानून पारित करना जो अन्यथा इसके विधायी निकाय के भीतर हैं

पेटेंस। अनुच्छेद 246 (1) और (2) की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है।

और बिना किसी संदेह या कठिनाई के स्वीकार करता है। इसलिए यह दिया जाना चाहिए कि

उचित प्रभाव। सबसे पहले, इसलिए, कोई निहितार्थ नहीं पढ़ा जा सकता है

संविधान के अध्याय IV, भाग V के प्रावधानों में जो

उनकी भाषा समर्थनीय नहीं है और दूसरी बात यह है कि प्रयास किया जाना चाहिए

संविधान के विभिन्न प्रावधानों को सुसंगत बनाने के लिए और उपचार करने के लिए नहीं इसका कोई भी हिस्सा अनावश्यक या अनावश्यक है। कुछ मात्रा में पुनरावृत्ति

या ओवरलैपिंग हमारे जैसे संविधान में अपरिहार्य है जो-इसके विपरीत

अमेरिकी संविधान, विस्तृत रूप से तैयार किया गया है और मिनट में चलता है

विवरण। इसलिए, इसका और भी बड़ा कारण है, जबकि इसका अर्थ

हमारे संविधान में, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि शक्तियां प्रदान की जाएं इसके विभिन्न प्रावधानों द्वारा उनके पूर्ण खेल और किसी भी एक की अनुमति है प्रावधान, निर्माण द्वारा, अस्तित्व को रद्द करने के रूप में नहीं माना जाता है और दूसरे का प्रभाव। वास्तव में, यदि यह सही है कि विशिष्ट शक्तियाँ अध्याय IV, भाग V में कुछ अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त संपूर्ण हैं

जिन मामलों में संसद सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारिता प्रदान कर सकती है न्यायालय, यह पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक था

अनुच्छेद 138 (1) कि उच्चतम न्यायालय के पास ऐसा और न्यायशास्त्र होगा संघ सूची के किसी भी मामले के संबंध में राज्य और शक्तियाँ जैसा कि संसद विधि द्वारा प्रदान करे। इस लेख पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है यह दर्शाता है कि यदि इसके बिना भी यह संसद के लिए सक्षम था अध्याय 246 (1) और (2) के तहत अपनी शक्ति के आधार पर अनुच्छेद

उस लेख को लागू करके प्राप्त किया। इस तर्क का जवाब दो है। अध्याय ऊपर बताए अनुसार मोड़ें। इसके अलावा, अनुच्छेद 138 (1) का उद्देश्य है -

अधिकारिता प्रदान करने के लिए संसद की शक्ति को और बढ़ाएँ

उच्चतम न्यायालय ने पहले से ही विशेष रूप से अध्याय में निपटाए गए मामलों में भी

टैर IV, भाग V. उदाहरण के लिए अनुच्छेद 136 (2) में कुछ भी नहीं है खंड (1) किसी निर्णय, निर्धारण, दंडादेश या

द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किया गया आदेश सशस्त्र बलों से संबंधित कोई भी कानून। लेकिन अनुच्छेद 138 (1) के आधार पर

सूची I की प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 93 के साथ पढ़ा गया, यह [1979] 2 एस. सी. आर. के लिए सक्षम हो सकता है।

520

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लगी बेड़ियों को हटाने के लिए

विशेष अनुमति प्रदान करें और उस अधिकार क्षेत्र का विस्तार किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए निर्णय, बचाव, सजा या आदेश तक करें।

सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी कानून के तहत एआर द्वारा गठित। इसी तरह, अनुच्छेद 138 (1) के तहत कार्य करते हुए, संसद अनुच्छेद 131 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त मूल अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है।

यह मानते हुए भी कि अनुच्छेद 138 (1) का इरादा नहीं हो सकता है

उपरोक्त किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इसका उद्देश्य कम से कम हो सकता है

संसद को संघ सूची के किसी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी विशेष प्रकार की अधिकारिता और शक्तियां प्रदान करने का अधिकार। यदि अध्याय IV, भाग V में निहित प्रावधानों की संपूर्णता के संबंध में तर्क सही था, तो तर्क की समानता से, यह संसद के लिए सक्षम होगा कि वह लिसा I (चुनाव) की प्रविष्टि 72 में उल्लिखित मामलों के संबंध में एक कानून पारित करे।

.....के लिए

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय।) , इस तथ्य के कारण कि संविधान का अनुच्छेद 71 संसद को विशेष रूप से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी मामले को कानून द्वारा विनियमित करने का अधिकार देता है, जिसमें वे आधार भी शामिल हैं जिन पर ऐसे चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। अनुच्छेद 71, वास्तव में कई अन्य अनुच्छेदों की तरह, दर्शाता है कि हमारे संविधान में अतिव्यापी प्रावधान हैं। इसलिए, संसद को सूची I और III में उल्लिखित मामलों के संबंध में कानून पारित करने की क्षमता है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे कानूनों द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार इस तरह से किया जाता है जिस पर विचार नहीं किया जाता है।

अध्याय IV, भाग V के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार, उदाहरण के लिए, निवारक निरोध सूची III में प्रविष्टि 3 का विषय है। जैसा कि श्री राम जेठमलानी ने तर्क दिया है, संसद के लिए यह सक्षम है कि वह अनुच्छेद 246 (2) के तहत अपनी शक्तियों के आधार पर उस विषय पर देर से कानून बनाए और सूची I की प्रविष्टि 77 के साथ पठित अनुच्छेद 246 (1) के तहत अपनी

शक्तियों के आधार पर यह भी प्रावधान करे कि निवारक निरोध के कानून के तहत पारित निरोध के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

अब यह देखना बाकी है कि क्या सातवीं अनुसूची की सूची I या सूची III में कोई प्रविष्टि है जिसमें विषय वस्तु शामिल है।

उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता ताकि संसद को उस मामले के संबंध में कानून पारित करने के लिए मजबूर किया जा सके। यह सवाल शायद ही कोई कठिनाई प्रस्तुत करता है। सूची I की प्रविष्टि 77 इस प्रकार है:

उच्चतम न्यायालय का संविधान, संगठन, अधिकारिता और शक्तियाँ (ऐसे न्यायालय की अवमानना सहित), और उसमें ली गई फीस; उच्चतम न्यायालय के समक्ष वकालत करने के हकदार व्यक्ति।

आरई: विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

521

एक बार प्रावधानों की संपूर्णता के बारे में तर्क

भाग 5 के अध्याय 4 को अस्वीकार कर दिया गया है, संसद को स्पष्ट रूप से विधेयक के खंड 10 (1) द्वारा यह प्रावधान करने की आवश्यकता है कि इसके बावजूद

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित कुछ भी अपील किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के अधिकार के रूप में निहित होगी -

तथ्य और कानून दोनों पर सर्वोच्च न्यायालय। एक कानून जो अड्डी प्रदान करता है

प्रमाणतः उसकी "अधिकारिता और शक्तियों" के संबंध में एक कानून अदालत,

सूची I की प्रविष्टि 77 प्रस्तुत करती है, जैसा कि विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है

सामान्य तौर पर, सूची I की प्रविष्टि 95 के साथ एक आश्चर्यजनक विरोधाभास, सूची की प्रविष्टि 65

सूची III का द्वितीय और प्रविष्टि 46। अंतिम रूप से उल्लिखित तीन का संचालन

प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से एक योग्यता खंड द्वारा सीमित हैं, जो कानून के क्षेत्र को विशेष सूची में उल्लिखित मामलों तक सीमित करता है जिसमें

प्रविष्टि दिखाई देती है। सूची I की प्रविष्टि 95 अधिकार क्षेत्र से संबंधित है और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की शक्तियाँ

इस सूची के मामलों के बारे में "। सूची-II की प्रविष्टि 65 अधिकारिता से संबंधित है।

और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की शक्तियाँ,

इस सूची में से कोई भी मामला "। सूची III की प्रविष्टि 46 न्यायशास्त्र से संबंधित है।

उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की बोलचाल और शक्तियाँ

इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में "। एक संदर्भ भी हो सकता है

श्री राम जेटमलानी ने अनुच्छेद 323 बी पारित किया

हमारा ध्यान, जो प्रदान करता है कि उपयुक्त विधानमंडल, द्वारा

कानून, किसी भी विवाद के न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय या परीक्षण के लिए प्रावधान करता है, सभी या किसी भी विशेष मामले के संबंध में शिकायतें या अपराध

खंड (2) में अभिनिर्धारित जिसके संबंध में ऐसे विधानमंडल को शक्ति है

कानून बनाने के लिए। सूची I की प्रविष्टि 77 अपनी विशिष्टता में विशिष्ट है।

विधायी सूचियों में संज्ञानात्मक प्रविष्टियों के बीच इसकी व्यापक और गैर-कानूनी रूप से योग्य भाषा। इसके अंतर्गत आने वाला कानून का क्षेत्र नहीं है

योग्यता द्वारा सीमित "। किसी भी मामले में

इस सूची में ", यानी, सूची 5। यह विरोधाभास इस बात पर जोर देता है कि शक्ति

में निहित किसी विषय के संबंध में विधान बनाने के लिए संसद का

प्रविष्टि 77, जो, तत्काल मामले में, "अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ हैं

उच्चतम न्यायालय का प्रयोग किसी भी संदर्भ के बिना किया जा सकता है

सूची I या किसी अन्य सूची में निहित मामले। नहीं हो सकता है।

औचित्य, हमारे द्वारा पहले से ही निपटाए गए तर्क पर लौटने के लिए, क्योंकि के संबंध में संसद की शक्ति के विस्तार को कम करना अध्याय में किसी बात के कारण प्रविष्टि 77 की विषय वस्तु IV, भाग V।

समस्या एक जुड़वां किस्म की है और इसके दो परस्पर जुड़े पहलू हैं। अगर संसद में एक नई संस्था स्थापित करने की शक्ति है। अदालत, निस्संदेह अनुच्छेद 246 (2) के आधार पर जिसे सूची III की प्रविष्टि 11 ए के साथ पढ़ा जाता है,

15

—9 78 एससीआई/78 [1979] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

522

यह अजीब बात होगी कि संसद के पास उस न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने का पूरा अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी कानून या संविधान में संभावित रूप से खामियां और खामियां मौजूद हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि हमने ऊपर बताया है, हमारे संविधान ने न केवल नए न्यायालय बनाने की शक्ति प्रदान की है, बल्कि संसद को यह प्रदान करने की शक्ति प्रदान करने का ध्यान रखा है कि ऐसे न्यायालय के निर्णय से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। एक नया न्यायालय स्थापित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद आवश्यकता के कारणों से एक ऐसा न्यायालय बनाना आवश्यक मान सकती है जो मौजूदा न्यायालयों के पदानुक्रम में एक स्थापित पैटर्न के अनुरूप न हो। नवनिर्मित न्यायालय का दर्जा उसके गठन या उसके समक्ष आने वाले मामलों की प्रकृति के कारण ऐसा हो सकता है कि उसके निर्णयों और आदेशों से केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही न्यायसंगत रूप से अपील की जा सके। यह प्रविष्टि 77, सूची I द्वारा कवर किए गए विधायी क्षेत्र के आयाम के औचित्य की व्याख्या करता है।

यह एक तार्किक परिणाम के रूप में होना चाहिए कि संसद के पास विधेयक के खंड 6 द्वारा यह प्रावधान करने की विधायी क्षमता भी है कि यदि किसी अपराध के संबंध में घोषणा की तारीख

पर, ऐसे अपराध के संबंध में अभियोजन में किसी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन किसी भी अपील या संशोधन के न्यायालय में लंबित है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित हो जाएगा। खंड 6 में निहित प्रावधान पूरी तरह से सूची I की प्रविष्टि 77 द्वारा चित्रित विधान के क्षेत्र में आता है। खंड 6 का विषय सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां हैं। सूची III की प्रविष्टि 2, "आपराधिक प्रक्रिया, जिसमें आपराधिक संहिता में शामिल सभी मामले शामिल हैं। इस संविधान के प्रारंभ की प्रक्रिया भी खंड 6 का ध्यान रखेगी। वास्तव में, वह प्रविष्टि, जो इसे अधिकतम संभव अर्थ देती है, खंड 10 (1) के प्रावधान का समर्थन भी कर सकती है।

हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि संसद के पास विधेयक के खंड 6 और 10 (1) को अधिनियमित करने के लिए विधायी अधिकार है, विद्वान सॉलिसिटर जनरल के इस तर्क पर विचार करना अनावश्यक है कि बाकी सब कुछ विफल होने पर, संसद को सूची I की प्रविष्टि 97 के साथ पठित अनुच्छेद 248 (1) के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों पर कानून बनाने की क्षमता होगी।

सूची. संक्षेप में, हमारी राय है कि विधेयक के खंड 2,6 और 10 (1) संसद की विधायी क्षमता के भीतर हैं। कि

कहने के लिए, संसद के पास आर्ड के निर्माण के लिए प्रावधान करने की क्षमता है:

विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

523

विधेयक के खंड 2 के रूप में विशेष न्यायालयों का उपबंध है कि वे उच्चतम न्यायालय को विधेयक के खंड 6 द्वारा उपबंधित लंबित अपीलों और संशोधनों का निपटारा करने का अधिकार प्रदान करते हैं और जैसा कि खंड 10 (1) द्वारा किया गया है, यह उपबंध करके सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करते हैं कि किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से तथ्य और विधि दोनों पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील अधिकार के रूप में निहित होगी।

हालांकि संसद की विधायी क्षमता विशेष बनाने के लिए है

अदालतें, आपराधिक मामलों की सुनवाई के तत्काल मामले में, ऊपर दिए गए कारणों से इनकार नहीं किया जा सकता है, इस तर्क के एक हिस्से के लिए विज्ञापन देना आवश्यक है कि, किसी भी स्थिति में, संसद को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त न्यायालयों के पदानुक्रम के बाहर

अदालत बनाने की कोई शक्ति नहीं है। विधायी क्षमता के सवाल पर बहस के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि संविधान

ट्यूशन में न्यायिक प्रणाली की एक पूरी संहिता शामिल है जो शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए प्राथमिकता के क्रम में प्रदान करती है। अनुच्छेद 124

यह उपबंध करता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 232 (1)

कि संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है और

जबकि संविधान के भाग VI के अध्याय VI में अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए प्रावधान किया गया है। चित्र को पूरा करने के लिए, अनुच्छेद 236 (ए) एक "जिला न्यायाधीश" को परिभाषित करता है जिसमें शहर के दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश,

लघु कारण न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश। अंत में, अनुच्छेद 237 राज्यपाल को अध्याय VI के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम को मजिस्ट्रेट के किसी भी वर्ग या वर्गों पर लागू करने का अधिकार देता है। संविधान ने न्यायालयों के पदानुक्रम के लिए पूरी तरह से और प्रचुर मात्रा में प्रावधान किया है, यह आग्रह किया जाता है कि संसद को यह बनाने की अनुमति नहीं है

एक न्यायालय या न्यायालयों का एक वर्ग जो इसके अंतर्गत नहीं आता है या इसके अंतर्गत नहीं आता है।

योजना। इस तर्क का एक महत्वपूर्ण अंग जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि एक ऐसे विचारण न्यायालय का निर्माण जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन नहीं है, न्यायिक स्वतंत्रता की संवैधानिक अवधारणा के लिए हानिकारक है, विशेष रूप से जब विधेयक केंद्र सरकार को खंड 5 द्वारा सशक्त बनाता है।

उस विशेष न्यायालय को निर्दिष्ट करना जिसमें अभियोजन स्थापित किया जाएगा या जिसमें एक लंबित अभियोजन स्थानांतरित किया जाएगा।

हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। पहले में क्या महत्वपूर्ण है

यह पूछताछ करने के लिए है कि क्या संसद के पास विधायी क्षमता [1979] 2 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

524

विशेष न्यायालयों का निर्माण करना। यदि ऐसा है, तो अगला सवाल यह है कि क्या संविधान में कुछ ऐसा है जो उस शक्ति को उसी तरह के एक और न्यायालय की स्थापना और न्यायालयों की संविधान की पदानुक्रमित प्रणाली में प्रदान किए गए पदनाम तक सीमित करता है। हम संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं जो विशेष न्यायालय बनाने की संसद की शक्ति पर ऐसी सीमा लागू करने को उचित ठहराए। वास्तव में, यह तर्क उसी चरित्र को दर्शाता है जो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अध्याय IV, भाग V में पाए जाने या प्रदान किए जाने से बड़ी या अलग शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं। संविधान के निहितार्थ को इतना व्यापक नहीं बनाया जाना चाहिए कि संसद को व्यक्त और सलाह से प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग को नकार दिया जाए। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 11 ए के शब्द जो "उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के न्यायिक प्रशासन; गठन और संगठन" से संबंधित हैं, अपने विस्तार में पर्याप्त रूप से व्यापक हैं ताकि संसद न केवल उसी प्रकार के और पदनाम के न्यायालयों की स्थापना कर सके जैसा कि ऊपर देखे गए प्रावधानों में संदर्भित किया गया है, बल्कि नए या विशेष न्यायालयों का गठन और आयोजन कर सके, जो प्रविष्टि में उल्लिखित सीमा के अधीन हो।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय।

यह सच है कि विधेयक द्वारा बनाए गए विशेष न्यायालयों के पास नहीं होगा

संवैधानिक दर्जा जो उच्च न्यायालयों को ऐसे न्यायालयों के कारण प्राप्त है। संविधान द्वारा परिकल्पित उच्च न्यायालय नहीं हैं। वास्तव में, वहाँ

लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए केवल एक उच्च न्यायालय हो सकता है, हालांकि दो या दो से अधिक

राज्यों या दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के पास हो सकता है

अनुच्छेद के अर्थ में विशेष न्यायालय जिला न्यायालय नहीं हैं। 235 , इसके परिणामस्वरूप उन पर नियंत्रण निहित नहीं होगा

किसी भी उच्च न्यायालय में। लेकिन हम यह स्वीकार नहीं करते हैं कि इन कारणों से विचार करते हुए, विशेष न्यायालयों के निर्माण की गणना नुकसान के लिए की जाती है या न्यायिक स्वतंत्रता के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को नष्ट कर दें। हमारा

इस दृष्टिकोण के कारण तब स्पष्ट हो जाएंगे जब हम अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर विचार करेंगे, लेकिन यह कहने के लिए पर्याप्त होगा।

इस पर

यह कि विधेयक के खंड 10 (1) में किसी विशेष न्यायालय के प्रत्येक निर्णय और आदेश से उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान और किसी मामले को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रावधान (जिसमें विधेयक शामिल नहीं है, लेकिन जिसके बिना, जैसा कि हम दिखाएंगे, विधेयक अमान्य हो जाएगा) विशेष न्यायालयों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं या होंगे। उसके साथ विचार किया जाएगा, क्योंकि हम अपने निर्णय के दौरान इंगित करेंगे कि विशेष न्यायालयों में केवल उच्च न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी। उच्च न्यायालय का एक वर्तमान न्यायाधीश, हालांकि विशेष आरई में नियुक्त किया गया है:

विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

52 5

अदालत, उसके साथ उसकी संवैधानिक स्थिति, अधिकार, विशेषाधिकार ले जाएगी

और दायित्व। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि केवल

स्थल का परिवर्तन उसकी स्वतंत्रता की भावना को प्रभावित करेगा या उसे कार्यपालिका के प्रभाव के लिए खुला रखेगा। संविधान के अनुच्छेद 226 की सौम्य उपस्थिति के बारे में भी कोई अनजान नहीं हो सकता है जिसे उचित मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जा सकता है।

संसद की विधायी क्षमता के समान ही महत्वपूर्ण,

इन प्रावधानों को लागू करना और अधिक सामाजिक महत्व का सवाल यह है कि क्या यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की गारंटी का उल्लंघन करता है। उस लेख में कहा गया है:

राज्य किसी भी व्यक्ति को समानता से वंचित नहीं करेगा

कानून या क्षेत्र के भीतर कानूनों का समान संरक्षण

भारत से।

कई आपत्तियाँ, उदात्त से लेकर इतना उदात्त नहीं, की गई हैं।

अनुच्छेद 14 के संदर्भ में विधेयक के प्रावधानों के विरुद्ध लिया गया। लेकिन, मोटे तौर पर, यह चुनौती विधेयक द्वारा किए गए वर्गीकरण की वैधता और संबंधों की कमी के खिलाफ है।

उस वर्गीकरण के आधार और विधेयक के उद्देश्य के बीच। द. यह आगे तर्क दिया जाता है कि विधेयक परीक्षण के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाता है।

ऐसे अपराध जो गारंटी के मूल सिद्धांत के विरुद्ध हों।

समानता। विधेयक कार्यपालिका को भेदभाव करने के लिए खुला छोड़ता है समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच कुछ को चुनकर और चुनकर

उन पर विशेष न्यायालयों द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है, दूसरों को मुकदमा चलाने के लिए छोड़ दिया गया है

न्यायालयों के नियमित पदानुक्रम द्वारा। द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

विशेष अदालतों के समक्ष सुनवाई के लिए विधेयक कथित रूप से कठिन है

उस प्रक्रिया के साथ तुलना जो आम अदालतें आम तौर पर अपनाती हैं,

इस प्रकार व्यक्तियों के एक वर्ग को निष्पादक द्वारा चुने जाने के लिए छोड़ दिया जाता है

एक बुरी नज़र से, शत्रुतापूर्ण और प्रतिकूल व्यवहार के लिए। द.

यह तर्क दिया जाता है कि विधेयक घोषणा करने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं देता है

धारा 4 (1) के तहत यह तय करने के लिए कि कौन और किन कारणों से होना चाहिए

विशेष न्यायालयों को मुकदमे के लिए भेजा गया और ऐसे दिशा-निर्देश जो इसके अंतर्गत आते
 हैं

बिछाने के लिए बंदरगाह अस्पष्ट और अनिश्चित हैं।

इन तर्कों को विद्वान महान्यायवादी द्वारा पूरा किया जाता है,

विद्वान महान्यायवादी, विभिन्न महाधिवक्ता और श्री

राम जेठमलानी ने यह बताते हुए कि विधेयक किसी भी तरह से नहीं है

वर्ग विधान का एक उदाहरण; कि यह एक वर्गीकरण बनाने के लिए प्रदान करता है
 अपराधों की प्रकृति के संदर्भ में, सार्वजनिक स्थिति

अपराधियों द्वारा कब्जा कर लिया गया और असाधारण अवधि जिसके दौरान

अपराध कथित रूप से किए गए हैं; कि प्रावधान

विधेयक और प्रस्तावना के पाठ पर्याप्त और [1979] 2 एस. सी. आर. प्रदान करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

526

यह तय करने के लिए आवश्यक घोषणा करने के लिए निश्चित मार्गदर्शन कि किसे विशेष
 न्यायालयों में परीक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए; कि, इस संदर्भ में, विधेयक विशेष न्यायालयों
 द्वारा परीक्षण के लिए व्यक्तियों को चुनने और चुनने के लिए सरकार को मनमाना या अप्रमाणित
 शक्ति निहित नहीं करता है; कि विशेष न्यायालयों के समक्ष परीक्षण के लिए विधेयक द्वारा
 निर्धारित प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया से अधिक कठिन होने के बजाय, कुछ महत्वपूर्ण मामलों
 में अभियुक्त के लिए अधिक फायदेमंद है; और चूंकि, किसी भी स्थिति में, विशेष न्यायालयों की
 प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया से अधिक कठिन नहीं है, इसलिए विधेयक के प्रावधानों में
 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला कोई भेदभाव शामिल नहीं है।

कानूनों से संबंधित इस अदालत के फैसलों का एक संक्षिप्त विवरण

विशेष अदालतों के निर्माण के लिए जो प्रावधान किया गया है, वह सही स्थिति की स्पष्ट धारणा और विधेयक के पक्ष और विपक्ष के बिंदुओं की बेहतर सराहना की सुविधा प्रदान करेगा। संघ का लिखित संक्षिप्त विवरण

सरकार में विशेष न्यायालयों का एक संक्षिप्त विवरण है, जिनसे यह प्रतीत होता है कि ऐसे न्यायालयों की स्थापना कई अवसरों पर ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी, विशेष रूप से जिन्हें व्यापक रूप से सुरक्षा कानून कहा जा सकता है जैसे कि रॉलेट अधिनियम, 1919, बंगाल प्रांतीय कानून (संशोधन) अधिनियम, 1925, शोलापुर मार्शल लॉ अध्यादेश 1930, बंगाल अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1930 और 1932, बिहार लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, बॉम्बे सार्वजनिक सुरक्षा उपाय अधिनियम, 1947, सी. पी. और बरार सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और यू. पी. लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम। ये हैं कानून

वे प्रकृति में कठोर थे और उन लोगों के लिए एक निष्पक्ष परीक्षण के सार से इनकार करने की विशेषता थी जिनके पास उनके द्वारा निर्धारित संक्षिप्त प्रक्रिया के दायरे में आने का दुर्भाग्य था। उन्होंने पीड़ित व्यक्ति को अपनी दलीलों की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने का अवसर दिए बिना जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने के लिए एक संक्षिप्त प्रक्रिया प्रदान की। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए इन कानूनों के तहत विशेष अदालतों की स्थापना की गई थी। उन्हें कथित तौर पर खतरे में पड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इसलिए, उन्होंने अनिवार्य रूप से एक भयावह महत्व और गंध प्राप्त कर ली।

स्वतंत्रता के आगमन और हमारे अधिनियम के बाद

संविधान, सार्वजनिक व्यवस्था के खतरों से निपटने और लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभिन्न कानूनों के तहत विशेष अदालतों की स्थापना की गई थी। 1950 में संविधान के उद्घाटन के बाद के वर्षों में, इस न्यायालय को उन कानूनों की वैधता पर विचार करना पड़ा, जिनके तहत विभिन्न राज्य सरकारों को संविधान द्वारा सशक्त किया गया था।

राज्य

ऐसे अपराधों या अपराधों के वर्गों या मामलों या मामलों के वर्गों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए विधान मंडल, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में निर्देशित कर सकती है। सबसे पहला आरई:

विशेष न्यायालय विधेयक (चंद्रचूड़, सी. जे.)

527

संविधान लागू होने के बाद, जो विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना को संदर्भित करता है, जनार्दन रेड्डी और अन्य बनाम। हैदराबाद राज्य और अन्य (1) जिसमें हैदराबाद के सैन्य राज्यपाल ने निजाम द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों के आधार पर विशेष न्यायाधिकरणों का गठन किया, जिसमें तीन सदस्य थे। राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए उनके द्वारा नियुक्त। लेकिन उस मामले में निर्णय ने इस सवाल को जन्म दिया कि क्या हैदराबाद उच्च न्यायालय का निर्णय, जो 26 जनवरी, 1950 से पहले सुनाया गया था और जिसने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था, संविधान के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष फिर से खोला जा सकता है। उस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया गया था और उल्लंघन के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया था।

अनुच्छेद 14 का।

यह तर्क कि परीक्षण के लिए निर्धारित विशेष प्रक्रिया

इससे पहले कि विशेष न्यायालयों ने अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता की गारंटी का उल्लंघन किया था, विशेष रूप से उठाया गया था और इस न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, (1) काठी रानींग रावत बनाम में विचार किया गया था। सौराष्ट्र राज्य, (3) लचमंडस केवलराम आहूजा और अनूर। बनाम। बॉम्बे राज्य, (4) सैयद कासिम रजवी बनाम। हैदराबाद राज्य और अन्य।, (5) हबीब मोहम्मद बनाम। हैदर का राज्य

बुरा, (*) राव शिव बहादुर सिंह और अनूर। बनाम। विन्ध्य प्रदेश राज्य, (7) केदार नाथ बाजोरिया बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (*) और असगराली नैजराली सिंगापोरावाला बनाम। द स्टेट ऑफ बॉम्बे (")। इन मामलों में विभिन्न कानूनों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को लगभग बिना किसी अपवाद के भेदभावपूर्ण माना गया था, जिसके बारे में कोई गंभीर विवाद उचित रूप से नहीं उठाया जा सकता था। चूंकि विशेष प्रक्रिया थी अपराधों के मुकदमे के लिए निर्धारित सामान्य प्रक्रिया की तुलना में अधिक कठोर और कठिन, आगे जिस प्रश्न पर इस न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता थी, वह यह था कि क्या पक्षीय कानूनों के तहत अनुमेय वर्गीकरण वैध था। यदि वर्गीकरण वैध था, तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें एक साथ समूहीकृत किया गया था और जो दूसरों से अलग थे

एक अलग प्रक्रिया द्वारा कोशिश की जाए, भले ही यह अधिक कठिन हो, बशर्ते कि अंतर का मांगी गई वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध हो

विचाराधीन कानून द्वारा प्राप्त किया जाना।

(1) [1951] एस. सी. आर. 344 .

(3) [1952] एस. सी. आर 435

(4) [1952] एस. सी. आर 710

(5) [1953] एससीआर 589।

(6) [1953] एससीआर 661।

(7) [1953] एस. सी. आर. 1188

(8) [1954] एस. सी. आर. 30

(9) [1957] एस. सी. आर 678

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1979] 2 एस सी आर।

528

अनवर अली सरकार (ऊपर) में यह बहुमत द्वारा आयोजित किया गया था कि

पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950 की धारा 5 (1) पूरी तरह से अमान्य थी क्योंकि इसने सरकार को अपनी इच्छानुसार अपराधों या कैस्क को वर्गीकृत करने के लिए मनमाने अधिकार प्रदान किए थे और अधिनियम ने सरकार द्वारा इस अभ्यास के लिए कोई नीति या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए थे। मामलों या अपराधों को वर्गीकृत करने का उसका विवेकाधिकार। यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह अधिनियम उस अध्यादेश की एक शाब्दिक प्रति थी जिसे संविधान के लागू होने से पहले तैयार किया गया था और जैसा कि न्यायाधीश फजल अली (पृष्ठ 308) ने कहा था, अनुच्छेद 14 उन लोगों के दिमाग में मौजूद नहीं हो सकता था जिन्होंने आयुध तैयार किया था। जहाँ तक अपराधों के त्वरित विचारण की आवश्यकता के बारे में प्रस्तावना में दिए गए संदर्भ का संबंध है, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही प्रस्तावना के शब्दों को धारा 5 (1) में पढ़ा गया हो, "त्वरित परीक्षण" अभिव्यक्ति बहुत अस्पष्ट, अनिश्चित और तर्कसंगत वर्गीकरण के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए मायावी थी। दास जे. ने आयोजित किया

धारा आंशिक रूप से शून्य होगी जहाँ तक कि यह सरकार को विशेष न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने के लिए "मामलों के वर्गों" से अलग "मामलों" को निर्देशित करने का अधिकार देती है। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, कुछ अपराधों के त्वरित सुनवाई के लिए प्रावधान अधिनियम का उद्देश्य था जो बोधगम्य अंतर से एक अलग बात थी जो वर्गीकरण का आधार होना चाहिए था। भेद और उद्देश्य अलग-अलग तत्व होने के कारण, उद्देश्य अपने आप में अपराधों या मामलों के वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकता है। सभी मामलों या अपराधों के वर्गों या मामलों के वर्गों के निपटारे में त्वरित सुनवाई वास्तव में वांछनीय थी। पतंजलि शास्त्री सी. जे. ने अपने असहमत निर्णय में

कहते हैं कि राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से या विवेक के साथ काम किया था तब से मामलों को विशेष न्यायालय में भेजने का महत्वपूर्ण इरादा

विशेष विशेषताएँ थीं जो विशेष समूह को चिह्नित करती थीं।

के तहत संभव से अधिक तेजी से निपटान की आवश्यकता वाले मामले

सामान्य प्रक्रिया।

काथी रानिंग रावत (ऊपर) का फैसला उसी पीठ ने किया था जो अनवर अली सरकार ने लिया था। दोनों मामलों की आंशिक रूप से एक साथ सुनवाई हुई लेकिन पूर्ववर्ती को स्थगित कर दिया गया ताकि राज्य सरकार उन परिस्थितियों को समझाते हुए एक हलफनामा दायर कर सके जिनके कारण विशेष अध्यादेश पारित किया गया था। सौराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सुरक्षा उपाय (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 1949 की धारा 11, जिसे काठी रानींग रावत (उपरोक्त) में आक्षेपित किया गया था, पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950 की धारा 5 (1) के समान थी। इसका उल्लेख किया गया है

चार अलग-अलग श्रेणियाँ, अर्थात् "अपराध", "अपराधों के वर्ग", "मामले" और "मामलों के वर्ग" और राज्य सरकार को इन श्रेणियों में से किसी एक या अधिक पर अध्यादेश के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने का निर्देश देने का अधिकार दिया। यह बहुमत आरई द्वारा आयोजित किया गया था:

विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

कि उस अध्यादेश की प्रस्तावना, जिसमें "सौराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और शांति और शांति की पूर्व पूर्ति के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता" का उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे के साथ, जिसमें उन तथ्यों को समझाया गया है जिनके तहत विवादित आदेश पारित किया गया था, अनवर अली सरकार (ऊपर) से मामले को अलग करने का आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह स्पष्ट था कि सरकार के पास विशेष प्रक्रिया द्वारा मुकदमा चलाने के लिए अपराधों, अपराधों के वर्गों या मामलों के वर्गों को वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन था। इसलिए, बहुमत के अनुसार, अध्यादेश की धारा 11 जहां तक यह राज्य सरकार को अधिकृत करती है

प्रत्यक्ष अपराधों, अपराधों के वर्गों या अपराधों के वर्गों के लिए दंड

विशेष अदालत द्वारा चलाए जाने वाले मामले उल्लंघनकारी नहीं थे

अनुच्छेद 14 और अधिसूचना जो उस भाग के तहत जारी की गई थी

अध्यादेश अमान्य या अधिकार से बाहर नहीं था

मुखर्जी जे. और दास जे., जिन्होंने चार में से दो बहुमत दिए।

निर्णयों ने जारी अधिसूचना के बीच अंतर को इंगित किया

अनवर अली सरकार (ऊपर) में और जो काठी रानींग में जारी किया गया था

रावत (ऊपर) (पृष्ठ 454-455 और पृष्ठ 470 देखें)। जबकि,

पूर्व को पश्चिम बंगाल की धारा 5 (1) के उस भाग के तहत जारी किया गया था।

विशेष न्यायालय अधिनियम जो राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए अधिकृत करता है

विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने वाले विशेष "मामले", बाद वाला था

सौराष्ट्र अध्यादेश की धारा 11 के उस भाग के तहत जारी किया गया जिसने राज्य सरकार को "अपराधों", "वर्गों" को निर्देशित करने के लिए अधिकृत किया

विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने वाले अपराधों या मामलों के वर्गों का।

लच्चमंडस आहूजा में, (ऊपर) एक बैंक डकैती के मामले को बॉम्बे सरकार द्वारा विशेष न्यायाधीश के पास मुकदमे के लिए भेजा गया था।

बॉम्बे सार्वजनिक सुरक्षा उपाय अधिनियम, 1947 की धारा 12, जो पश्चिम बंगाल अधिनियम की धारा 5 (1) और सौराष्ट्र अध्यादेश की धारा 11 के समान ही थी। सवाल यह था कि

अनवर अली सरकार और काठी रानींग रावत (उपरोक्त) के निर्णयों के अनुपात से पूरी तरह से कवर किया गया, जिसके आवेदन द्वारा बहुमत ने माना कि तर्क की समानता पर, धारा 12 उस हद तक असंवैधानिक थी, जिस हद तक उसने सरकार को विशेष न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाने के लिए विशेष "मामलों" का निर्देश देने के लिए अधिकृत किया था। पतंजलि शास्त्री सी. जे. इस पहलू पर बहुमत से अलग नहीं थे

बात है। उन्होंने कहा कि यह मानते हुए कि अनवर अली सरकार में निर्णय को देखते हुए धारा 12 का विशेष भाग भेदभावपूर्ण था, (ऊपर) मुकदमा जो पहले ही शुरू हो चुका था, बाद में संविधान के लागू होने से दूषित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, बॉम्बे राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अटॉर्नी जनरल ने धारा 12 के प्रासंगिक भाग की अयोग्यता के संबंध में कानूनी स्थिति का विरोध नहीं किया।

1

[1979] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

530

सैयद कासिम रजवी, हबीब मोहम्मद और राव शिव बहादुर

सिंह, (ऊपर) संविधान लागू होने की तारीख से पहले मुकदमे शुरू हो गए थे। इनमें से पहले मामले में बहुमत द्वारा और अन्य दो मामलों में एक सर्वसम्मत न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 13 का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है, कि एक पूर्व-संविधान कानून को पिछले सभी लेनदेन के लिए वैध माना जाना चाहिए और इसलिए, विशेष न्यायाधिकरण या विशेष न्यायालय ने उनके समक्ष मामलों का वैध रूप से संज्ञान लिया था। संविधान के लागू होने के बाद मुकदमे में जो कुछ बचा था, वह भौतिक मामलों में सामान्य मानक से विचलित नहीं था, ताकि अनुच्छेद 14 के अर्थ के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार किया जा सके।

केदार नाथ बाजोरिया (ऊपर) में अपीलार्थी का मामला

और दो अन्य राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय को आवंटित किए गए थे जिसका गठन सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1949 की धारा 3 के तहत किया

गया था। मुकदमा 3 जनवरी, 1950 को शुरू हुआ और संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी से पहले नौ अभियोजनों की मुख्य रूप से जांच की गई। विशेष न्यायालय द्वारा 29 अगस्त, 1950 को दंड संहिता की धारा 120 बी और 420 और निवारक भ्रष्टाचार अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) के तहत दोषसिद्धि का आदेश दर्ज किया गया था। अपीलार्थियों का यह तर्क कि अधिनियम की धारा 4, जिसके तहत राज्य सरकार ने विशेष न्यायालय को अपना मामला आवंटित किया था, ने अनवर अली सरकार (उपरोक्त) में अनुपात लागू करके अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया था, बहुमत द्वारा खारिज कर दिया गया था, जे. बोस ने असहमति जताते हुए कहा कि अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य और नीति को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इसके शीर्षक, प्रस्तावना और इसके प्रावधानों द्वारा प्रकट किया गया है,

उन अपराधों का वर्गीकरण जिनके विचारण के लिए विशेष न्यायालय

स्थापित किया गया था और एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई थी जिसे अनुचित या मनमाना नहीं कहा जा सकता था। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए,

न्यायालय ने उस पर भरोसा किया जिसे "प्रसिद्ध" के रूप में वर्णित किया गया था कि

युद्ध के बाद की अवधि, कई उपक्रम जो इसके लिए स्थापित किए गए थे

संकट और आवश्यक आपूर्ति के नियंत्रण ने विशेष अवसर दिए

अधिनियम की अनुसूची के दौरान आम और व्यापक रूप से प्रचलित थे विशेष
अवधि और यह एक प्रभावी जाँच करने के लिए था

उन अपराधों पर जिन्हें विवादित कानून की आवश्यकता माना जाता था सरी। ऐसा
विधान, बहुमत के अनुसार, जिसके तहत स्पी

विशेष प्रकार के मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई थी

एक छोटी और सरलीकृत प्रक्रिया, एक पूरी तरह से बुद्धिमत्ता पर आधारित थी
स्पष्ट और उचित संबंध रखने वाले वर्गीकरण के गीबल सिद्धांत आरई:

विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि अधिनियम राज्य सरकार को किसी व्यक्ति के किसी विशेष मामले को चुनने के लिए एक निरंकुश विवेकाधिकार प्रदान करता है

अभियुक्त और उसे मुकदमे के लिए विशेष अदालत में भेजें। इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह विधायिका के लिए सक्षम था कि वह चुनिंदा व्यक्तियों पर कानून लागू करने के लिए इसे प्रशासनिक प्राधिकरण पर छोड़ दे।

या अंतर्निहित नीति का संकेत देकर एक परिभाषित समूह के भीतर की चीजें

और उद्देश्य जिसके अनुसार और जिसके पूरा होने में प्रशासनिक प्राधिकरण से व्यक्तियों या चीजों का चयन करने की अपेक्षा की जाती थी

बहुमत के अनुसार, कि राज्य सरकार नहीं थी अनुसूची में निर्धारित अपराधों के सभी मामलों को आवंटित करने के लिए बाध्य

विशेष न्यायाधीश लेकिन मामले में विवेकाधिकार के साथ निहित थे और विशेष न्यायालय के समक्ष केवल मुकदमे के लिए कुछ मामलों का चयन कर सकते थे

अनुच्छेद 14 के विरुद्ध अपराध।

असगराली नजराली सिंगापोरावाला में, (सुप्रा) संसद द्वारा अधिनियमित आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 लागू हुआ, जबकि अपीलार्थी और अन्य पर दंड संहिता की धारा 116 आदि के साथ पठित धारा 161 के तहत अपराधों के लिए प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, बॉम्बे के समक्ष मुकदमा चलाया जा रहा था। अधिनियम में विशेष न्यायाधीशों द्वारा रिश्वत और भ्रष्टाचार के अपराधों की सुनवाई और सभी लंबित मुकदमों को ऐसे न्यायाधीशों को हस्तांतरित करने का प्रावधान है। प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने अधिनियम के पारित होने के बावजूद मुकदमा जारी रखा और अपीलार्थियों को बरी कर दिया। इस न्यायालय द्वारा सर्वसम्मति से यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि लोक सेवकों द्वारा रिश्वत और भ्रष्टाचार के अपराधों को उचित रूप से एक समूह या श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण जो एक अंतर्दृष्टिपूर्ण निर्विवादता पर स्थापित किया गया था, अधिनियम के उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध रखने के लिए आयोजित किया गया था, जो कुछ अपराधों के त्वरित मुकदमे का प्रावधान करने के लिए था। इस न्यायालय पर एक तर्क दिया गया था जो अनवर अली सरकार (सुप्रा) में क्रमशः पृष्ठ 314 और 328 पर महाजन जे. और मुखर्जी जे. के आक्षेपों पर आधारित था, कि अपराधों के त्वरित मुकदमे में वर्गीकरण के लिए एक उचित आधार नहीं हो सकता है। जाहिरा तौर पर उस तर्क को अदालत का समर्थन नहीं मिला,

जिसमें कहा गया था (पृष्ठ 691) कि अनवर अली सरकार में विद्वान न्यायाधीशों की विशेष टिप्पणियाँ, अकेले खड़े होकर, इस तर्क का समर्थन कर सकती हैं -

तर्क लेकिन उन टिप्पणियों में अंतर्निहित सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा केदार नाथ बाजोरिया में निर्णायक नहीं माना गया था। (सुप्रा)

यह विश्लेषण मगनलाल छगनलाल (पी) लिमिटेड बनाम इस मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले के संदर्भ के बिना अधूरा होगा।

नगरपालिका [1979] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

532

[

ग्रेटर बॉम्बे एंड ओआरएस निगम। (1) उस मामले में दो समानांतर

प्रक्रियाएं, एक बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1888 के अध्याय वी. ए. के तहत और दूसरी बॉम्बे गवर्नमेंट प्री मिसेस (बेदखली) अधिनियम, 1955 के तहत, व्यक्तियों को बेदखल करने के लिए उपलब्ध थीं।

सार्वजनिक परिसर से। दोनों अधिनियमों के प्रासंगिक पक्षकारों की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि दोनों अधिनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया दीवानी मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया की तुलना में अधिक कठोर और प्रतिकूल थी और यह अधिकारियों के मनमाने और निरंकुश विवेक पर छोड़ दिया गया था कि वे कुछ और अध्यादेशों के खिलाफ ऐसी विशेष प्रक्रिया अपनाएं।

दूसरों के खिलाफ दीवानी मुकदमे का कोई उपाय नहीं। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां सामान्य प्रक्रिया से भिन्न अधिक कठोर प्रक्रिया के लिए उपबंध करने वाला कोई कानून सामान्य प्रक्रिया द्वारा कवर किए गए पूरे क्षेत्र को शामिल करता है, बिना किसी दिशानिर्देश के उन मामलों के वर्ग के रूप में जिसमें किसी भी प्रक्रिया का सहारा लिया जाना है, कानून अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित होगा। हालांकि, अपील के लिए एक प्रावधान ठीक कर सकता है

दोष और यदि प्रस्तावना और आसपास की परिस्थितियों से

साथ ही कानूनों के प्रावधानों को स्वयं, हलफनामों द्वारा समझाया और प्रवर्धित किया गया, आवश्यक दिशानिर्देशों को स्पष्ट किया जा सकता है,

कानून अनुच्छेद 14 से प्रभावित नहीं होगा। दोनों अधिनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के गुण-दोष पर न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह इतना कठोर या अनुचित नहीं था कि इस निष्कर्ष को उचित ठहराया जा सके कि यदि कुछ मामलों में उनका सहारा लिया जाता है तो भेदभाव का परिणाम होगा और अन्य मामलों में दीवानी अदालतों की सामान्य प्रक्रिया। एक अलग लेकिन कोन द्वारा

हम में से दो, अर्थात् भगवती, जे. और वी. आर. कृष्ण अय्यर जे. ने निर्णय देते हुए कहा कि यह अपरिहार्य था कि जब कोई विशेष प्रक्रिया होती है तो

व्यक्तियों के एक परिभाषित वर्ग के लिए निर्धारित, जैसे कि मुनि पर कब्जा करने वाले सिविल या सरकारी परिसर, विवेकाधिकार जो निर्देशित और नियंत्रित है

कानून की अंतर्निहित नीति और उद्देश्य के अनुसार आवश्यक रूप से प्रशासनिक प्राधिकरण में निहित होना चाहिए जो मुनि सिपाल या सरकारी निकायों पर कब्जा करने वालों का चयन करता है ताकि उन्हें संचालन के भीतर लाया जा सके।

विशेष प्रक्रिया। विद्वान न्यायाधीशों ने आगे कहा कि विशेष प्रक्रिया और सामान्य प्रो के बीच मामूली अंतर हैं।

समानता खंड के निषेध को लागू करने के लिए अनुज्ञा पर्याप्त नहीं है।

और यह नहीं माना जा सकता है कि केवल इसलिए कि एक प्रो

एक नियमित अदालत के मंच का प्रतिनिधित्व करता है जबकि दूसरा प्रदान करता है

एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मंच, बाद वाला अनिवार्य रूप से अधिक है

पहले वाले की तुलना में कठोर और कठिन। इसलिए, विद्वान ने कहा

न्यायाधीश, जब भी विधायिका द्वारा कोई विशेष तंत्र तैयार किया जाता है

स्थापित प्राधिकारी को विवादों के निर्धारण की शक्ति पर भरोसा करना

विधायिका द्वारा कानून के नियमित न्यायालयों के प्रतिस्थापन में, किसी को चाहिए

आरई: विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

533

केवल न्यायालयों द्वारा न्याय के प्रशासन की प्रचलित प्रणाली के लिए एक निश्चित झुकाव के कारण इस तरह के प्राधिकरण की स्थापना के खिलाफ प्रतिकूल प्रतिक्रिया न करें। महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगों के लिए उपयोग के लिए सार्वजनिक परिसरों की त्वरित और त्वरित वसूली की आवश्यकता के संदर्भ में, जहां प्रक्रिया की शिथिलता वसूली के उद्देश्य को विफल कर सकती है, विशेष प्रक्रिया द्वारा निर्धारित

इन दोनों अधिनियमों को दीवानी अदालत की सामान्य प्रक्रिया की तुलना में वास्तव में और काफी अधिक कठोर और प्रतिकूल नहीं माना गया था। दोनों अधिनियमों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया। यह देखा गया था, इतना महत्वपूर्ण और गुणात्मक रूप से असमान नहीं था कि विवेक की बुराई को आकर्षित किया जा सके

खनन।

ऐसे कई मामले हैं जो प्रो के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं।

अनुच्छेद 14 के तहत उत्पन्न होने वाले दोष और जो लागू होने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं

उन प्रश्नों के लिए जो आमतौर पर उस लेख के तहत उत्पन्न होते हैं। इनमें से

बुधन चौधरी और अन्य बनाम में निर्णयों का उल्लेख किया जा सकता है।

बिहार राज्य। (1) श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस. आर.

तेंदोलकर और अन्य, () श्री सी. एल. एमडेन बनाम। यू. पी. राज्य (3)

कंगसारी हलदर और एक अन्य बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य, () ज्योति

प्रसाद बनाम। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए प्रशासक (*) और गुजरात राज्य और एक अन्य बनाम श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड,

अहमदाबाद, आदि (') लेकिन, जैसा कि मैथ्यू जे. ने अंतिम पुरुषों में देखा था।

कथित मामला, "यह समीक्षा करने के लिए परिचित सीखने की एक निष्क्रिय परेड होगी

बहुविषयक मामले जिनमें संवैधानिक आश्वासन

कानून के समक्ष समानता लागू की गई है। इसलिए, हमारे पास केवल उन मामलों पर हमारा ध्यान केंद्रित करें जिनमें विशेष न्यायाधिकरण या

अपराधों की सुनवाई के लिए अदालतें स्थापित की गईं या विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई या अपराधों के वर्ग या मामले या मामलों के वर्ग। सर्वेक्षण जो

हमने उन मामलों को बनाया है जो एक उचित विचार देने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं

वैधता निर्धारित करने में जिन सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए

ऐसे मामलों में वर्गीकरण और विशेष प्रक्रिया की तर्कसंगतता

अभियुक्त अपराधियों के मुकदमे के लिए निर्धारित आदेश एक अलग गठन करने के लिए या विशिष्ट वर्ग।

यह बहुत पहले 1960 में इस अदालत ने कांगसारी में कहा था

हलदर (सुप्रा) कि पूर्वसर्ग निम्नलिखित मामलों में लागू होते हैं -

पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनुच्छेद 14 को कई बार दोहराया गया है।

कि वे अब लगभग मनगढ़ंत लगते हैं "। किन बातों पर विचार किया गया

(1) [1955] (1) एस. सी. आर. 1045

(2) [1959] एस. सी. आर 279

(3) [1960] (2) एससीआर 592।

(4) [1960] (2) एस. सी. आर 646

(5) [1962] (2) एससीआर 125।

(6) [1974] (3) एस. सी. आर. 760

[1979] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

53 4

कुछ 18 साल पहले स्वाभाविक रूप से ऐसा हुआ था

इस न्यायालय के एड न्यायाधीश ने कहा है कि यह गठन में नहीं है अनुच्छेद 14 के तहत सिद्धांत लेकिन ठोस मामलों में उनके अनुप्रयोग में

कि कठिनाइयाँ आम तौर पर उत्पन्न होती हैं। लेकिन, यह देखते हुए कि हम उन कुछ लोगों की तुलना में एक बड़ी पीठ में बैठे हैं जिन्होंने अनुच्छेद के तहत समान मामलों का फैसला किया था

14 , और में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के विशिष्ट महत्व को ध्यान में रखते हुए

यह संदर्भ, हालांकि प्रश्न स्वयं एक पूर्व टिप्पणी के बिना नहीं हैं, हम प्रस्ताव करते हैं, हालांकि निस्संदेह कुछ पुनरावृत्ति की कीमत पर, इस के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले पूर्वसर्गों को बताने के लिए। जहाँ तक वे हमारे विचार के लिए उत्पन्न होने वाले बिंदुओं के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं। उन प्रस्तावों को इस प्रकार कहा जा सकता है:

1. अनुच्छेद 14 का पहला भाग, जिसे अनुच्छेद 14 से अपनाया गया था

आयरिश संविधान, नागरिक समानता की घोषणा है।

भारत के क्षेत्रों के भीतर सभी व्यक्तियों के अधिकार। यह.

गणतंत्रवाद का एक बुनियादी सिद्धांत स्थापित करता है। दूसरा।

भाग, जो पहले का परिणाम है और इस पर आधारित है

चौदहवें संशोधन की पहली धारा का अंतिम खंड

अमेरिकी संविधान के अनुसार, यह आदेश देता है कि

ऐसे सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी

भेदभाव के बिना उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं का आनंद लेना।

समान कानून, अर्थात् ऐसे कानून जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कार्य करते हैं। समान परिस्थितियों में।

2. राज्य को अपनी सरकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपनी नीतियों को प्रभावी बनाने में विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के भीतर विभिन्न समूहों या

व्यक्तियों के वर्गों पर अलग-अलग तरीके से काम करने वाले कानून बनाने की आवश्यकता है, और उस उद्देश्य के लिए उसे ऐसे व्यक्तियों या चीजों को अलग करने और वर्गीकृत करने की बड़ी शक्तियां होनी चाहिए जिनके अधीन होना चाहिए।

आई।

कानून।

3. राज्य को अपने कानूनों की समान सुरक्षा प्रदान करने का संवैधानिक आदेश एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करता है जो एक सटीक सूत्र के आविष्कार और अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इससे पहले, वर्गीकरण का गठन व्यक्तियों या चीजों के सटीक या वैज्ञानिक बहिष्कार या समावेश द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालयों को भ्रामक सटीकता पर जोर नहीं देना चाहिए या इसकी वैधता निर्धारित करने के लिए सैद्धांतिक परीक्षण लागू नहीं करना चाहिए।

किसी भी मामले में वर्गीकरण। वर्गीकरण उचित है।

यदि यह स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है।

आरई: विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

535

अनुच्छेद 14 की गारंटी में अंतर्निहित सिद्धांत नहीं है कि कानून के समान नियम सभी पर लागू होने चाहिए

भारतीय क्षेत्र के भीतर के व्यक्ति या वही व्यक्ति

उनके लिए मृत्यु दर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, चाहे जो भी हो

परिस्थितियों का अंतर। इसका मतलब यह है कि सभी

समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा

प्रदत्त विशेषाधिकारों और अधिरोपित देनदारियों में। समान।

कानून को एक ही स्थिति में सभी पर लागू करना होगा

यह, और एक के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए
 व्यक्ति और अन्य यदि विषय के संबंध में -
 कानून बनाना उनकी स्थिति काफी हद तक समान है।
 वर्गीकरण की प्रक्रिया से, राज्य के पास शक्ति है
 यह निर्धारित करने के लिए कि किसे एक वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए
 विधान के उद्देश्यों और अधिनियमित कानून के संबंध में
 किसी विशेष विषय पर। यह शक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है, कुछ में
 डिग्री कुछ असमानता पैदा करने की संभावना है; लेकिन अगर एक कानून
 कई अच्छी तरह से परिभाषित लोगों की स्वतंत्रता से संबंधित है
 वर्ग, यह समान प्रो के इनकार के आरोप के लिए खुला नहीं है
 इस आधार पर कि इसका अन्य पर कोई अनुप्रयोग नहीं है
 लोग। इस प्रकार वर्गीकरण का अर्थ है वर्गों में अलगाव।
 जिनका एक व्यवस्थित संबंध होता है, जो आमतौर पर कॉम में पाया जाता है
 मोन गुण और विशेषताएँ। यह अभिधारणा करता है कि
 तर्कसंगत आधार और इसका मतलब यह नहीं है कि
 कुछ व्यक्ति और वर्ग मनमाने ढंग से।

5. कानून के अनुसार वर्गों को बना और अलग कर सकता है

समाज की आवश्यकताएँ और आवश्यकताएँ और जैसा कि सुझाव दिया गया है
 अनुभव से। यह बुराई के स्तर को भी पहचान सकता है, लेकिन

वर्गीकरण कभी भी मनमाना, कृत्रिम या कृत्रिम नहीं होना चाहिए।
 वाला।

टालने

7. वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए लेकिन होना चाहिए

तर्कसंगत, अर्थात्, यह केवल कुछ पर आधारित नहीं होना चाहिए

गुण या विशेषताएँ जो सभी में पाई जाती हैं

व्यक्तियों को एक साथ समूहीकृत किया गया है और दूसरों में नहीं जो हैं छोड़ दिया लेकिन उन गुणों या विशेषताओं में एक होना चाहिए

विधान के उद्देश्य के लिए उचित संबंध में।

परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, दो शर्तों को पूरा करना होगा,

अर्थात्, (1) कि वर्गीकरण पर आधारित होना चाहिए

एक बोधगम्य अंतर जो उन लोगों को अलग करता है जो हैं

दूसरों से एक साथ समूहीकृत और (2) वह अंतर साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए

इच्छित वस्तु के

अधिनियम द्वारा प्राप्त किया गया।

[1979] 2

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

. भेद जो वर्गीकरण का आधार है और

अधिनियम का उद्देश्य अलग-अलग चीजें हैं और क्या है उनके बीच एक सांठगांठ हो।

यह आवश्यक है कि

व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्रदान करना या देनदारियाँ थोपना अन्य व्यक्तियों में से मनमाने ढंग से चुना गया

बड़ी संख्या में

समान रूप से इच्छित विशेषाधिकारों के संबंध में स्थित है

प्रदत्त या अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित देनदारियाँ, यह करती है विधान के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण को निषिद्ध नहीं करता है,

बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण इस अर्थ में मनमाना न हो

ऊपर बताया गया है।

. यदि विधायी नीति स्पष्ट और निश्चित है और

उस नीति को विवेकपूर्ण तरीके से लागू करने का प्रभावी तरीका

कानून द्वारा प्रशासकों के एक निकाय पर निहित है या

कुछ अधिकारियों के लिए कानून का चयनात्मक अनुप्रयोग करना

व्यक्तियों के वर्ग या समूह, कानून स्वयं नहीं हो सकता है

भेदभावपूर्ण कानून के एक टुकड़े के रूप में निंदा की गई। में।

ऐसे मामलों में, कार्यकारी निकाय को दी गई शक्ति

कानून के विषय को वर्गीकृत करने के लिए उस पर 'शुल्क' का आयात करें।

में दर्शाए गए उद्देश्य के अनुसार

कानून। यदि प्रशासनिक निकाय वर्गीकरण करने के लिए आगे बढ़ता है

ऐसे आधार पर व्यक्ति या चीजें जिनका कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है विधायिका के
उद्देश्य के लिए, इसकी कार्यवाही हो सकती है

समान संरक्षण खंड के खिलाफ अपमानजनक के रूप में रद्द कर दिया गया।

दूसरी ओर, यदि कानून स्वयं खुलासा नहीं करता है एक निश्चित नीति या उद्देश्य
और यह अधिकार प्रदान करता है

एक और अपनी खुशी पर चयन करने के लिए, कानून

इसके चेहरे पर भेदभावपूर्ण माना जाएगा,

चाहे इसे लागू करने का कोई भी तरीका हो।

क्या कोई कानून किसी को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है

इस धारणा पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए कि इस तरह प्राधिकरण प्रयोग
करने में मनमाने तरीके से कार्य करेगा

इसके लिए प्रतिबद्ध विवेकाधिकार। कानून द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग

होता है; लेकिन कानून की वैधता का विरोध नहीं किया जा सकता है

इस तरह की आशंका के कारण। विवेकाधीन शक्ति है

जरूरी नहीं कि एक भेदभावपूर्ण शक्ति हो।

वर्गीकरण का तात्पर्य अनिवार्य रूप से एक विशिष्टता बनाना है। वर्गीकृत व्यक्तियों और उन लोगों के बीच भेदभाव या भेदभाव

जो उस वर्ग के सदस्य नहीं हैं। यह सार है कि

एक वर्गीकरण जो वर्ग पर कास्ट कर्तव्यों और आरई हैं:

विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

537

सामान्य पब में आराम करने वालों से अलग बोझ

लाइकी। वास्तव में, वर्गीकरण का विचार ही यह है कि

समानता, ताकि यह बिना कहे चला जाए कि केवल

असमानता का तथ्य किसी भी तरह से इस मामले को निर्धारित नहीं करता है

संवैधानिकता।

12. क्या विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करने वाला कोई अधिनियम

कुछ अपराधों का मुकदमा भेदभावपूर्ण है या नहीं है और

प्रत्येक मामले में अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए -

यह उत्पन्न होता है, क्योंकि सभी मामलों पर लागू कोई सामान्य नियम नहीं हो सकता है

सुरक्षित रूप से रखा जाए। ओप का एक व्यावहारिक मूल्यांकन

विशेष परिस्थितियों में कानून का अनुपात आवश्यक है।

सरी।

13. कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का नियम उतना ही आता है जितना

उपखंड के किसी भी नियम के रूप में अनुच्छेद 14 के दायरे में

कानून और यह आवश्यक है कि सभी वादी, जो हैं
समान रूप से स्थित, स्वयं का लाभ उठाने में सक्षम हैं

राहत और रक्षा के लिए समान प्रक्रियात्मक अधिकार
संरक्षण और बिना भेदभाव के।

इन परीक्षणों के अनुप्रयोग से, निष्कर्ष अप्रतिरोध्य है कि

विशेष न्यायालय विधेयक द्वारा प्रदान किया गया वर्गीकरण वैध है और इसके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं ली जा सकती है। चूंकि विधेयक अपराधों के एक वर्ग और केवल अपराधियों के एक वर्ग के विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमे का प्रावधान करता है, इसलिए विचार के लिए जो प्राथमिक प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या विधेयक इस वर्गीकरण के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करता है कि क्या इसके द्वारा परिकल्पित वर्गीकरण मनमाना और कृत्रिम है। विधेयक के खंड 5 द्वारा केवल उन अपराधों का ही विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण किया जा सकता है जिनके संबंध में केंद्र सरकार ने खंड 4 (1) के तहत घोषणा की है। वह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा केवल तभी की जा सकती है जब उसकी राय हो कि प्रस्तावना में उल्लिखित अवधि के दौरान, भारत में उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पद धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने का प्रथम दृष्टया प्रमाण है और यह कि विधेयक की प्रस्तावना में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार, उक्त अपराध से अधिनियम के तहत निपटा जाना चाहिए। इस प्रकार जो वर्गीकरण धारा 4 (1) करती है, वह अपराधों और अपराधियों दोनों का है, पहला, प्रस्तावना में उल्लिखित अवधि के संबंध में, अर्थात् 27 फरवरी, 1975 से 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा होने तक और संविधान के छठे पैराग्राफ में उल्लिखित उद्देश्य के संबंध में कि संसदीय डेमोक्रेसी और भारत के संविधान द्वारा या उसके तहत बनाए गए संस्थानों के कामकाज के लिए यह अनिवार्य है कि ऐसे अपराधों को करने से न्यायिक रूप से रोका जाना चाहिए।

16

—978 एससीआई/78 [1979] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दर्जा, अर्थात्, भारत में उनके द्वारा धारण किए गए उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पद के संबंध में। यह केवल तभी है जब ये दोनों कारक सह-अस्तित्व में हैं कि विशेष अपराधियों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में अभियोजन विशेष न्यायालय में स्थापित किया जा सकता है।

:

आपातकाल की घोषणा एक मामला नहीं है और न ही हो सकता है

किसी राष्ट्र के जीवन में सामान्य घटना और वास्तव में आपातकाल की घोषणा एक असाधारण स्थिति के कारण आवश्यक होने का दावा किए बिना नहीं रह सकता है। संविधान का अनुच्छेद 352, जिसके तहत जून, 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था, अध्याय XVIII में आता है जिसे "आपातकालीन प्रावधान" कहा जाता है। वह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि एक "गंभीर आपातकाल" मौजूद है जिससे भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है, चाहे वह युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से हो। अनुच्छेद 358 के तहत, जबकि आपातकाल की घोषणा की जाती है

संचालन में, राज्य एक कानून बना सकता है या कोई कार्यकारी कार्रवाई कर सकता है, भले ही वह अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। यह एक ऐसा परिणाम है जो आपातकाल की घोषणा पर प्रभाव डालता है। 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा के बाद राष्ट्रपति ने 27 जून को अनुच्छेद 359 के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर दिया गया।

आपातकाल की अवधि के दौरान, कई दूरगामी कानून बनाए गए

परिणाम संसद और विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा पारित किए गए थे

और लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्रभावित करने वाले आदेश केंद्र सरकार द्वारा या उसके अधिकार के तहत जारी किए गए थे। इनमें भारतीय रक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1975; विदेशी मुद्रा की स्वीकृति और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 1975; आंतरिक सुरक्षा का रखरखाव शामिल हैं।

(संशोधन) अधिनियम, 1975; चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975; संविधान (अड़तीस और उनतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975; आंतरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1976 का रखरखाव; आंतरिक सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976; प्रेस काउंसिल (निरसन) अधिनियम, 1976; आपत्तिजनक मामलों के प्रकाशन की रोकथाम अधिनियम, 1976; पार्लिया मेंटरी कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) निरसन अधिनियम, 1976; संविधान

(बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976; लोक (संशोधन) अध्यादेश, 1977 की पुनः प्रस्तुति; विवादित चुनाव (प्रधानमंत्री और अध्यक्ष) अध्यादेश, 1977; और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव। आपातकाल की घोषणा के बाद, प्रेस सेंसरशिप लागू करने की दृष्टि से विभिन्न रेग्युलेटोरी उपाय किए गए।

1 आरई: विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

539

इस संबंध में आदेश और निर्देश 26 जून, 5 जुलाई को दिए गए हैं।

6 जुलाई, 13 जुलाई और 5 अगस्त, 1975। 8 जनवरी, 1976 को अनुच्छेद 359 (1) के तहत एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया था जिसमें अधिकार को निलंबित कर दिया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय का रुख करना। आपातकाल की अवधि के दौरान किए गए इन और अन्य उपायों को एक द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

हममें से, फज़ल अली, जे. राजस्थान राज्य में और अन्य। बनाम भारत संघ (1) इस प्रकार:

(1) पूरे इलाके में एक गंभीर आपातकाल लगा दिया गया था।

देश;

(2) नागरिक स्वतंत्रता को काफी हद तक वापस ले लिया गया था।

(3) लोगों के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार थे

निलंबित;

(4) प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगाई गई थी; और

(5) न्यायिक शक्तियों को काफी हद तक अपंग कर दिया गया था।

विधेयक की प्रस्तावना के तीसरे खंड में एक सटीक पुनरावृत्ति है।

इन पाँच कारकों का अपघटन।

28 मई, 1977 को भारत सरकार ने अपने मंत्रालय में गृह मंत्रालय ने आयोग की धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी की जांच अधिनियम, 1952 के तहत सेवानिवृत्त प्रमुख श्री जे. सी. शाह की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जांच आयोग के रूप में "अधिकार के दुरुपयोग के आरोपों के कई पहलुओं" में पूछताछ, पूर्व उपकर और किए गए कदाचार और की गई या की गई कार्रवाई 25 तारीख को घोषित आपातकाल के मद्देनजर लिया जाना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जून, 1975 "। आयोग ने 11 मार्च और 26 अप्रैल को दो भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 1978 , जिसमें इसके निष्कर्ष शामिल हैं जिन्हें आम तौर पर कहा जाता है ' एमेर की अवधि के दौरान की गई ज्यादतियों का आरोप भारत में उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा सम्मान और दूसरों द्वारा उनके साथ या उनके सहयोग से निवान्स। इसके लिए कुछ अन्य आयोग भी नियुक्त किए गए थे। उद्देश्य। विधेयक की प्रस्तावना का पहला पाठ संदर्भित करता है - इन जांच आयोगों द्वारा दी गई रिपोर्टों में खुलासा किया गया है कि उन व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के प्रथम दृष्टया साक्ष्य की उपस्थिति जो देश में उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों पर रहे और अन्य जुड़े हुए। 25 जून, 1975 के आपातकाल के दौरान उनके साथ और 27 फरवरी, 1975 की पूर्ववर्ती अवधि।

(1) [1978] 1 एस. सी. आर. 1,181.

[1979] 2 एससीआर।

540

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हम नियत समय में बाद की तारीख की प्रासंगिकता पर विचार करेंगे, लेकिन जिन तथ्यों और परिस्थितियों का हमने ऊपर वर्णन किया है, वे नहीं छोड़ते हैं संदेह है कि इस अवधि के दौरान कथित अपराध किए गए हैं

आपात स्थिति अपने आप में एक वर्ग का गठन करती है और इसी तरह वे व्यक्ति भी करते हैं जिन पर उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों का उपयोग करने का आरोप लगाया जाता है।

उनके द्वारा प्रतिबद्ध होने के उद्देश्य से एक आवरण या अवसर के रूप में आयोजित किया गया उन अपराधों को। हम सच्चाई या अन्यथा से चिंतित नहीं हैं

आरोप, हमारे सामने संकीर्ण सवाल यह है कि क्या,

सबसे पहले, वर्गीकरण कुछ गुणों या विशेषताओं पर आधारित है।

स्टिक्स जो एक साथ समूहबद्ध सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं और दूसरों में नहीं जो छूट गए हैं। इस सवाल का जवाब हो सकता है

एक और केवल एक, अर्थात् कि अपराध कथित रूप से किए गए हैं

आपातकाल के दौरान उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में सामान्य कार्यालय एक अलग श्रेणी में स्थित हैं। आपातकाल का आवरण, इसलिए यह आरोप लगाया जाता है, इस तरह के धारकों को एक अनूठा अवसर प्रदान किया जाता है

कानून के शासन को नष्ट करने और राजनीतिक अपराधों को अंजाम देने के लिए कार्यालय समाज को। उस समूह से बाहर रह गए अन्य लोगों के पास न तो साधन थे और न ही

ऐसा करने का अवसर, क्योंकि उनके पास आने वाले अधिकार की कमी थी

आधिकारिक पद से। इस प्रकार, वे व्यक्ति जो विधेयक द्वारा अलग किए गए हैं

विशेष न्यायालयों के समक्ष विचारण के लिए सामान्य विशेषताएँ होती हैं और

जो लोग उस समूह से बाहर आते हैं, उनके पास वे नहीं होते हैं।

इसका मतलब यह नहीं है कि समूह से बाहर रहने वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं।

कभी महान मैग्नी के अपराध किए हों या नहीं किए हों

उनके सार्वजनिक कार्यालयों का शोषण करके व्यवहार करें। लेकिन उन अपराधों, अगर बिल्कुल भी,

मूल रूप से अलग प्रकार के होते हैं और आम तौर पर एक अलग गति होती है।

वैशन। सबसे पहले, पूरक का कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

जब आपातकाल लागू नहीं होता है तो मानव स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। द.

लोगों की स्वतंत्रता का दमन अपराधों को आसानी से करने में मदद करता है।

सार्वजनिक आलोचना दुर्व्यवहार के लिए एक शक्तिशाली निवारक है और जब वह दबा दिया जाता है, पता लगाने का कोई डर नहीं होता है। दूसरा, अपराध जो

असाधारण अवधि के दौरान किए जाने का आरोप है जैसे

आपातकाल की अवधि उनके डिजाइन में तिरछी और चयनात्मक होती है। उनका उद्देश्य। इन्हें आम तौर पर पकड़ने और स्थायी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

राजनीतिक शक्ति; और वे व्यापक रूप से राजनीतिक विपक्ष के खिलाफ निर्देशित हैं

नादियाँ। एक उच्च सार्वजनिक पद का धारक, जो सामान्य समय में,

रिश्वत लेने का उसे समृद्ध करने से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है।

स्वयं। यह, निर्विवाद रूप से, सर्वोच्च निंदा के योग्य है और

ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस तरह के अपराधों की सुनवाई भी तेजी से नहीं की जानी चाहिए सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के हित में। लेकिन वे अपराध हैं

राजनीतिक प्रेरणाओं के ताना-बाना से बुना नहीं गया। समान।

कानून को सभी पर एक ही स्थिति और विधायिका में लागू करना होगा

हानि या बुराई के स्तर को पहचानने के लिए स्वतंत्र है। संसदीय डेमो आरई:

विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

541

क्रेसी भारत में अपने कठिन दिनों को देखेगा जब कानून उन सभी अपराधियों के त्वरित मुकदमे का प्रावधान करेगा जो उनके द्वारा आयोजित सार्वजनिक पदों का दुरुपयोग करते हैं। सार्वजनिक जीवन में शुद्धता हर समय एक वांछित लक्ष्य है और सभी स्थितियों में, आपातकाल या कोई आपातकाल नहीं। लेकिन हम ऐसे नहीं बैठ सकते।

अति विधायिका और तत्काल वर्गीकरण को समाप्त करें

कम-समावेशन का आधार उस अंक पर कि उन अन्य लोगों को छोड़ दिया गया है स्पर्श किया गया, जब तक कि संवैधानिक प्रतिबंधों का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

इस संदर्भ में, इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है कि:

" यदि कानून संभवतः बुराई पर हमला करता है जहां इसे सबसे अधिक महसूस किया जाता है,

इसे उखाड़ फेंकना नहीं है क्योंकि अन्य उदाहरण भी हैं

कोई आवश्यकता नहीं है कि कानून को सभी में जोड़ा जाना चाहिए सी. एम. ब्रेसिंग शर्तें "।

(वेस्ट कोस्ट होटल कंपनी बनाम देखें। पारिश) (1)।

अगला बिंदु जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या वर्गीकरण

यह उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध रखता है जिसे विधेयक प्राप्त करना चाहता है। विधेयक का उद्देश्य उन अपराधों और अपराधियों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना है जो, जैसा कि हमने बताया है, एक एकल और विशेष वर्ग का गठन करते हैं। वर्गीकरण के आधार और विधेयक के उद्देश्य के बीच घनिष्ठ संबंध विधेयक के सामने से ही स्पष्ट है। जैसा कि विधेयक की प्रस्तावना के 5 वें पैराग्राफ में कहा गया है, सामान्य आपराधिक अदालतों से, काम की भीड़ के कारण, उचित रूप से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे विधेयक द्वारा विचार किए गए अभियोजन को तेजी से समाप्त कर दें। अदालतों में भीड़भाड़, बढ़ते बकाया और दिनचर्या को दर्शाने वाली आसान और असंबद्ध शिथिलता

हमारे न्यायालयों में मुकदमे समकालीन जीवन के सर्वविदित तथ्य हैं। वे विवाद की अनुमति देने के लिए बहुत स्पष्ट हैं। सेमिनार और संगोष्ठियाँ

जो लगता है उसे हल करने के तरीके और साधन खोजने में उत्सुकता से व्यस्त हैं

एक कठिन और निराशाजनक समस्या होना। इसलिए विधेयक न्यायसंगत है।
न्यायसंगत रूप से एक ऐसी विधि प्रदान करता है जिसके तहत अभियोजन इसके दायरे में आते हैं।

कार्यक्षेत्र को तेजी से समाप्त किया जा सकता है। यह कोई जवाब नहीं है कि त्वरित परीक्षण प्रत्येक परीक्षण की एक सार्वभौमिक आवश्यकता है।

प्रस्तावना के छठे पैराग्राफ का पाठ सच्चाई को दर्शाता है

खंड 4 (1) के तहत वर्गीकरण के आधार और ओ. बी. के बीच संबंध विधेयक का जे.
ई. सी. वह अनुच्छेद कहता है कि यह फ्रंक के लिए अनिवार्य है

संसदीय लोकतंत्र और उनके द्वारा बनाई गई संस्थाओं का गठन

या भारत के संविधान के तहत कि अपराधों का आयोग

प्रस्तावना में लाया गया यू. टी. के साथ न्यायिक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए

सबसे अधिक प्रेषण। यदि यह सच है, और हमें इसे सच मान लेना है, तो

अपराध उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए थे।

(1) 300 अमेरिका 379,400।

[1979] 2 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

542

आपातकाल की घोषणा की आड़ में भारत में कार्यालय और

लोकतंत्र के नाम पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों के मुकदमे को हमारे देश में लोकतंत्र के संचालन और हमारे संविधान द्वारा बनाई गई संस्थाओं के हित में अधिकतम प्रेषण के साथ समाप्त किया जाना चाहिए। इन आरोपों को न्यायोचित मानते हुए ये मुकदमे जितने लंबे समय तक चलते रहेंगे, लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अधिक बाधाएं होंगी, जो कि

आसान विकास का पौधा नहीं है। यदि विधेयक में जिन अभियोजनों की परिकल्पना की गई है, उन्हें 5 से 10 वर्षों के बीच सामान्य, आराम से चलने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें शुरू करने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। विधेयक के तहत अभियोजन की त्वरित समाप्ति विधेयक का दिल और आत्मा है।

इस प्रकार, दोनों परीक्षण तत्काल मामले में पूरे किए जाते हैं, अर्थात्, (1) वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित है जो अंतर करता है।

(2) उक्त विभेद का विधेयक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध है, अर्थात्, विधेयक के खंड 4 (1) के तहत की गई घोषणा के अनुसरण में अभियोजन की त्वरित समाप्ति।

यदि वर्गीकरण वैध है और इसका आधार एक उचित संबंध रखता है

विधेयक के उद्देश्य के साथ, अनुच्छेद 14 के तहत किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता है कि विधेयक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया जो इसकी शर्तों के भीतर आती है, सामान्य परीक्षणों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया की तुलना में कठोर या अधिक कठिन है। वर्गीकरण में अनिवार्य रूप से उन लोगों को अधीन करने की आवश्यकता होती है जो इसके भीतर नियमों और प्रक्रियाओं के एक अलग समूह के अधीन आते हैं, जो आमतौर पर सामान्य परीक्षणों पर लागू होने वाली प्रक्रिया की तुलना में अधिक अक्षम हो सकते हैं। हमारे विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न से संबंधित लगभग सभी निर्णयों में और जिनकी हमने समीक्षा की है, विशेष कानूनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया स्पष्ट रूप से और निर्विवाद रूप से उस प्रक्रिया की तुलना में अधिक कठोर थी जो अन्यथा परीक्षणों को नियंत्रित करती। लेकिन एक बार जब दोहरे परीक्षण के अनुप्रयोग द्वारा एक वर्गीकरण को बरकरार रखा जाता है, तो कठोर उपचार या नुकसानदेह प्रक्रिया के अधीनता इसकी प्रासंगिकता खो देती है, इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 14 के प्रयोजनों के लिए, असमान लोग असमान व्यवहार की शिकायत नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावों में से एक हमारे निर्णय के दौरान, अर्थात्, प्रस्ताव संख्या 11 में इस आशय का उल्लेख किया गया है कि "वर्गीकरण का तात्पर्य अनिवार्य रूप से उन व्यक्तियों के साथ भेदभाव करना है जो वर्गीकृत हैं और जो उस वर्ग के सदस्य नहीं हैं। यह एक वर्गीकरण का सार है कि वर्ग पर आम जनता पर पड़ने वाले कर्तव्यों और बोझों से अलग कर्तव्य और बोझ डाल दिए जाते हैं।

वास्तव में

वर्गीकरण का विचार ही असमानता का है, ताकि यह आरई के साथ चले:

विशेष न्यायालय विधेयक (चंद्रचूड़, सी. जे.) 543

यह कहते हुए कि केवल असमानता का तथ्य किसी भी तरह से संवैधानिकता के मामले को निर्धारित नहीं करता है। इसलिए, यह सूचीबद्ध करना अनावश्यक है, जबकि हम अनुच्छेद 14 पर हैं, विधेयक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और सामान्य प्रक्रिया के बीच अंतर के विभिन्न बिंदुओं को यह पता लगाने के लिए कि क्या पहला बाद वाले की तुलना में अधिक नुकसानदेह है। हम केवल इतना ही जोड़ेंगे कि विधेयक के कुछ प्रावधान, जिन पर हम वर्तमान में विचार करेंगे, विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किए गए अभियुक्तों पर सामान्य अदालतों के समक्ष मुकदमे के लिए रखे गए अभियुक्तों की तुलना में कुछ नुकसान डालते हैं, जबकि कुछ अन्य प्रावधान उन्हें कुछ लाभ देते हैं जिनसे दूसरों को वंचित किया जाता है।

यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं है

तत्काल मामला कि विधेयक इसे मनमाना और अप्रमाणित पर छोड़ देता है

विशेष न्यायालयों के समक्ष मुकदमे के लिए व्यक्तियों को चुनने और चुनने का केंद्र सरकार का विवेकाधिकार और बाकी को नियमित न्यायालयों में सामान्य प्रक्रिया द्वारा मुकदमा चलाने के लिए छोड़ देता है। अगर ऐसा होता तो

अनुच्छेद 14 के संदर्भ में यह जांच करना आवश्यक हो जाता है कि क्या विधेयकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया प्रक्रिया से अधिक कठिन है।

जो सामान्य परीक्षणों को नियंत्रित करता है। लेकिन विधेयक के तहत सरकार को महसूस किया जाता है

विचारण मंच के मामले में कोई विकल्प या विकल्प नहीं होने के कारण, यदि खंड 4 (1) की शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो अभियोजन पक्ष को विशेष न्यायालय में स्थापित किया जाना चाहिए। उस खंड द्वारा, यदि केंद्रीय सरकार

यह राय है कि प्रस्तावना में उल्लिखित अवधि के दौरान किसी अपराध के होने का प्रथम दृष्टया सबूत है -

ए

वह व्यक्ति जो भारत में सार्वजनिक या राजनीतिक पद पर था और प्रस्तावना में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त अपराध से अधिनियम के तहत निपटा जाना चाहिए, केंद्र सरकार

प्रत्येक मामले में उस प्रभाव के लिए एक घोषणा राशन बनाएगी जिसमें उसकी राय उपरोक्त है। इस प्रकार, अपेक्षित राय का गठन बिना किसी अपवाद के, प्रत्येक मामले में घोषणा करने के दायित्व पर सरकार पर डालता है,

जिसमें राय बनती है। घोषणा करने पर, खंड 5 के तहत अनिवार्य रूप से एक और परिणाम आता है। उस खंड में प्रावधान है कि खंड 4 (1) के तहत की जा रही घोषणा पर, विशेष अपराध के संबंध में कोई अभियोजन केवल विशेष न्यायालय में ही शुरू किया जाएगा। न केवल मुकदमा शुरू करने की कोई गुंजाइश नहीं है

उन मामलों में जो खंड 4 (1) के दायरे में आते हैं, लेकिन खंड 5 एक कदम आगे जाता है और यह प्रावधान करता है कि खंड 4 (1) में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में लंबित अभियोजन भी विशेष न्यायालय को हस्तांतरित किए जाएंगे। खंड 6, जो उसी अवधारणा का विस्तार है, यह प्रावधान करता है कि यदि किसी अपराध के संबंध में घोषणा की तारीख को, ऐसे अपराध के संबंध में अभियोजन में किसी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन, चाहे [1979] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

544

लंबित या निपटाया गया, अपील या पुनरीक्षण के किसी भी न्यायालय में लंबित है, उसे निपटान के लिए उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। संक्षेप में, यह विधेयक एक ही क्षेत्र में दो समानांतर न्यायिक आदेशों के अस्तित्व को बाहर करता है और प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित करता है कि इसके दायरे में आने वाले सभी अपराधों की सुनवाई केवल विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी और किसी अन्य अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा नहीं।

यह इन उद्देश्यों के लिए विचार करने के लिए एक और बिंदु छोड़ देता है

अनुच्छेद 14, जो अंतिम होने के बावजूद, महत्व के मामले में सबसे कम नहीं है। वह बिंदु प्रस्तावना में उल्लिखित तिथि, अर्थात् 27 फरवरी, 1975 की प्रासंगिकता से संबंधित है। विधेयक के औचित्य का गठन करने वाले कारण इसकी प्रस्तावना के आठ पैराग्राफ में निहित हैं, जिनमें से एक पैराग्राफ वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। इसमें कहा गया है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत कुछ जांच आयोगों की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा के संचालन के दौरान देश में उच्च सार्वजनिक या

राजनीतिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों और ऐसे अपराधों के साथ जुड़े अन्य लोगों द्वारा किए गए अपराधों के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अस्तित्व का खुलासा करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

इस पाठ की व्याख्या करते हुए, विद्वान सॉलिसिटर द्वारा आग्रह किया गया था

जनरल और श्री राम जेठमलानी ने कहा कि ज्यादातियों और अवैधताओं को बचाने की एक स्पष्ट प्रवृत्ति विशेष तिथि पर स्पष्ट हो गई। लोकसभा के एक सदस्य और तत्कालीन प्रधानमंत्री के बीच सदन में आदान-प्रदान किए गए प्रश्नों और उत्तरों की एक जोड़ी पर रिलायंस को उस विवाद के समर्थन में रखा गया था। लोकसभा की चर्चाओं के अनुसार

(5 शृंखला, खंड 48, पृष्ठ 258, दिनांक 27 फरवरी, 1975), दोनों के बीच यही हुआ:

" श्री जनेश्वर मिश्रा (इलाहाबाद): के बारे में?

मारुति? श्रीमती इंदिरा गांधी: कोई भ्रष्टाचार नहीं है

मारुति। होन के बाद से। सदस्य ने इसे उठाया है, मैं कह सकता हूं कि

पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया गया है; नहीं

गलत किया गया है; कोई विशेष अनुग्रह नहीं होना चाहिए, या है दिया गया, क्योंकि यह प्रधान मंत्री के साथ संबंधित है

तेर का बेटा।

मैं जो कह रहा था वह यह है कि हम भी उतने ही चिंतित हैं जितने किसी और के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अन्य निकाय। मैं अंदर नहीं जाना चाहता

विवरण। मैंने पहले चरण-दर-चरण क्रियाओं के बारे में बात की है।

हमने ले लिया है। मैंने यह सार्वजनिक सभाओं में कहा है और मैंने कहा है

नेताओं के साथ इस पर चर्चा की। लेकिन आज ऐसा लगता है कि बहुत

चयनात्मक प्रकार का अभियान या आरोप। भ्रष्टाचार कम नहीं होगा:

विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

545

इस तरह से जाओ। अगर असली इरादा भ्रष्टाचार को खत्म करना है,
यह हर समय इससे निपटने का एक ईमानदार तरीका होना चाहिए।
स्तर।

श्री श्यामनंदन मिश्रा: ईमानदारी का प्रमाण पत्र

आप से आना चाहिए? श्रीमती इंदिरा गांधी: बिलकुल नहीं "।

दावा है कि ज्यादातियों और अवैधताओं की रक्षा करने की प्रवृत्ति

इन उत्तरों के कारण स्पष्ट हो गया या कि विशेष

जवाबों ने एक नई जागरूकता पैदा की कि अपराधियों की जांच की जा रही थी

जिनका कर्तव्य उन्हें कानून के दायरे में लाना था, वे हमारे लिए बहुत नादान हैं।

स्वीकृति। यहाँ तक कि यह मानते हुए भी कि इसके लिए कोई विश्वसनीय आधार है

समान रूप से, उन व्यक्तियों का एक साथ समूह बनाना जिन पर कॉम होने का आरोप है

आपातकाल की अवधि के दौरान अन्य लोगों के साथ अपराध जो कम किए गए हैं
पूर्व में कुछ अपराधियों की जाँच में खुद को शामिल करने का आरोप

आपातकाल की घोषणा एक साथ जुड़ने के समान है,

समान वर्ग, ऐसे व्यक्ति जिनके पास सामान्य गुण नहीं हैं या

विशेषताएँ। यह निर्विवाद रूप से विधायिका के लिए उचित है कि
अवधि के दौरान मानव स्वतंत्रता का दमन

सोचिए कि इस

आपात स्थिति ने उच्च सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों को एक अवसर प्रदान किया
या

लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने के लिए गणना की गई। आधार है कि सस्पेन
सियोन, विशेष रूप से, पसंदीदा स्वतंत्रता इंजीनियरों की कठोर अवज्ञा

कानून और संविधान को समझना आसान है। यही कारण है कि अपराध

546

विस्तारित वर्गीकरण को उचित ठहराते हुए, परामर्श ने हमारा ध्यान आकर्षित किया

शाह जांच आयोग के कुछ निष्कर्ष (खंड I, मद 8, पृष्ठ 59 से 64) आपातकाल की घोषणा से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा सत्ता के कथित दुरुपयोग पर। वे निष्कर्ष, हमारे अनुसार, वर्तमान उद्देश्य के लिए बिंदु से परे हैं। हमारे सामने सवाल यह नहीं है कि आपातकाल की घोषणा से पहले किसी उच्च या निम्न व्यक्ति ने किसी अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग किया था या नहीं। सवाल यह है कि क्या, जिन लोगों पर आपातकाल से पहले अपराध करने का आरोप है, उन्हें उसी वर्ग में रखा जा सकता है, जिन पर आपातकाल की अवधि के दौरान अपराध करने का आरोप है। इस सवाल का जवाब नकारात्मक होना चाहिए।

तदनुसार हमारा विचार है कि वर्गीकरण के लिए प्रदान किया गया है

विधेयक के खंड 4 (1) द्वारा उस सीमित सीमा तक वैध है जिसके लिए केंद्र सरकार को उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा आपातकाल की अवधि के दौरान किए गए कथित अपराधों के संबंध में घोषणा करने का अधिकार है। द. वर्गीकरण अब तक अमान्य है क्योंकि इसमें 27 फरवरी और 25 जून, 1975 के बीच ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध शामिल हैं। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान वर्गीकरण के तहत उन अपराधों और अपराधियों के संबंध में कोई घोषणा नहीं की जा सकती है।

यह विधेयक के खंड 4 (1) द्वारा प्रदान किए गए वर्गीकरण की वैधता के संबंध में प्रश्न का निपटारा करता है। जिन लोगों को वर्गीकरण में गलत तरीके से शामिल किया गया है, उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उन पर विशेष अदालतों द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जहाँ तक उन लोगों का संबंध है जिन्हें सही ढंग से एक साथ समूहीकृत किया गया है, हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि चूंकि वर्गीकरण वैध है, इसलिए अनुच्छेद 14 के प्रयोजनों के लिए यह विचार करना अनावश्यक है कि क्या विधेयक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया से अधिक कठिन है। यह अवलोकन स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 के उद्देश्यों तक ही सीमित है। इसे सीमित करने का कारण यह है कि ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1) में बहुमत के फैसले में अंतर्निहित धारणा कि संविधान के कुछ अनुच्छेद विशेष रूप से विशिष्ट मामलों से संबंधित हैं, ए. के. गोपालन (उपरोक्त) को इस संबंध में स्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया गया था-आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ (2) में बहुमत द्वारा शासित, जिसे आम तौर पर बैंक राष्ट्रीयकरण मामले के रूप में जाना जाता है। शंभू नाथ में

सरकार बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।, (3) यह सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि निवारक निरोध के कानून को चाल से मिलना चाहिए। न केवल अनुच्छेद 21 और 22 बल्कि अनुच्छेद 19 (1) (डी) का भी। में -

(1) [1950] एस. सी. आर 88

(2) [1970] 3 एस. सी. आर. 530,578

(3) [1974] 1 एस. सी. आर. 1

आरई: विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

547

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1) हम में से एक, जे. भगवती, ने यह मत व्यक्त किया था कि कानून को अब वैध माना जाना चाहिए-यह तय किया कि

अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 19 को बाहर नहीं करता है और यह कि भले ही कोई कानून हो किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करना और

परिणामस्वरूप अनुच्छेद 21 द्वारा मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है, जहाँ तक कि यह किसी भी अधिकार को कम करता है या छीन लेता है।

अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार, चुनौती का सामना करना होगा उस लेख से। जिस विचार को बहुमत ने स्वीकार किया, वह यह है कि

के फाट III में निहित विभिन्न लेखों में वर्णित अधिकार

संविधान अधिकारों की अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन वे अंग हैं। एक एकीकृत संवैधानिक योजना। इस प्रकार यह सीमा से परे है

अब यह विवाद कि संविधान के भाग III के विभिन्न अनुच्छेदों को पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं माना जा सकता है।

उस दृष्टिकोण पर, यह कहना पर्याप्त नहीं है कि चूंकि वर्गीकरण

यह वैध है, इस पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या विधेयक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया से अधिक कठिन है। विशेष प्रक्रिया की कठोरता अनुच्छेद 14 के तहत उत्पन्न होने वाले विचारों में अप्रासंगिक होगी, क्योंकि वर्गीकरण वैध है (इंगित सीमा तक)। लेकिन जहां तक कोई विशेष प्रावधान आकर्षित होता है, विधेयक को संविधान के अन्य प्रावधानों को भी पूरा करना पड़ता है। यह सिद्धांत कि मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले

अनुच्छेद पारस्परिक रूप से अनन्य हैं और यह कि भाग III में कोई विशेष अनुच्छेद एक स्व-निहित संहिता का गठन करता है, यह जांच करना आवश्यक हो जाता है कि क्या विधेयक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया संविधान के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करती है।

अनुच्छेद 21 संविधान का एकमात्र अन्य प्रावधान है जो

इस संदर्भ में उपयुक्त है। इसमें प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1) में, यह माजो द्वारा आयोजित किया गया था: यह कि अनुच्छेद 21 द्वारा अनुध्यात प्रक्रिया "सही और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होनी चाहिए और मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं होनी चाहिए; अन्यथा, यह कोई प्रक्रिया नहीं होगी और अनुच्छेद 21 की आवश्यकता पूरी नहीं होगी"। इसलिए यह जांच करना अनिवार्य है कि क्या विधेयक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया न्यायसंगत और निष्पक्ष है या किसी भी मामले में मनमाना या दमनकारी है।

प्रो के खिलाफ अनंत प्रकार की शिकायतें की गई हैं।

विधेयक के दर्शन। उनमें से कुछ इतने असंगत हैं कि हम उन्हें सूचीबद्ध करना अनावश्यक समझते हैं। हम उनमें से कुछ का ही उल्लेख करेंगे। कई लोगों के नमूने के रूप में जो बनाए गए थे। यह आग्रह किया जाता है कि एक व्यक्ति डाल दे

(1) [1978] 2 एससीआर 621।

(1) [1978] 2 एस. सी. आर. 621,674

-

[1979] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

548

विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए धारा के लाभ से वंचित किया जाता है

439 दंड प्रक्रिया संहिता, जिसके अधीन कोई उच्च न्यायालय या

सत्र न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर सकता है; कि यह अनुज्ञेय है।

विधेयक के प्रावधानों के तहत सरकार को स्थिति चुनने के लिए विचारण जो अभियुक्त के लिए असुविधाजनक है, जिससे उसे इनकार किया जाता है

पुलिस; कि अभियुक्त को अदालतों के समक्ष मुकदमे के अधिकार से वंचित किया जाता है सजा की सीमित शक्तियों के साथ; कि वारंट प्रक्रिया निर्धारित करती है

विधेयक द्वारा अपराधों की सुनवाई के लिए, परिस्थितियों में, आवश्यकता है

कम बोझिल; कि विशेष न्यायालय द्वारा मृत्यु की अवधि, यदि कोई हो, की पुष्टि करने का कोई प्रावधान नहीं है, कि विधेयक

प्रत्येक मामले में अपील करने का अधिकार प्रदान करता है, जितना राज्य को अभियुक्त और इस प्रकार राज्य के अधिकारों का विस्तार करता है और अधिरोपित करता है

अभियुक्त पर बोझ के लिए अनावश्यक; जबकि अपराध संहिता

एन. ए. एल. प्रक्रिया में राज्य को इससे पहले अदालत की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करते हुए, बिली ऐसी कोई पूर्व शर्त नहीं लगाता है, और इसी तरह आगे भी।

हमने इन पर और इसी तरह के अन्य लोगों पर चिंता से विचार किया है।

शिकायतें और आशंकाएँ लेकिन हम उनमें कोई सार नहीं देखते हैं, सिवाय इसके कि बाद में संकेत दिया जाए। विधेयक के खंड 9 के अनुसार, विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए रखे गए अभियुक्त पर मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों के मुकदमे के लिए संहिता द्वारा निर्धारित बचाव पक्ष द्वारा मुकदमा चलाया जाना है। परीक्षण, अन्यथा निर्धारित किए जाने के अलावा, उक्त संहिता द्वारा शासित होना चाहिए। सैयद कासिम रजवी (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वारंट प्रक्रिया किसी भी अर्थ में अभियुक्त के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है। जहां तक जमानत का संबंध है, अभियुक्त के लिए इसकी मांग करना खुला है और उचित मामलों में, विशेष न्यायालय का विस्तार उचित होगा।

वह जमानत पर है। जहां तक मुकदमे की स्थिति का संबंध है, दुर्भावनापूर्ण धारणा बनाना और यह कहना कि एक असुविधाजनक मंच को जानबूझकर चुना जाएगा, अनुचित है। इसके अलावा, संहिता की धारा 177 से 189 वाले अध्याय XIII के प्रावधान, जो "जांच और परीक्षणों में आपराधिक न्यायालयों की अधिकारिता" से संबंधित हैं, विधेयक द्वारा बाहर नहीं किए गए हैं। वे प्रावधान मुकदमे की स्थिति के बारे में प्रश्न को नियंत्रित करेंगे। मृत्युदंड की पुष्टि के लिए प्रावधान के अभाव के बारे में शिकायत अवास्तविक है क्योंकि खंड 10 (1) के तहत, प्रत्येक

अभियुक्त को इस न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यह अधिकार किसी भी मायने में सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा की शुद्धता की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय से कहने के अभियुक्त के अधिकार से कम है। जहाँ तक अन्य शिकायतों का संबंध है, वे इस आरोप को सही ठहराने के लिए बहुत तुच्छ हैं कि विधेयक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अन्यायपूर्ण या अनुचित है। वास्तव में इस श्रेणी की अधिकांश अन्य शिकायतें सैयद कासिम आरई में अभियुक्त की ओर से की गई थीं:

विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

549

रज़ी और हबीब मोहम्मद (ऊपर) लेकिन उन्हें इस अदालत ने खारिज कर दिया था। प्रक्रिया में प्रत्येक परिवर्तन को अन्यायपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए और वास्तव में जैसा कि राव शिव बहादुर सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा गया था, जिसका अनुसरण भारत संघ बनाम सुकुमार पाइन में किया गया था, (1) अपराध करने के आरोपी व्यक्ति को किसी विशेष न्यायालय या किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा मुकदमा चलाने का कोई निहित अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कि जहां तक भेदभाव के रूप में कोई संवैधानिक आपत्ति है या किसी अन्य मौलिक अधिकार का उल्लंघन शामिल है। संजय गांधी में

बनाम भारत संघ, (2), हममें से एक, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा कि अपराधिक मुकदमे के किसी भी पक्ष को धीमी गति से न्याय करने का निहित अधिकार नहीं है। संविधान की अनदेखी किए बिना इसे लगातार ध्यान में रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय अवरोध।

यद्यपि ऐसा ही है, तथापि विधेयक के प्रावधान हमें तीन महत्वपूर्ण मामलों में निष्पक्ष और अन्यायपूर्ण प्रतीत होते हैं। सबसे पहले, विधेयक में मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में स्थानांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिस तरह से एक न्यायाधीश स्वयं का आचरण करता है, वह निकट पक्षपातपूर्ण हो सकता है, इस मामले में न्याय के हित के लिए आवश्यक होगा कि मामले की सुनवाई उससे वापस ले ली जाए। ऐसे अन्य मामले भी हैं जिनमें एक न्यायाधीश वास्तव में पक्षपाती नहीं हो सकता है और फिर भी अभियुक्त को परिचर परिस्थितियों के कारण एक उचित आशंका हो सकती है कि उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया जाता हुआ भी देखा जाना चाहिए। किसी अभियुक्त को किसी न्यायालय की अधिकारिता के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए मजबूर करना, जो वास्तव में पक्षपाती है या यथोचित रूप से पक्षपाती माना जाता है, प्राकृतिक

न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन है और निष्पक्षता से इनकार है। अभी भी ऐसे अन्य मामले हैं जिनमें समीचीनता या दोष है।

विषाक्तता के लिए एक मामले के हस्तांतरण की आवश्यकता हो सकती है, भले ही कोई पूर्वाग्रह शामिल न हो। उचित मामलों में परीक्षणों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान का अभाव हो सकता है

न्याय प्रदान करने के लिए स्थापित एक संस्थान के रूप में विशेष न्यायालयों में लोगों के विश्वास को कम करता है। दूसरी दुर्बलता जिससे विधेयक का प्रक्रियात्मक भाग प्रभावित होता है, वह यह है कि खंड 7 द्वारा, विशेष न्यायालयों की अध्यक्षता या तो उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश द्वारा की जानी है या एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कोई अपवाद नहीं है। जहाँ तक वैकल्पिक स्रोत की बात है

(1) [1966] 2 एस. सी. आर. 34,38

(2) ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 514।

[1979] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

550

संबंधित है, हम के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए उच्चतम सम्मान का मनोरंजन करते हैं उच्च न्यायालय और हम चिंतित हैं कि हमने अपने निर्णय में कुछ नहीं कहा है

इसे एक वर्ग के रूप में उन पर कोई भी आक्षेप लगाने के रूप में माना जाना चाहिए। उनमें से कुछ ने एक बार फिर वकीलों के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया है, कुछ ने

प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में, और उनमें से कई हैं

जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मांग। निसन्देह वे एक पर कब्जा करते हैं

समाज में सम्मान और सम्मान की स्थिति। लेकिन कोई अपने को बंद नहीं कर सकता।

संवैधानिक स्थिति पर नज़र है कि जबकि अनुच्छेद 217 द्वारा, एक बैठक

कुलर आयु में, सेवानिवृत्त न्यायाधीश विशेष के न्यायाधीश के रूप में अपना पद संभालेंगे। सरकार की खुशी के दौरान न्यायालय। आनंद का सिद्धांत है

न्यायिक स्वतंत्रता का विध्वंसक।

एक विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाला एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो प्रदर्शन करता है

शक्ति और स्वतंत्रता को सरकार द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है

और इसे उनकी नियुक्ति को समाप्त करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है

और जब वह पसंद करता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यदि नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जानी है

भारत में, नियुक्ति की समाप्ति के लिए भी इसी तरह के समझौते की आवश्यकता होगी

गुलशन। हम उस समर्पण से प्रभावित नहीं हैं। लेकिन, यह देते हुए कि

तर्क वैध है, परामर्श की प्रक्रिया की अपनी सीमाएँ हैं

और वे काफी प्रसिद्ध हैं। परामर्श करने की बाध्यता नहीं हो सकती है

अनिवार्य रूप से एक कार्यकारी पर एक चेक के रूप में कार्य करता है जो निर्धारित है

असुविधाजनक पदधारी को हटा दें। इसलिए हमारा मानना है कि

कि विधेयक का खंड 7 संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है

इस हद तक कि एक व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है

केवल परामर्श से विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ।

फिर भी एक और दुर्बलता जिससे निर्धारित प्रक्रिया

विधेयक में यह निहित है कि एकमात्र दायित्व जो खंड 7 पर अधिरोपित होता है - केंद्र सरकार एक व्यक्ति को अध्यक्षता के लिए नामित करती है

विशेष न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के लिए है। यह एक उचित स्थान नहीं है और परामर्श प्रक्रिया के नुकसान पर ध्यान देना कुछ हद तक शर्मनाक है, हालांकि, सुनी-

सुनाई बातों के अनुसार, यह कहा जा सकता है कि परंपरा के मामले में, यह दुर्लभतम मामलों में है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। लेकिन एक अभियुक्त के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को आशा की पवित्र अभिव्यक्तियों पर निर्भर नहीं किया जा सकता है, अतीत का अनुभव उन्हें कैसे सही ठहरा सकता है। यह आश्वासन कि परंपराओं को शायद ही कभी तोड़ा जाता है, एक आरोपी के लिए एक खराब सांत्वना है जिसका जीवन और सम्मान दांव पर है। वास्तव में, किसी को इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, न ही वास्तव में सरकार के दृष्टिकोण से, जैसा कि अभियुक्त आरई के दृष्टिकोण से है:

विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

551

और समाज की अपेक्षाएँ और संवेदनशीलताएँ। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि निष्पक्ष और अप्रदूषित न्याय के नाम पर, विशेष न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए समर्थन, जिसे मामलों के एक विशेष वर्ग की सुनवाई के लिए नामित किया जाना है, न केवल अभियुक्त बल्कि पूरे समुदाय के विश्वास को प्रेरित करे। का प्रशासन

न्याय का एक सामाजिक आयाम है और बड़े पैमाने पर समाज की इसमें हिस्सेदारी है।

निष्पक्ष और समान रूप से न्याय।

ये, हमारी राय में, से तीन प्रक्रियात्मक दुर्बलताएँ हैं

जिनसे विधेयक प्रभावित होता है और जो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं

प्रावधान, इस अर्थ में कि वे द्वारा निर्धारित प्रक्रिया बनाते हैं

अभियुक्त के साथ अन्यायपूर्ण और अनुचित कार्य करें।

सुनवाई के दौरान इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया

संदर्भ, जिसके बाद विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने एक राज्य दायर किया न्यायालय में
निम्नलिखित प्रभाव से:

" 1. कि पहले से ही लिखित प्रस्तुतियों के दौरान

दाखिल किया गया है, यह भारत संघ की ओर से तर्क दिया गया है कि रेफरी के तहत विधेयक में परिकल्पित परीक्षण की प्रक्रिया रेन्स अधिक उदार है और एक निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करता है।

2. कि विधेयक की प्रस्तावना में अंतिम पाठ में कहा गया है कि कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तन किए जा रहे थे जिसके द्वारा टालने योग्य देरी को बिना हस्तक्षेप किए समाप्त कर दिया जाता है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।

3. कि तर्कों के दौरान, कुछ टिप्पणियाँ इस माननीय न्यायालय द्वारा कुछ परिवर्तनों का संकेत दिया गया था जो निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित कर सकता है और अधिक विश्वास को प्रेरित कर सकता है विशेष न्यायालयों के कार्यकरण के बारे में जानकारी।

4. कि न्यायालय में कार्यवाही के आलोक में, सी. आर. सॉलिक्टर जनरल द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे सरकार के लिए।

5. कि सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सरकार इस सुझाव को स्वीकार करता है कि केवल उच्च न्यायालय का एक वर्तमान न्यायाधीश विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए न्यायालय की नियुक्ति की जाएगी। और यह कि सरकार इस बात से भी सहमत है कि नियुक्ति होगी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से किया जाए।

6. कि सरकार भी इस सुझाव से सहमत है कि उच्चतम न्यायालय को विशेष रूप से स्थानांतरण करने का अधिकार होगा एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में एक मामला, इसके बावजूद कि

विधेयक में अन्य प्रावधान ।

[1979] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

552

7. कि भारत सरकार ने सोली को अधिकृत किया है
महान्यायवादी उपरोक्त पर न्यायालय को एक बयान देंगे
पंक्तियाँ ।

एस. डी./-

एस. एन. कैकर

भारत के सॉलिक्टर जनरल 25-9-78

विद्वान महान्यायवादी ने हमें आश्वासन दिया कि सरकार
जैसा कि उल्लेख किया गया है, विधेयक में उचित परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है
ऊपर पैराग्राफ 5 और 6 में । यद्यपि हम प्रतिक्रिया की सराहना करते हैं
सरकार को यह याद रखना होगा कि उचित संशोधन
विधानमंडल द्वारा पारित किया जाना होगा । यह आश्वासन कि
सरकार द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे और यह संभावना है कि
वे विधायिका द्वारा पारित किए जा सकते हैं जो हमें निर्वहन से मुक्त नहीं कर सकते हैं
विधेयक पर घोषणा करना हमारा कर्तव्य है जैसा कि यह आज भी है । जब तक
विधेयक में तीन उल्लंघनकारी प्रावधान हैं जिनका हमने उल्लेख किया है
ऊपर से, प्रक्रिया अन्यायपूर्ण होने के कारण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करेगी ।
और अनुचित । अन्य आपत्तियाँ बिना किसी सार के हैं, विशेष रूप से

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और इस न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।
ये दोनों विधेयक के उत्कृष्ट, नहीं, बचत सुरक्षा उपाय हैं।

विधेयक में एक और प्रावधान है जिसका हमें उल्लेख करना चाहिए।

हम इस सवाल पर हैं। खंड 4 के उपखंड (1) में प्रावधान है -

केंद्र सरकार द्वारा घोषणा करना जबकि उप

खंड (2) में प्रावधान है कि "ऐसी घोषणा को प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा।

किसी भी अदालत में "। यद्यपि केन्द्रीय सरकार की राय

कि उपखंड (2) के प्रावधानों के बावजूद यह न्यायपालिका के लिए खुला रहेगा।
कम से कम इस न्यायालय द्वारा इंगित सीमाओं के भीतर समीक्षा

खुदीराम दास बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। (1) यह देखा गया था

उस मामले में हम में से एक, भगवती जे., के लिए बोलते हुए

न्यायालय, कि कानून की सरकार में "निरंकुश जैसा कुछ नहीं है

विवेकाधिकार न्यायिक समीक्षा से मुक्त है "। राय होनी चाहिए

सरकार द्वारा गठित, कम से कम कहने के लिए, तर्कसंगत और प्रामाणिक तरीके से।

हमारे सामने इस सवाल पर कुछ चर्चा हुई थी कि

क्या इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद के तहत अपने सलाहकार अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में दी
गई राय। 143 (1) इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद के अर्थ में घोषित कानून के रूप में संविधान
का प्रावधान बाध्यकारी है। 141 संविधान से। भविष्य के अवसर पर इस प्रश्न पर और अधिक
पूरी तरह से विचार करना पड़ सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस समय ऐसा हुआ है

(1) [1975] 2 एस. सी. आर. 832,845

आरई: विशेष अदालत बिल (चंद्रचूड़, सी. जे.)

इस संदर्भ में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को निर्धारित करने में खर्च किया गया खर्च व्यर्थ नहीं गया होगा। एस्टेट शुल्क विधेयक (1), यू. पी. विधान सभा (3) और सेंट जेवियर कॉलेज (*) के मामलों में यह विचार व्यक्त किया गया था कि सलाहकार राय में कानून की बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है।

अटॉर्नी में-ऑटारियो के लिए जनरल बनाम। अटॉर्नी-कनाडा के लिए महाधिवक्ता (1) प्रिंसीपल द्वारा यह भी कहा गया था कि न्यायालय द्वारा अपने सलाहकार अधिकार क्षेत्र में व्यक्त की गई राय का "विधि अधिकारियों की राय से अधिक कोई प्रभाव नहीं होगा"। दूसरी ओर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राम किशोर सेन बनाम. छबिलदास मेहता बनाम में भारत संघ (") और गुजरात उच्च न्यायालय। विधायी विधानसभा, गुजरात राज्य (6) ने यह विचार रखा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय अनुच्छेद के तहत है। 143 अनुच्छेद के अर्थ के भीतर उसके द्वारा घोषित कानून है। 141. मद्रास प्रांत में v. मेसर्स बोड्डू बैदन्ना (7) संघीय न्यायालय ने मध्य प्रांत मामले (8) में उसके द्वारा दी गई राय पर उसी तरह चर्चा की जैसे कोई बाध्यकारी निर्णय पर चर्चा करता है। हम दृश्य की ओर झुके हुए हैं

कि यद्यपि यह इस न्यायालय के लिए प्रश्न की पुनः जांच करने के लिए हमेशा खुला है

इसके द्वारा पहले से ही तय किया गया है और यदि आवश्यक हो तो अधिक नियम बनाएँ भारत के क्षेत्र में अन्य सभी न्यायालयों की तरह इसके द्वारा लिया गया है

वे इस बात से चिंतित हैं कि उन्हें इस द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से बाध्य होना चाहिए न्यायालय अनुच्छेद के तहत अपने सलाहकार अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में भी।

143 (1) संविधान से। हम भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे।

सेंट जेवियर्स कॉलेज (ऊपर) में रे, सी. जे. द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए कि भले ही राय सलाहकार अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में दी गई हो

बाध्यकारी नहीं हो सकता है, यह बहुत अधिक वजन का हकदार है। यह अजीब होगा।

कि किसी विवाद में कानून के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

दो निजी पक्षों के बीच इस मामले में सभी अदालतों पर बाध्यकारी होना चाहिए।

देश लेकिन सलाहकार राय किसी को भी बाध्य नहीं करना चाहिए, भले ही

जैसा कि तत्काल मामले में, यह सभी इच्छुक लोगों को नोटिस जारी करने के बाद दिया जाता है

पक्षकार, सभी संबंधित लोगों को सुनने के बाद जो सुनना चाहते थे,

और में उठाए गए प्रश्नों पर पूर्ण विचार करने के बाद

संदर्भ। लगभग सब कुछ, जो संभवतः पक्ष में आग्रह किया जा सकता है विधेयक का और उसके खिलाफ हमारे सामने आग्रह किया गया था और यह सोचने के लिए कि हमारे

राय व्यर्थता में एक अभ्यास है जो गहराई से निराशाजनक है। यह कहते हुए

यह, हम एक प्रतिष्ठित द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से अनजान नहीं हैं

(1) [1944] एफ. सी. आर. 317,320,332,341।

(2) [1965] 1 एस. सी. आर. 413,446-47।

(3) [1975] 1 एस. सी. आर. 173 201-202।

(4) [1912] ए. सी. 571,589

(5) ए. आई. आर. 1965 कैल 282।

(6) (1970) II गुजरात लॉ रिपोर्टर 729।

(7) [1942] एफ. सी. आर. 90

(8) [1959] एफ. सी. आर. 18.

17-

978 एससीआई/78 [1979] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

554

1

लेखक ने कहा कि यद्यपि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकार राय को उच्च प्रेरक अधिकार है, लेकिन यह अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर उसके द्वारा घोषित कानून नहीं है। (संवैधानिक कानून देखें)

भारत द्वारा

एच. एम. सीरवाई, दूसरा संस्करण, खंड II, पृष्ठ 1415, पैरा 25.68)।

हमने टचस्टोन पर विशेष न्यायालयों के निर्माण को बरकरार रखा है

संविधान से। हमने यह भी विचार व्यक्त किया है कि विशेष न्यायालयों में उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, अनुच्छेद 21 की आवश्यकता को पूरा करेगी। लेकिन हम उस अवलोकन का विरोध नहीं कर सकते जो इस तर्क के दौरान किया गया था कि उच्च न्यायालयों को विधेयक के तहत मामलों की सुनवाई करने के लिए अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश करने से, परिस्थितियों में, हर दृष्टिकोण से सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने विवेकाधिकार पर अपने न्यायालयों के न्यायाधीशों को विशेष मामले सौंपेंगे और आवंटित करेंगे, जैसा कि वे अपने कार्य की सामान्य दिनचर्या में करते हैं। देरी से बचने और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विधेयक के तहत किसी मामले या मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायाधीश को कोई अन्य काम नहीं सौंपा जा सकता है। यह केंद्र सरकार द्वारा किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए किसी विशेष न्यायाधीश के नामांकन को रद्द कर देगा। कानून पूरा जीवन नहीं है और किसी कार्रवाई का औचित्य, हालांकि निर्णय लेने के लिए न्यायालय के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए पैरा-माउंट विचार का विषय होना चाहिए जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करना चाहते हैं। न्यायालय पक्षपात के आरोप को जोखिम में डालने का जोखिम भी नहीं उठा सकते हैं और कोई भी न्यायाधीश नहीं चाहता कि उसके बारे में यह कहा जाए कि उसे सरकार द्वारा किसी विशेष व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष रूप से नामित किया गया था। समुदाय को न्यायपालिका में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए, जिसे न केवल संवैधानिक मामलों पर बल्कि कई अन्य मामलों पर भी निर्णय लेना होता है, जिसमें कानून आम आदमी के जीवन को कई बिंदुओं पर छूता है। जैसा कि प्रो. फिनर ने 'द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट' में कहा है। 151-152) . " भीड़ सूक्ष्मता से भेदभाव नहीं करती है, और जब यह एक चीज के लिए अविश्वास करता है तो यह दूसरे के लिए अविश्वास कर सकता है, हालांकि मामले अलग-अलग होते हैं। हमारे विद्वान भाई, जे. शिंगल द्वारा इस संबंध में की गई गहन विचारशील टिप्पणियों पर सरकार के हाथों सबसे सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

अंत में, संदर्भ का हमारा उत्तर इस प्रकार है:

(1) संसद के पास विधायी क्षमता है -

विशेष न्यायालयों का निर्माण करना और यह प्रावधान करना कि एक अपील होगी

विशेष न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के अधिकार के अनुसार

विधेयक के खंड 4 (1) के तहत घोषणा करना।

सुप्रीम कोर्ट तक। विधेयक के खंड 2 और 10 (1)

इसलिए, संसद के विधायी समूह के भीतर हैं।

टेंस; आरई:

विशेष अदालत बिल (कृष्णा अय्यर, जे.)

555

(2) के खंड 4 (1) में प्रदान किया गया वर्गीकरण

विधेयक उस हद तक वैध है जिस हद तक केंद्रीय सरकार

के संबंध में घोषणा करने का अधिकार है

अवधि के दौरान किए गए कथित अपराध

उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा आपातकाल

भारत में कार्यालय। जिन लोगों पर अपराध करने का आरोप है

आपातकाल की घोषणा से पहले अपराध नहीं हो सकता है

वैध रूप से उन लोगों के साथ समूहीकृत किया जाए जिन पर आरोप लगाया गया है

आपातकाल की अवधि के दौरान अपराध किए हैं।

इसलिए यह केंद्र सरकार के लिए सक्षम नहीं है।

विधेयक के खंड 4 (1) के तहत घोषणा करना।

उन व्यक्तियों का समूह जिन पर अपराध करने का आरोप है

27 फरवरी 1975 और 25 जून 1975 के बीच।

(3) के परीक्षण के लिए विधेयक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

ऐसे अपराध जिनके संबंध में एक घोषणा वैध हो सकती है

के खंड 4 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया

विधेयक निम्नलिखित को छोड़कर न्यायसंगत और निष्पक्ष है।

मुद्दे:

(क) विधेयक के खंड 7 में प्रावधान, जिसके तहत

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है।

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त;

(ख) खंड 7 में वह प्रावधान जिसके तहत नियुक्ति की जाती है।

विशेष न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है।

केंद्र सरकार के परामर्श से लेकिन

मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना

भारत; और

((c) किसी मामले के हस्तांतरण के लिए प्रावधान का अभाव

एक विशेष न्यायालय से दूसरे में।

(4) यह विधेयक अन्य सभी मामलों में वैध और संवैधानिक है।

कृष्णा आयर, जे.-एक्सनेंस का नोट नहीं बल्कि एम्फा का एक स्ट्रोक

सिस्ट कुछ बुनियादी बातों तक सीमित इस अलग राय को जोड़ने का मेरा मुख्य इरादा है। शुरुआत में यह स्पष्ट करना उचित है कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए गए सभी कानूनी निष्कर्ष मेरी सहमति का आदेश देते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मुद्दों पर, मेरा अनुपात अलग है, जो अधिक कठोर और शायद अधिक कठिन लगता है। हालांकि, अंतिम प्रवाह और काफी सामंजस्य ने मेरे कवरेज को कम कर दिया। सर्वसम्मति की कीमत मौनता नहीं है जहां व्यक्तिगत अभिव्यक्ति विशिष्ट योगदान दे सकती है।

शुरुआत में ही, मेरे सामाजिक-कानूनी का एक असाधारण उच्चारण।

ऐसा परिप्रेक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है जिसका संवैधानिक प्रभाव हो। मैं उधार देता हूँ।

इस [1979] 2 एस. सी. आर. के पीछे सामाजिक न्याय की सीमा नीति को विवेकपूर्ण सहमति।

556

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिल। जैसा कि मैंने इसे पढ़ा, यह माप एक की भ्रूण अभिव्यक्ति है आवश्यक
विधायी परियोजना, जो अगर पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो यह काफी काम करेगी।

बाध्यकारी अपराधी के माध्यम से पकड़ने की ओर कम ब्रेक-थ्रू

प्रक्रिया, भारतीय सार्वजनिक और राजनीतिक डेक के उच्च निवासियों,

जो व्यवहार में 'अच्छूत' और 'दुर्गम' बने हुए हैं। कानून के शासन के लिए '। ऑपरेशन क्लीन-अप
'एक' पूर्णता भक्त है।

गंभीर अनुभव है कि कानून उन लोगों के खिलाफ टेरोरम में बनाए गए हैं जो लंबे
समय तक शीर्ष शक्ति गुट कागजी बाघ साबित होते हैं। द.

लोकपाल या प्रहरी के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति जो सत्ता में हैं, अभी या
पहले, और सूचना तक कानूनी पहुंच प्रदान करते हैं

एड नागरिक प्रतिरक्षा के साथ शिकायत करने के लिए मौजूद नहीं है, सभी के बावजूद

अनुमानों के खिलाफ राजनीतिक अनुच्छेद कारों की नाराजगी और प्रति

उच्च स्तरों द्वारा संस्करण। कानून वही है जो कानून करता है, न कि कानून। कहते हैं
और शब्द और कर्म के बीच नैतिक अंतर लोगों के लिए खतरा है

जीवन और कानून में विश्वास। और फिर, त्रासदी-लोकतंत्र एक बन जाता है

हताहत।

एक विकासशील देश के लिए हमारे समय का सबसे बड़ा आघात

तत्काल लेकिन उत्तेजक अनिवार्यताएँ, निराशाजनक हैं, फिर भी मर जाते हैं-कठिन, गरीबी

जनता और लोकतांत्रिक, फिर भी भ्रष्टाचार-ग्रस्त, सत्ता के जीवन का तरीका

चालकों। वे एक साथ मिलकर घोर दुर्व्यवहार पैदा करते हैं व्यक्तिगत उन्नति,
एक्सपोजर का दमन और कई अन्य

पैरा-राजनीतिक जोड़-तोड़ करने वाले और नौकरशाहों को उकसाने वाले। और यह कानून का शासन लंगड़ा या भौंकता है लेकिन कभी काटता नहीं है। एक अनाम कवि

इस प्रणालीगत अवहेलना के सामाजिक आयाम को भद्दे तरीके से पेश किया गया

इंसाइट:

" कानून पुरुष और महिला दोनों को बंद कर देता है।

जो आम से हंस चुराता है,

लेकिन बड़े अपराधी को छोड़ दें।

जो

हंस से आम चोरी करता है "।

तीसरी दुनिया की सेटिंग में 'शिखर' अपराधों का प्रभाव अधिक है

बोधगम्य सामाजिक वैज्ञानिकों के रूप में वाटरगेट सिंड्रोम से भी भयानक
दिया है। भ्रष्टाचार और दमन-ऐसी स्थिति में चचेरे भाई

नकाब उतार

अवस्थाएँ-विकासात्मक प्रक्रियाओं का अपहरण। और, लंबे समय में, अंतराल
राष्ट्रीय प्रगति का अर्थ है संविधान में लोगों का विश्वास कम करना।

राष्ट्रीय का अर्थ है सामाजिक न्याय। और इसलिए, पता लगाने और देने के लिए

इन भारी-भरकम अपराधियों के लिए छोटी छूट जो अक्सर सार्वजनिक नैतिक भार उठाने और
बहुआयामी घोषणापत्रों द्वारा लोगों को गुमराह करते हैं

आरई है: विशेष अदालत बिल (कृष्णा अय्यर, जे.)

557

विधेयक द्वारा आंशिक रूप से शुरू किया गया एक तत्काल विधायी मिशन

चर्चा करें। ऐसे अति-अपराधियों को शीर्ष पदों पर दंडित करना, सीलिंग

कानूनी पलायन मार्गों और विलंबकारी रणनीतियों को बंद करना और उन्हें लाना

उच्च गति और प्रारंभिक अंतिमता के साथ न्याय के लिए, एक इच्छा व्यक्त की गई है अतीत में आयोगों और समितियों द्वारा व्यर्थ और एक मंद है

कानून के शासन की गतिशीलता का सिद्धांत। यह बिल, उम्मीद है लेकिन आंशिक रूप से, लोगों के त्यागपत्र देने वाले सनकीपन के विपरीत नई जमीन तोड़ता है

कि सभी उच्चाधिकार प्राप्त जांच, रिपोर्ट और सिफारिशें

विधायी और न्यायिक निरर्थकता में अंत, कि ये सभी बहादुर अभ्यास

लेकिन ध्वनि और रोष कुछ भी नहीं दर्शाता है, कि 'हमेशा की तरह व्यवसाय' है

सार्वजनिक व्यवसाय की हस्ताक्षर धुन, इससे पहले, यहाँ और इसके बाद।

इसलिए इस सामाजिक न्याय उपाय को नैतिक सिद्धांत में मेरी व्यापक सहमति है।

और संवैधानिक वर्गीकरण में, गंभीर दुर्बलताओं के अधीन जिनसे यह पीड़ित है क्योंकि विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने संक्षिप्त रूप से स्केच किया है।

क्या यह उपाय अपराधिक राशि की बीमारी को प्रभावी ढंग से ठीक करेगा मित्त्र भविष्य को बताने के लिए है।

यह सब एक पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। मुझे पूर्ण तर्क में सामने आने दें।

मेरे शोध प्रबंध में कहा गया है कि यह विधेयक, जहां तक अच्छा है, अब तक खराब है। जैसा कि यह नहीं जाता है-हालांकि एक व्यावहारिक अपवाद द्वारा सहेजा गया मैं प्रस्तुत करूंगा ली समझाएँ। जहाँ प्रस्तावित कानून में पूर्व और उत्तर शामिल नहीं हैं।

:

जेन्सी क्राइम-उच्च कोष्ठक में काम करने वाले और केवल 'एमर' चुनते हैं सामान्य 'अपराधी, इसका सौम्य उद्देश्य शायद एक गुप्त आवरण बन जाता है-!

पहले और बाद में अपराधियों की तरह। एक अल्पकालिक उपाय

एक बारहमासी खतरे का सामना करना न तो एक तार्किक कदम है और न ही राष्ट्रीय आधार है

फिल्टरिंग। वर्गीकरण, यदि मैं अपने निष्कर्ष का अनुमान लगा सकता हूँ, तो यह है

संवैधानिक टूटने के कगार पर-उस समय नीचे और बन जाता है

अनुच्छेद के हमले के लिए लगभग असुरक्षित। 14

न्यायालय की सलाहकार राय मांगी जाती है, सामाजिक नीति पर नहीं लेकिन
संवैधानिकता पर। यहाँ, हालांकि, यह मेरा बहुत समर्थन है विधेयक की मूल
नीति, प्रस्तावक का स्पष्ट उद्देश्य,

उपाय का सही सिद्धांत और कानून की तत्काल प्रासंगिकता

लेशन-सार्वजनिक रूप से शीर्ष अपराधियों के लिए निश्चित, फिर भी उचित न्याय और

राजनीतिक जीवन-जो मुझे कुछ प्रावधानों की आलोचना करने के लिए मजबूर करता है
अस्पष्ट करने के लिए बहुत बुनियादी आधार। मैं अनुमान से शुरू करता हूँ

इस प्रकृति का एक अधिनियम, द्वारा उल्लिखित प्रमुख परिवर्तनों के साथ

अनुच्छेद के साथ टकराव को रोकने के लिए मुख्य न्यायाधीश। 21 और व्यापक कवरेज के
साथ

अनुच्छेद के साथ समझौता करना। 14, लंबे समय से बकाया है और, यदि इसमें पारित
किया जाता है

कानून और अनिवार्य रूप से लागू किया गया, आंशिक रूप से डूबे हुए विश्वास को बचा सकता
है लोकतंत्र में सामान्य समुदाय की क्षमता-कार्रवाई में, पहले से ही

स्वतंत्रता के बाद से तिरछे के लिए सत्ता के विकृति द्वारा नैतिकता प्राप्त

आवधिक संसदीय बहसों द्वारा प्रमाणित उद्देश्य और कई

आयोग की रिपोर्ट अभी भी धूल जमा कर रही है।

शानदार।

[1979] 2 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेरी बात को स्पष्ट करने के लिए, थोड़ा विभाजन की आवश्यकता है। देव

एक राज्य में, जो अर्थव्यवस्था को निर्देशित करता है, निवेश का अर्थ है सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अभूतपूर्व पैमाने पर सार्वजनिक व्यय और यह राष्ट्रीय

आवश्यकता को कभी-कभी गुप्त रूप से व्यक्तिगत अवसर में बदल दिया जाता है।

उच्च पदों पर बैठे लोगों के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है। कानून के यथार्थवादी शासन को गुमराह पुरुषों के हाथों में निर्देशित मिसाइलों की हानिकारक क्षमता के साथ माना जाना चाहिए, खासकर जब

पीड़ित एक 'नरम' राज्य है, और उसे खतरे का सामना करने के लिए उठना चाहिए और आदमी को अपराधी को पकड़ना चाहिए, चाहे वह कभी भी इतना ऊँचा हो। मैंने इस तर्क को सही ठहराने के लिए पर्याप्त कहा है कि ये अपराधी संवैधानिक विधेयक को एक अलग वर्ग के रूप में पूरी तरह से भरते हैं जो त्वरित अभियोजन और उच्च न्यायिक एजेंसियों द्वारा अंतिम दंड का हकदार है यदि तीसरी दुनिया के देशों में जनता के बीच संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक विकास में गिरावट को बहाल किया जाना है। विधेयक की प्रस्तावना इस अभिविन्यास का खुलासा करती है और विधेयक के प्रस्तावक श्री राम जेठमलानी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इसका संकेत दिया है।

व्यावहारिक समूहीकरण के मार्ग में कोई भी विद्वान पांडित्य बाधा नहीं बन सकता है

उच्च पदस्थ पदधारियों के लिए अलग से, उच्च गति की आपराधिक कार्रवाई के उद्देश्यों के लिए जल्दी निर्णायकता के साथ निवेश किया जाता है और उच्च स्तरीय अदालतों द्वारा इसकी जांच की जाती है। विधेयक का अंतर अटूट रूप से ध्वनि देता है। और इस तरह के स्वच्छ उपक्रम को आगे बढ़ाने में विफलता कानून के शासन और जीवन के शासन के लिए एक झटका हो सकता है और लाखों लोगों के बीच लोकतंत्र के संकट को गहरा कर सकता है-जो लोग हमारे राष्ट्र को बनाते हैं-जो आज भी बड़े पैमाने पर निराश हैं। इसलिए यह समय है, अगर शांति पूर्ण परिवर्तन संवैधानिक योजना है, तो सत्ता के गढ़ों में आपराधिक लोगों को त्वरित और निर्णायक रूप से उजागर करने और दोषी ठहराने के लिए पूर्व-सशक्त कदमों से शुरुआत की जाए-आर्थिक अपराधियों का एक विशेष वर्ग जिसमें नौकरशाही और बड़े व्यवसाय के उत्प्रेरक हों, जैसा कि हाल ही में आयोग की रिपोर्टों में प्रचलित रूप से चित्रित और स्पष्ट किया गया है। वर्गीकरण संबंधी वर्णन का ऐसा सरल, सामाजिक तार्किक सार है जो अनुच्छेद के समतावादी विवेक को संतुष्ट करता है। 14. सुरक्षात्मक कवच के रूप में सार्वजनिक पद के साथ मास्टर-अपराधियों और दागी सीज़र का एक त्वरित उदाहरण बनाने से बेहतर डिजाइन-इंजीनियरिंग क्या हो सकती है?

कानून के शासन की जन-उन्मुख योजना में सार्वजनिक शक्ति की मूलभूत मानसिक गतिशीलता-महान विश्वास और निश्चित रूप से लेखाकार-उच्च स्थान पर है।

मेरा मानना है कि इस सामान्यीकृत संस्करण में एक उचित वर्गीकरण है।

इस विधान में समावेश निहित है, लेकिन आगे यह प्रयास करें कि यह कम समावेशी और इसलिए असमान होने के करीब है। क्योंकि यह एक स्पष्ट रूप से व्यापक सिद्धांत का एक संक्षिप्त प्रक्षेपण है कि उच्च अपराधी से अपराधिक कानून द्वारा त्वरित गति से निपटा जाएगा ताकि आम आदमी को पता चल सके कि जब सार्वजनिक शक्ति का निजी लाभ या व्यक्तिगत बदला लेने के लिए दुरुपयोग किया जाता है तो कानून का शासन तेजी से सुधर जाएगा:

विशेष अदालत बिल (कृष्णा अय्यर, जे.)

559

उन्हें नीचा दिखाएँ और लोकतांत्रिक में लोगों के विश्वास को बहाल करें

कानून के अनुसार त्वरित न्याय के माध्यम से संस्थान। इस मायने में

कि बड़ी प्रशासनिक शक्तियों वाले बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर त्वरित प्रेषण के साथ मुकदमा चलाया जाएगा और दोषी होने पर दंडित किया जाएगा। त्वरित परीक्षण

और सभी अपराधिक मामलों में शीघ्र सजा की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन, कच्चा यथार्थवाद बताता है कि धीमी गति की मंदी की स्थिति में

न्याय, अदालतों के साथ डॉकेट द्वारा दबा हुआ, तेजी से मुकदमे और त्वरित सजा के लिए एक विशेष मामला है जहां अपराधी अदालत में बैठता है। प्रशासनिक पिरामिड के शीर्ष पर। निश्चित रूप से न्याय, एक साल बाद

लंबे समय तक चलने वाली कमीशन कार्यवाही में शायद ही कभी दोषसिद्धि होती है

जब मनुष्य की यादें गंभीर अपराधों को भूल गई होंगी, अगर

कानून के शासन में किसी भी प्रतिबद्ध और पुरुषों का विश्वास होगा

दुरुपयोग के घोर अपराधों के विश्वसनीय आरोपों के बावजूद शीर्ष अधिकारियों को इस तरह के पदों पर बने हुए देखकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। द.

आम लोग इन पसंदीदा प्रजातियों के भाग्य को देखते हैं जब

वे आपराधिक कानून के मानदंडों का उल्लंघन करते हैं और यदि उन्हें तुरंत दंडित नहीं किया जाता है, तो वे व्यवस्था में ही विश्वास खो देते हैं। 'कानून के तहत समान न्याय' के बारे में सनकीपन 'मुझे आदमी दिखाएँ और मैं आपको कानून दिखाऊंगा'। लोकतांत्रिक प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्ता का व्यवसाय-सार्वजनिक शक्ति-व्यापार नहीं कर रहा होगा।

इस क्षेत्र में सामाजिक दर्शन और कानून का दर्शन जोरदार है।

यह आवश्यक है कि सार्वजनिक शक्ति के कार्यालय, विशेष रूप से गरीबी वाले देश में, व्यक्तिगत लाभ की कार्यशाला नहीं होगी। तत्काल सुधार प्रक्रिया अदालत है, न कि कुछ वर्षों में एक बार होने वाला मतदान।

तुम हो जाओ।

कभी भी इतना ऊँचा कानून आपको देखेगा, आपको पकड़ेगा, दोषी पाए जाने पर आपको दोषी ठहराएगा और वह भी, जल्दी लेकिन निष्पक्ष रूप से।

महत्वपूर्ण परीक्षा यह है कि 'सारी शक्ति एक विश्वास है', इसके धारक 'जवाबदेह' हैं।

इसके अभ्यास 'के लिए' लोगों से, और लोगों के लिए, सभी स्रोत, और सभी का अस्तित्व होना चाहिए। इस उच्च और एकमात्र मानक के अनुसार विधेयक को नैतिक रूप से विफल होना चाहिए यदि यह गैर-आपातकालीन अपराधियों को छूट देता है जिनके बारे में पूर्व आयोग की रिपोर्ट, जो अब आधिकारिक कबूतर के छेद में सो रहे हैं, गवाही देते हैं।

और

भविष्य की आयोग रिपोर्ट (कौन जानता है?) समय पर गवाही दे सकते हैं।

में।

इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में, आपातकाल एक महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और

विधेयक 27 फरवरी, 1975 के ऑपरेशन से पहले इसे लगभग मान्यता देता है, जब कोई 'आपातकाल' नहीं था। अगर 'आपातकाल' महत्वपूर्ण मानदंड था तो पहले की तारीख क्यों?

यह आम जानकारी है कि वर्तमान में हमारे देश में आपराधिक अदालतें हैं।

धीमी गति में उत्कृष्टता प्राप्त करें। प्रक्रिया विलंबित होती है, डॉकेट भारी होते हैं, यहां तक कि प्रक्रिया की सेवा में भी देरी होती है और, और भी अधिक परेशान करने वाली, अपीलों और संशोधनों और पर्यवेक्षी न्यायशास्त्र पर अपीलें होती हैं।

2 एस. सी. आर. को नहीं, बल्कि अभियोजनों की त्वरित समाप्ति, चौंका देने वाली और चौंका देने वाली है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

560

न्यायिक प्रक्रिया की बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में व्याख्यान द्वारा प्रशासन द्वारा स्वयं देरी में योगदान की बात करें। कई वर्षों में फैले संसदीय और पूर्व-विधायी अभ्यासों ने आपराधिक प्रक्रिया के मौलिक सरलीकरण और सुव्यवस्थित करने के लिए शायद ही कुछ किया हो।

वस्तुतः पुनः अधिनियमित किया गया, मामूली उत्परिवर्तनों के साथ, पुराना कोड फॉरेंसिक प्रवाह को बहुत धीमा और कानून में अंतर्निहित रखने के लिए उत्तरदायी बनाता है। अदालतें छल के लिए संसद द्वारा बनाई गई संहिता की तुलना में कम दोषी हैं और सरकारें न्यायपालिका को सुचारू रूप से काम करने के लिए बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने या देरी करने की दोषी हैं। न्याय हमारी योजना में एक सिंडराला है। फिर भी, वी. वी. आई. पी. अभियुक्त को नियमित रूप से विलंबित करने वाली कानूनी प्रक्रिया से निपटने के लिए छोड़ना अंतहीन देरी के सामने आत्मसमर्पण करना है।

एक अपरिहार्य एविल। इसलिए, हमें पूर्ण प्रक्रियात्मक समानता के बारे में सूक्ष्म नहीं होना चाहिए और विशेष स्थितियों से प्रभावित होने वाली नवीन प्रक्रियाओं में रचनात्मक होना चाहिए।

लेकिन अनुच्छेद का मुहावरा। 14 त्रुटिहीन है। शक्ति की स्थिति

कथित अपराधी, कथित अपराध की प्रकृति बनाम जनता का विश्वास और त्वरित मुकदमेबाजी की अंतिमता की अनिवार्य आवश्यकता, बताने वाले कारक हैं। हर अंतर एक अंतर नहीं है। ' त्वरित सुनवाई '

'देश में उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों और ऐसे अपराधों से जुड़े अन्य लोगों द्वारा किए गए सार्वजनिक प्रकृति के अपराध' मामले का केंद्र है।

आइए हम 'आपातकाल' पर बारीकी से नज़र डालते हैं, जिन बुराइयों को इसने जन्म दिया और

उचित उप-वर्गीकरण। कार्यवाही से आने वाली जानकारी उच्चाधिकार प्राप्त न्यायिक आयोगों के एक समूह की जानकारी और रिपोर्ट से पता चलता है

कि उस शांत दौर के दौरान, कई लोगों को चौंकाने वाले व्यवहार का सामना करना पड़ा। में। प्रस्तावना के शब्द, नागरिक स्वतंत्रता को एक महान पूर्व में वापस ले लिया गया था तंबू, लोगों के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, सख्त प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और न्यायिक शक्तियों में कटौती की गई काफी हद तक।

आगे बढ़ने से पहले, विधायी और न्यायिक सीमा जैसा कि मूर्ति वॉच वर्क्स में बताया गया है, इसे स्पष्टता के साथ देखा जाना चाहिए। आदि। वी. द अस्ट. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि के कलेक्टर (1)

" प्रत्येक भेदभाव भेदभाव नहीं है। लेकिन

वर्गीकरण को तभी बनाए रखा जा सकता है जब यह प्रासंगिकता पर आधारित हो।

सियाल वाले। संवैधानिक मानक जिसके द्वारा पर्याप्त भेद की भावना जो वर्गीकरण के लिए एक वैध आधार बनाती है

यह मापा जा सकता है, बार-बार कहा गया है

(1) [1974] 3 एस. सी. आर. 121 130 पर।

आरई: विशेष अदालत बिल (कृष्णा अय्यर, जे.)

561

अदालतें। यदि यह किसी ऐसे अंतर पर निर्भर करता है जो उचित और न्यायपूर्ण हो।

जिस उद्देश्य के लिए यह प्रस्तावित किया गया है, उसके संबंध में यह संवैधानिक है।

राष्ट्रीय। इसे अलग तरह से रखने के लिए, साधनों में संबंध होना चाहिए।

उचित आधार पर वर्गीकरण के लिए राज्य और क्या है
उचित व्यावहारिक विवरण और विभिन्न प्रकार का प्रश्न है।

कारक जो अदालत अनिच्छुक और शायद अवैध होगी

जाँच करने के लिए। इस अपूर्ण संसार में भी पूर्णता
समूहीकरण एक ऐसी महत्वाकांक्षा है जिसे शायद ही कभी पूरा किया गया हो। इसमें

संदर्भ में, हमें बीच के संबंध को याद रखना होगा

बचाव में सरकार के विधायी और न्यायिक विभाग

वर्गीकरण की वैधता का खनन। एक शक्ति।

अत्यधिक व्यापक होने और विविध समझ पर आधारित होने के लिए वर्गीकृत करना

कार्यकारी व्यावहारिकता का उपहास, न्यायपालिका जल्दबाजी नहीं कर सकती
जहाँ विधायिका भी युद्धरत तरीके से चलती है।

हालांकि, मूल सवाल यह है कि वर्गीकरण के आधार के रूप में आपातकाल का कानून के उद्देश्य से
क्या उचित संबंध है।

यह हमें दो पहलुओं पर ले जाता है जो सावधानीपूर्वक जाँच के योग्य हैं,

वर्गीकरण के लिए किन विशेष कारकों पर भरोसा किया जाता है और क्या है

विधायी लक्ष्य और फिर वह गंभीर मुद्दा-सहसंबंध शर्त क्या है

उन दोनों को? साधनों और उद्देश्यों का अभिन्न योग इसका सार है

वैध वर्गीकरण। एक उत्कृष्ट वर्गीकरण के लिए योग्य नहीं हो सकता है समानता से छूट जब
तक कि इसे वैधानिक लक्ष्य से जोड़ा न जाए। यह

यह विधेयक की कमजोर कड़ी है।

उद्देश्य और कारण न्यायालय का मार्गदर्शन करने वाली सूचनात्मक सामग्री हैं।

किसी विधान के उद्देश्य और भेद के संबंध के बारे में, यदि

किसी भी, अंत में देखने के लिए। आपातकाल अवधि के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है

उच्च पदस्थ सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक अधिकार का दुरुपयोग, चाहे जो भी समय हो कमीशन, थकाऊ देरी के बिना दंडित किया जाएगा जो आदेश देता है रिली शीर्ष अधिकारियों के मामले में न्याय को हरा देता है जिनके अपराध प्रभावित करते हैं लोकतांत्रिक शासनों की साख ।

मोहम्मद शुजात अली और अन्य में अदालत । वी. भारत संघ और ओआरएस । (1) वर्गीकरण के संवैधानिक पहलू की व्याख्या की है:

" यह सिद्धांत मानता है कि विधायिका वर्गीकृत कर सकती है ।

विधान के उद्देश्य के लिए लेकिन यह आवश्यक है कि वर्गीकरण

यह तर्कसंगत होना चाहिए । यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्ति या समान रूप से स्थित सभी चीजों के साथ समान व्यवहार किया जाता है ।

द

मी.

किसी वर्गीकरण की तर्कसंगतता का निश्चित होना इसकी डिग्री है । समान रूप से स्थित लोगों के साथ समान व्यवहार करने में सफलता ।

(1) [1975] 1 477 पर एस. सी. आर. 449 ।

आई. ए.

[1979]

2 एस. सी

2

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेकिन सवाल यह है: यह अस्पष्ट और महत्वपूर्ण क्या है

वाक्यांश 'समान रूप से स्थित' का अर्थ है? हम कहाँ ढूँढ़ें

स्थिति की समानता का परीक्षण जो कारण निर्धारित करता है

वर्गीकरण की योग्यता? अपरिहार्य उत्तर है

कि हमें वर्गीकरण से परे उद्देश्य की ओर देखना चाहिए कानून । एक उचित वर्गीकरण वह है जिसमें सभी शामिल हैं ।

उद्देश्य के संबंध में व्यक्ति या समान रूप से स्थित चीजें कानून " ।

सामान्य प्रस्ताव को कहने के बाद न्यायालय ने एक आर चेतावनी दी जो वर्तमान विवाद का मुख्य सार है: (1.

" मौलिक गारंटेक का समान संरक्षण है

कानून और वर्गीकरण का सिद्धांत केवल एक सहायक नियम है ।

उस गारंटेक को एक व्यावहारिक सामग्री देने के लिए अदालतों द्वारा विकसित किया गया

समाज की व्यावहारिक आवश्यकताओं के साथ इसे समायोजित करके और

इसे डूबने और कीमती को डूबने नहीं दिया जाना चाहिए । समानता की गारंटी ।
वर्गीकरण का सिद्धांत होना चाहिए

एक ऐसे बिंदु पर नहीं ले जाया जाए जहाँ एक उपयोगी सेवक होने के बजाय

वास्तव में, यह एक खतरनाक मास्टर बन जाता है, अन्यथा के लिए, के रूप में इंगित

जम्मू और कश्मीर राज्य में चंद्रचूड़, जे. बनाम ।

त्रियोल्की नाथ खोसा (2) "समानता की गारंटी उप होगी ।

वर्ग विधान में विलय, जिसका उद्देश्य कानूनों के रूप में होना था अलग-अलग और
अलग-अलग विशेषताओं वाले अच्छी तरह से चिह्नित वर्गों को नियंत्रित करें

. यह प्रक्रिया अनिवार्य होगी ।

टिच अचीवमेंट्स " ।

के लिए वर्गीकरण के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करने में अंत

समानता का सिद्धांत समानता का मौलिक अधिकार

कानून और कानूनों के समान संरक्षण को प्रतिस्थापित किया जा सकता है

हमारा

एपी

वर्गीकरण की अत्यधिक कार्यशील पद्धति द्वारा।

इसलिए, समान संरक्षण खंड के लिए प्रोच, गुड़ होना चाहिए।

कृष्ण अय्यर, जे. इन द्वारा कहे गए सावधानी के शब्दों से प्रेरित

जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा (2) "मिनी"

सूक्ष्म भेदों पर आधारित वर्गीकरण हमारे लिए गलत हैं।

समतावादी विश्वास और केवल पर्याप्त और सीधे वर्ग स्पष्ट रूप से प्रासंगिक लक्ष्यों को बढ़ावा देने में संवैधानिकता हो सकती है।

राष्ट्रीय वैधता। अधिक वर्गीकरण करना समानता को पूर्ववत करना है।

(जोर दिया गया)

मैथ्यू, जे. ने अंबिका मिल्स (3) में वही उच्चारण रखा

निम्न-समावेशन:

(1) 478 पर आई. बी. आई.

(2) [1974] 1 एस. सी. सी 19

(3) गुजरात राज्य और अन्र। वी. श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड अहमदाबाद [197]

3 782 पर एस. सी. आर. 760।

आरई: विशेष अदालत बिल (कृष्णा अय्यर, जे.)

563

" कानूनों का समान संरक्षण संरक्षक की प्रतिज्ञा है।

समान कानूनों का निर्माण। लेकिन कानून वर्गीकृत कर सकते हैं।

एक कारण

ध्वनि योग्य वर्गीकरण वह है जिसमें वे सभी शामिल हैं जो समान हैं।

क्या वाक्यांश 'समान रूप से स्थित' का अर्थ है? इसका जवाब है
सवाल यह है कि हमें वर्गीकरण से परे देखना चाहिए

कानून का उद्देश्य।

कानून का उद्देश्य या तो हो सकता है

सार्वजनिक शरारत का उन्मूलन या कुछ की उपलब्धि
सकारात्मक सार्वजनिक भलाई।

एक वर्गीकरण के तहत है-समावेशी जब सभी शामिल हैं

कक्षा में दुष्टता से दागी हैं लेकिन अन्य भी हैं

शब्दों में, एक वर्गीकरण निम्न-समावेशी के रूप में खराब है जब एक राज्य
व्यक्तियों को इस तरह से लाभ या बोझ देता है जो एक वैधता को आगे बढ़ाता है

साथी का उद्देश्य लेकिन समान लाभ प्रदान नहीं करता है या स्थान नहीं देता है

समान रूप से स्थित अन्य लोगों पर समान बोझ। ए क्लासी
एकीकरण अति-समावेशी है जब इसमें न केवल वे शामिल होते हैं जो

समान रूप से उद्देश्य के संबंध में स्थित हैं लेकिन अन्य
जो इतने स्थित भी नहीं हैं। "

(जोर दिया गया)

यहाँ, समान परिस्थिति वाला वर्ग क्या है, जिसके अनुसार

'पंखों के पक्षी' नहीं जिन्हें 'एक साथ झुंड' बनाना चाहिए, समान रूप से प्रयास करना चाहिए
और समान रूप से न्याय का फल प्राप्त करना चाहिए? कौन-सा आनुवंशिक भेद इस बात को
उचित ठहराता है रिश्वत लेने वाले कल, आज और कल के मंत्रियों के बीच की धारा जहां
तक-और यह जल चिह्न है-अनुकरणीय तात्कालिकता और न्यायिक प्रक्रिया की अस्थायी
अंतिमता का संबंध है?

विधेयक के प्रस्तावना भाग में कहा गया है कि

आपातकाल के युग में सौ पिशाच खलनायक प्रेतवाधित थे, जिनके पास महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएँ थीं। फज़ल अली, जे. ने उन्हें राजस्थान राज्य और अन्य, आदि में संघनित किया। भारत संघ आदि (1) और इन प्रावधानों को विधेयक की प्रस्तावना में उधार लिया गया है-और कहा गया है:

" (2) कि नागरिक स्वतंत्रता को काफी हद तक वापस ले लिया गया था;

(3) कि लोगों के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार थे

निलंबित;

(4) कि प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगाई गई थी; और

(1) [1978] 1 एस. सी. आर. 1 118 पर।

[1979] 2 एससी. आर.

564

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(5) कि न्यायिक शक्तियों को काफी हद तक अपंग कर दिया गया था "

सवाल यह नहीं है कि क्या बुराइयों के दुखद चतुष्कोण ने किया

अस्तित्व में है-- हमें, कानून में, यह मान लेना चाहिए कि उन्होंने किया था-- लेकिन तत्कालीन प्रचलित रुग्ण स्थितियों और अपरिहार्य स्थितियों के बीच महत्वपूर्ण संबंध क्या है?

आपराधिक न्यायालयों में भ्रष्ट या दमनकारी प्रशासकों पर मुकदमा चलाने की सामान्य प्रक्रियाओं की क्षमता। जहां मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों को रिश्वत के मामलों का संज्ञान लेने से मना किया गया है, यदि -

आरोपित

क्या वे मंत्री थे या उनके सहयोगी? क्या उच्च अधिकारियों द्वारा शक्तियों के आपराधिक दुरुपयोग को अदालत के न्यायशास्त्र से हटा दिया गया था? क्या गवाहों को गवाही देने से

प्रतिबंधित कर दिया गया था या पुलिस प्रोही को जाँच से रोक दिया गया था? नहीं। न्यायिक आयोगों द्वारा पाए जाने के बाद भी, अतीत में शीर्ष राजनीतिक सत्ता-धारक अक्सर भाग जाते थे

ए

उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला। न्यायिक प्रक्रिया के कुंडल से उनके बचने की विकृति का गलत निदान केवल आपातकालीन वायरस के कारण नहीं किया जा सकता है। वह दृष्टिकोण पक्ष-समाधान को ट्रैक करता है और बीमारी को जारी रखने का काम करता है। उदाहरण के लिए, गोपनीयता और अधिकार संदिग्ध और अहंकारी शक्ति के शस्त्रागार हैं। जानने का अधिकार स्वतंत्र कार्रवाई का एक मौलिक पहलू है और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम अक्सर भ्रष्ट लोगों की ढाल होता है। निर्भीक जाँच अपराधी 'महान लोगों' के उजागर होने की एक अनिवार्य शर्त है और यदि जाँच एजेंसियाँ जाँच करने या सार्वजनिक करने के लिए कांपती हैं तो उच्च पद पर रहने वाले सफेदपोश अपराधियों के अपराधों को कानून द्वारा अनियंत्रित किया जा सकता है। किसी भी जिम्मेदार नागरिक द्वारा शुरू की जाने वाली एक स्वतंत्र जाँच एजेंसी एक इच्छा है।

आदि, निरंतर में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए

ये

'आपातकालीन अतिरेक' का दिन।

आपात स्थिति की प्रस्तावना में प्रासंगिकताओं पर भरोसा किया गया था

और त्वरित परीक्षण के लिए इसकी सांठगांठ का विश्लेषण किया जा सकता है। नागरिक स्वतंत्रताएँ थीं

दबा दिया गया, प्रेस सेंसरशिप को कम कर दिया गया और न्यायिक शक्तियों को कम कर दिया गया। यह मानते हुए कि नागरिक स्वतंत्रता आपातकाल के दौरान एक दुर्घटना थी, इसने अति-राजनीतिक अपराधों के मुकदमों में कैसे बाधा डाली

खनिज? यदि घरेलू संस्थाओं में विश्वास पीड़ित है

मामला

आपातकाल की परवाह किए बिना, उच्च सार्वजनिक और राजनीतिक अपराधियों को दंडित करने में अनुचित देरी हो रही है। इसी तरह, अगर आपातकाल के दौरान प्रेस को दबा दिया गया था, तो इसका राजनीति से क्या लेना-देना था?

अदालतों में शिकायत दर्ज करके अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जा रहा है?
यदि न्यायिक शक्तियाँ उद्घोषणा और अनुवर्ती कार्रवाई से पंगु हो गईं

अधिसूचना, उन्होंने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायशास्त्र को प्रभावित किया

निवारक निरोध या कुछ के इनकार के खिलाफ राहत देने के लिए आदेश

स्वतंत्रताएँ। इसका निचली अदालतों में त्वरित अभियोजन से क्या लेना-देना था?

उच्च राजनीतिक अपराधियों की-वह बारहमासी स्वतंत्रता के बाद की प्रजाति?

यदि विभेदक मानदंड और लक्ष्य के बीच महत्वपूर्ण संबंध है

आर. ई. उदाहरण के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला एकमात्र वर्गीकरण संबंधी औचित्य कानून का होना चाहिए:

विशेष अदालत बिल (कृष्णा अय्यर, जे.)

565

समान उपचार से। इमर्जेन्सी भ्रष्ट मंत्रियों और निर्वाचित सीज़रों को दो श्रेणियों में विभाजित नहीं करता है। वे स्थान और समय में निरंतरता के साथ एक आम दुश्मन हैं और सामाजिक न्याय के सामने आने के लिए, एक स्थायी कानून द्वारा उनका पता लगाया जाना चाहिए।

आइए हम समस्या को थोड़ा अलग तरीके से देखें। भले ही स्वतंत्रता थी

कटौती नहीं की गई, प्रेस को बंद नहीं किया गया या अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं की गई, आपराधिक मुकदमे और अपील और संशोधन अपने आप हुए होंगे।

अनन्त विलम्ब। यह फॉरेंसिक देरी है जिसे समाप्त करना होगा और

इसका आपातकाल की बुराइयों से कोई लेना-देना नहीं है। इस तरह के अपराध

पहले न्यायिक आयोगों द्वारा उजागर किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल थे

और दोनों स्तरों पर कैबिनेट मंत्री और कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की गई अब और एक चुनिंदा समूह को छोड़कर। यह इच्छाशक्ति की कमी थी-इमेर की नहीं।

जेन्सी-- वह मामलों के गैर-अभियोजन में टुकड़े का खलनायक था

जांच आयोग जैसे कई आयोगों द्वारा खुलासा किया गया 1967 में उड़ीसा सरकार द्वारा
इंगित (श्री न्यायमूर्ति खन्ना),

जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग

1965 (श्री न्यायमूर्ति राजगोपाला अय्यंगार), मुधोलकर आयोग

सरकार द्वारा नियुक्त संयुक्त मोर्चा के 14 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ

1968 में बिहार का राज्यपाल और टी. एल. वेंकटरामा अय्यर आयोग

बिहार सरकार द्वारा नियुक्त प्रश्न, 1970-उल्लेख करने के लिए लेकिन

कुछ। हमें शायद ही यह कहने की आवश्यकता है कि सी. आर. आई. के लिए कोई सीमा का
कानून नहीं है। गौण अभियोजन। किसी तरह, कुछ लोग कानून से ऊपर होने का
प्रबंधन करते हैं और

कई कानून के नीचे रहते हैं। कैसे? मुझे कहने में संकोच हो रहा है।

मेरा कहना है कि उच्च शक्ति वाले सार्वजनिक और राजनीतिक अपराधी हैं

आपातकाल की कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है, बल्कि यह एक बहती हुई धारा रही है

लंबे समय तक और बोलियों के लिए किराया, कभी-कभी गौण रूप से, कुछ

एक पहाड़ी घाटी के माध्यम से बहते समय। इसलिए, एक भ्रष्ट कौंटी

बेहतर औचित्य के बिना वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है।

इसके अलावा, अनुच्छेद के 'मानवाधिकार' आयाम। 21 एक घातक है

निष्पक्ष प्रक्रिया के विधायी कटौती पर प्रभाव। का योगदान

प्रक्रियात्मक न्याय के मानवीकरण के लिए मेनका गांधी का मामला (1) उप है।

स्थिर। मैं इस पहलू पर विस्तार नहीं करता क्योंकि प्रमुख निर्णय में कहा गया है
उससे निपटा लिया।

तब सवाल यह है कि क्या इसके लिए कोई संवैधानिक तर्क है।

त्वरित न्याय गैर-आपातकालीन अपराधियों की पहुंच से बाहर होना

उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक कार्यालय। ऐसा विधेयक, क्या यह एक स्थायी जोड़ था कोष न्यायपालिका के लिए और जनता के लिए एक अधिकार क्षेत्र के रूप में उपलब्ध

सरकार को मजबूर करने के लिए, अगर उनके खिलाफ भी प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था

कार्यालय में एक मंत्री, एक बैठे उच्च के सामने एक अभियोजन शुरू करने के लिए

(1) [1978] 1 एससीसी 248।

[1979] 2 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

566

अदालत के न्यायाधीश, शक्ति पिरामिडों में ई. वी. आई. भ्रष्टाचार फैलाने के लिए एक संपूर्ण सुधारात्मक होंगे। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति खन्ना के शब्दों को याद करना उपयुक्त है।

(1)

" सरकार की प्रत्येक प्रणाली के लिए आवश्यक है कि वे

सत्ता को इसका उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए

आत्म-खोज का एक साधन। सारी शक्ति एक विश्वास की तरह है।

जिन लोगों ने इसे लोगों से प्राप्त किया है, वे दिखाने के लिए जवाबदेह हैं

कि इसका प्रयोग लोगों के लिए किया गया है। दोहराने के लिए कि मैं

हाल ही में कहा गया है, सत्ता में रहने वालों द्वारा अनिवार्य रूप से अधिकार का दुरुपयोग यह बड़े पैमाने पर मोहभंग का कारण बनता है और इसके परिणामस्वरूप जनता में निराशा पैदा होती है।

यह लोकतांत्रिक व्यवस्था से अधिक कहीं भी सच नहीं है-क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही खुद सत्ता सौंपती है

जिन्हें वे चुनते हैं। अधिकार का दुरुपयोग और दुरुपयोग

कई रूप ले सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप आत्म-उन्नति हो सकती है।

सत्ता में रखे गए लोगों द्वारा अधिक अधिकार प्राप्त करके

और राजनीतिक और प्रति को समाप्त करने के लिए उस अधिकार का उपयोग सोनल विरोधी। इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग

जाने का रास्ता

अधिनायकवाद और तानाशाही। शक्ति भी हो सकती है

इसे व्यक्तिगत संवर्धन का स्रोत बनाकर दुरुपयोग किया जाता है। कोर.

टूटना रिसता है और यदि वे जो शीर्ष पर शक्ति में हैं वे मोड़ देते हैं
टूट, हम जल्द ही पता चलेगा कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार हो जाता है

देश किसी भी तरह इस बुराई को बर्दाश्त कर सकते हैं, इसे नापसंद करते हैं कि वे कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही अच्छी तरह से विकसित है। में।

विकासशील देशों का मामला, भ्रष्टाचार की गिरफ्तारी और अक्सर विकास की प्रक्रिया को बाधित करता है और राष्ट्र एक भुगतान करता है

नैतिक हानि के संदर्भ में भारी कीमत

मूल्य।

कुछ भी नहीं।

जनता को और अधिक निराश करता है और लोगों के विश्वास को और अधिक हिलाता है

लोकतांत्रित प्रक्रिया में लोग और उनके विश्वास को कम करते हैं

जिन लोगों को यह काम सौंपा गया है, उनकी दृष्टि की तुलना में वे अपने काम में डूबे हुए हैं।

लोगों द्वारा अपने उपयोग का उपयोग करके पद के लिए चुने जाने से शक्ति

आत्म-उन्नति और व्यक्तिगत संवर्धन के लिए अधिकार।

प्रशासन की शुद्धता का बहुत अधिक महत्व है

हाल ही में अर्थव्यवस्थाओं से मुक्त हुए देश

विकास "।

आपातकाल-उन्मुख उप-वर्ग के खिलाफ मामला बताते हुए

गठन, मैं अभी भी सोचता हूँ कि संवैधानिक सिद्धांतों पर, डीएसआईएन द्वारा पवित्र, इस अस्थायी उपाय को बनाए रखना या बचाना संभव है जो एक विनाशकारी अवधि के दौरान अपराधों और अपराधियों को अलग करता है

(1) 18 फिरोज गांधी स्मारक व्याख्यान।

आरई: विशेष अदालत बिल (कृष्णा अय्यर, जे.)

567

जो समान दुष्ट संपत्तियों को साझा करते हैं। जब एक उद्धारक परिवर्तन होता है

स्थानीय उपलब्ध है, अदालत को इसका विकल्प चुनना चाहिए जब हमला अनुच्छेद के तहत हो। 14, बशर्ते कि वैकल्पिक रूप से वांछित तथ्य की धारणाएं प्रशंसनीय हों, न कि बेतुकी। प्रस्तावना में एक्स-रे के रूप में आपातकाल की शारीरिक रचना, सभी काली छायाएँ हैं, जिन्हें जब कल्पनाशील रूप से पढ़ा जाता है, तो परिस्थितियाँ प्रशंसनीय, यहां तक कि संभावित और आसानी से अनुमानित हो जाती हैं। कल्पना कीजिए कि सर्वव्यापी पुलिस, मीसा की अजेय लेकिन सर्वशक्तिमान शक्तियों के तहत काम कर रही है, जो मनुष्यों को हर तरह से पकड़ रही है।

बिना किसी न्यायोचित कारण या सरासर सनक के प्राधिकरण और उन्हें छिपी हुई जेलों में अंतहीन कारावास में डालना! भयानक यातना या चुनौती का आदेश देने या रोकने के लिए अवैधता का आह्वान करने के लिए कोई अदालत नहीं

उच्च-हाथ अनुचित! यदि यह एक संभावित खतरा है, तो स्वाभाविक रूप से एक डैन

भयंकर स्थिति विकसित होती है, और एक बार गर्म न होने पर असहनीय शक्ति विकसित होती है,

इस तरह के दुरुपयोग का उद्घाटन और वृद्धि एक बन जाता है

बाध्यकारी निरंतरता। संवैधानिक अत्याचार अभिशाप है

सभ्य लोकतंत्र। लोगों की घबराहट की उस स्थिति में,

बिना बोलने के, बिना चलने-फिरने के, बिना सुरक्षा के ये सभी अनिश्चित हैं।

वास्तविक शक्ति में कुछ, मनोचिकित्सकों पर निर्भर, जाने का अधिकार

अदालत और भ्रष्टाचार या दुरुपयोग के लिए अधिकार में एक निरंकुश व्यक्ति पर मुकदमा चलाएँ

शक्ति का भ्रम है। यदि आप उच्च स्थिति में अपराधों के खिलाफ बोलते हैं

हो सकता है

यदि आप सत्ता के दुरुपयोग के बारे में अदालत में शिकायत करते हैं, तो आप

न्यायिक राहत के साथ त्वरित हिरासत और गुप्त यातना के साथ स्वागत किया गया

हटा दिया गया और प्रेस का प्रचार बंद कर दिया गया। अगर ये भयानक रोग हो सकते हैं

मान लिया गया था कि आपातकाल के बीच एक हानिकारक सांठगांठ हो सकती है

मौसम और इस विधेयक के दायरे में आने वाले भयावह अपराध। शायद ये

डरावनी धारणाएं अतिरंजित हैं लेकिन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं और फजल अली, जे की टिप्पणियाँ जो पहले उद्धृत की गई हैं, न्यायाधीश को अनुमति नहीं देती हैं।

उन्हें काल्पनिक के रूप में खारिज करना। यह इस प्रकार है कि के बीच एक सांठगांठ भिन्नता और वस्तु अनुमान लगाने के लिए बहुत पुनरावर्तित नहीं है।

संक्षेप में स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट रूप से ठोस हो सकता है। अगर कोई आपात स्थिति है

सत्तावादी के पास भ्रष्टाचार विरोधी के तहत संज्ञेय आपराधिक 'सौदा' था

कानून और एक जानकार नागरिक ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई।

या एक रिट याचिका जिसे दुर्भावनापूर्ण रूप से एक कार्यकारी कार्यवाई प्रेरणा के रूप में चुनौती दी गई है

ग्राफ्ट द्वारा यह काफी कार्ड पर था कि उसका घर वापस जाने का रास्ता हो सकता है
 एक मेहमाननवाज लॉक-अप या भूखे हिरासत शिविर या भयावह स्थान में भेज दिया गया
 बुलडोजर पुलिस की धूमधाम के साथ एक अपराधी सत्तावादी द्वारा चलाया गया कैसे
 आपराधिक अतिचार या गंभीर शरारत की जानकारी पहले रखी जा सकती है
 वही पुलिस या मामला मजिस्ट्रेट के सामने शुरू किया जाता है यदि कार्रवाई की जाती है
 परिणाम? कानून का शासन कागज पर टिक सकता है लेकिन घबरा गया
 छिपाने में जहां कानूनी प्रक्रिया के आह्वान का वेतन एक है
 संदिग्ध कारावास। आप अदालत जा सकते हैं लेकिन सुनिश्चित रहें कि
 जेल में किरायेदारी जब आप बाहर आते हैं। ये खतरनाक संभावनाएँ [1979] 2 एस. सी. आर.

568

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिद्वंद्विता अतिशयोक्ति हो सकती है लेकिन इसकी कुछ नींव थी, और
 डर उपचार की किताब को मोड़ देता है। इस प्रकार का भयावह परिदृश्य
 ' आपातकालीन ज्यादतियों में व्यक्तियों के खिलाफ गैर-कार्रवाई के साथ संबंध था
 अधिकार और भ्रष्टाचार और दमन की वृद्धि के खिलाफ उच्च जब दुरुपयोग पर न्यायिक जांच
 सो गई थी। जब पुरुषों को एहसास होता है कि भाषण लोहे का होता है और मौन चांदी के टुकड़े
 होते हैं तो वे कानून की किताबों के बावजूद बहरे और गूंगे हो जाते हैं।

वर्गीकरण को बनाए रखने का एक और अच्छा कारण वैधता है।

राज्य के पास एक व्यस्त चरण, एक अति-रोगजनक अवधि, एक आकस्मिक बाढ़ को चुनने और
 उस जादू का अकेले इलाज करने की शक्ति है, जिससे अन्य जैसे खराब अवधि को उनके कम
 आघात के कारण अच्छी तरह से अकेला छोड़ दिया जाता है। यह डिग्री और आयाम का सवाल
 है। अम्बिका मिल्स (1) में इस न्यायालय ने कहा:

" मिस्टर जस्टिस होम्स, अंडर-इंक्लु के प्रति सहिष्णुता का आग्रह करते हुए

व्यापक वर्गीकरण में कहा गया है कि इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए
न्यायालय द्वारा परेशान किया जाता है जब तक कि वह स्पष्ट रूप से देख न सके कि
कानून के लिए कोई उचित कारण नहीं है जिसकी समान आवश्यकता नहीं होगी

जिन लोगों को यह अच्छूता छोड़ता है, उन्हें इसके विस्तार के लिए मजबूर करें। क्या,
तो, क्या गैर-विस्तार के उचित कारण हैं? क्या करना चाहिए?

एक अदालत तब ऐसा करती है जब उसका सामना एक कानून के तहत किया जाता है।

टर्स। क्या उसे अपने निर्णय द्वारा विधायिका को मजबूर करना चाहिए
निष्क्रियता या पूर्णता के बीच चयन करें?

विधायिका को प्रशासकों पर थोपने की आवश्यकता नहीं हो सकती है

ट्रेटिव एजेंसी के कार्य जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है या जो
इसे एक ही स्ट्रोक पर बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए।

" यदि कानून संभवतः बुराई पर हमला करता है जहां इसे सबसे अधिक महसूस
किया जाता है,

इसे उखाड़ फेंकना नहीं है क्योंकि अन्य उदाहरण भी हैं
जिस पर इसे लागू किया जा सकता था। कोई सिद्धांत नहीं है

कोई आवश्यकता नहीं है कि कानून में जोड़ा जाना चाहिए

सभी स्वीकार करने वाली शर्तें "।

(वेस्ट कोस्ट होटल कंपनी बनाम देखें। पारिश) (*)

आपातकाल सत्ता के आपराधिक दुरुपयोग का गवाह था, इसलिए कहते हैं

प्रस्तावना, एक ऐसे पैमाने पर जो पहले या बाद में नहीं सुना गया हो। इसलिए, यह ओमि नोस
अवधि विधायी अलगाव और विशेष उपचार के लिए खुद को उधार देती है। श्री न्यायमूर्ति मैथ्यू
ने उदारतावाद की व्यावहारिकता के अनुरूप चयनात्मक व्यवहार के न्यायशास्त्र की खोज की है।
वर्तमान विधेयक इस उक्ति का एक पाठ्यपुस्तक चित्रण है: (3)

(1) [1974] 3 783 पर एस. सी. आर. 760।

(2) 300 अमेरिका 379,400।

(3) गुजरात बनाम. अम्बिका मिल्स लिमिटेड [1974] 3 एस. सी. आर. 760
782-783 पर।

आरई: विशेष अदालत बिल (कृष्णा अय्यर, जे.)

56

" एक सामान्य समस्या के लिए टुकड़ों में दृष्टिकोण की अनुमति है

कम समावेशी वर्गीकरणों द्वारा, यह उचित प्रतीत होता है जब यह माना जाता है कि ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए विधायी है

आमतौर पर एक प्रयोगात्मक मामला। यह बताना असंभव है कि एक विशेष दृष्टिकोण कितना सफल हो सकता है, क्या विस्थापन हो सकते हैं, क्या पलायन हो सकते हैं, प्रयास में कौन सी नई बुराइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। प्रशासनिक तेजी

जाली और परीक्षण किए जाने चाहिए। विधायक, इन कारकों को पहचानते हुए, सावधानी से आगे बढ़ना चाह सकते हैं, और अदालतों को चाहिए

उन्हें ऐसा करने दें (ऊपर)।

अवैतनिक एसी के संग्रह में प्रशासनिक सुविधा

समस्या जो विधायी मस्तिष्क को सबसे तीव्र लगती है। वहाँ विधायिका एक क्षेत्र के केवल एक चरण का चयन कर सकती है

इससे पहले, एक

आवेदन या एक उपाय। (1)

यह याद रखा जा सकता है कि अनुच्छेद 14 की आवश्यकता नहीं है कि

प्रत्येक विनियामक कानून एक ही व्यवसाय में सभी पर लागू होता है; जहाँ

आकार उस बुराई का सूचकांक है जिस पर कानून निर्देशित किया जाता है, और छोटे के बीच अपराध की अनुमति है, और

बड़े

सुधार के लिए एक बार में एक कदम उठाने की भी अनुमति है।

समस्या के उस चरण में खुद को तैयार करना जो सबसे अधिक प्रतीत होता है

विधायी दिमाग के लिए तीव्र।

अपने क्षेत्र के भीतर कार्य करने वाला विधायी प्राधिकरण बाध्य नहीं है।
अपने विनियमन का विस्तार उन सभी मामलों में करने के लिए जो संभवतः
पहुँचते हैं। विधायिका नुकसान की डिग्री को पहचानने के लिए स्वतंत्र है।
और यह प्रतिबंधों को उन वर्गों के मामलों तक सीमित कर सकता है
जहाँ आवश्यकता स्पष्ट प्रतीत होती है (म्यूचुअल लोन कंपनी देखें।
वी. मार्टेल) (2)।

संक्षेप में, विधायी वर्गीकरण की समस्या एक पेरेन है
नीयल एक, कोई सैद्धांतिक परिभाषा स्वीकार नहीं करना। बुराई अंदर है
एक ही क्षेत्र अलग-अलग आयामों और गुणक का हो सकता है विभिन्न
उपचारों की आवश्यकता होती है। या इसलिए विधायिका कर सकती है
सोचिए (टिग्नर वी. देखें। टेक्सस) (3)।

एक बार एक उद्देश्य विधायी के भीतर होने का निर्णय लिया जाता है
क्षमता, हालांकि, वर्गीकरण से बाहर काम करना
केवल कभी-कभी न्यायिक नकारात्मकताओं द्वारा बाधित किया गया है।

(1) हैरिसन के दो लोग-एलनटाउन बनाम। मैकगिनले, 366 यू. एस. 582,59

(2) 56 एल. एड. 175, 180।

(3) 310 यू. एस. 141

978 एससीआई/78 [1979] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

570

अदालत का रवैया यह नहीं हो सकता है कि राज्य को या तो

सभी व्यवसायों, या यहां तक कि सभी संबंधित व्यवसायों और एक ही तरह से, या, बिल्कुल नहीं। किसी विशेष पर हमला करने का प्रयास

इसके कारण परेशान करने वाली, परेशान करने वाली और महंगी ट्रेन चल रही है जुड़े हुए या समान की पूरी श्रृंखला को कवर करने वाले नियम

उद्यम "।

" सब कुछ या कुछ भी नहीं होने से काम न आने वाली कठोरता हो सकती है। प्रिंसिपल कॉम

कानून में वादों की अनुमति है जहां गैर-परक्राम्य बुनियादी बातों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है। इस संदर्भ में विचाराधीन विधेयक पारित हो जाता है।

संवैधानिक परीक्षा।

आपातकाल से पहले और उसके दौरान अपराधों का ताना-बाना है -

समान रूप से, अपराध की प्रेरणा और बनावट अलग नहीं है। लेकिन, मेरे विचार में, जो बात विशेष कानून को मान्य करती है, वह है तत्कालीन स्थितियों की असामान्यता, भ्रष्ट संचालन का गहन चरण।

और

पुराने अपराधों को खोदने में अक्षमता। अम्बिका मिल्स (ऊपर) वर्गीकरण के लिए न्यायिक औचित्य है।

संक्षेप में, विधेयक खतरनाक रूप से असंवैधानिकता के करीब है (अनुच्छेद।

14) कुछ मामलों में, लेकिन निश्चित रूप से पूर्ववर्ती में निहित व्यावहारिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा बचाया जाता है। फिर भी, सामाजिक न्याय के लिए न्याय सबसे अच्छा एक स्थायी कानून द्वारा किया जाता है ताकि दृढ़ता से निपटा जा सके। अति-राजनीतिक अपराधियों के साथ, क्योंकि ये 'अछूत' और 'अप्राप्य' शक्ति-रक्षक देवक के भयावह लेकिन निरंतर साथी बन गए हैं विकासशील देशों में निवेश। अगर जानने का अधिकार और अभिव्यक्ति और आर्क को उजागर करने का अधिकार वास्तविक है तो और अधिक किया जाना बाकी है।

और

उपलब्ध उपचारों तक पहुंच, जिसके अभाव में कानून का शासन चमकता है

में

पुस्तकालय, लोगों के बीच नहीं।

चगनलाल मग्नलाल (1) का एक संक्षिप्त संदर्भ, इसे एक प्रकाश में प्रस्तुत करते हुए

विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए दृष्टिकोण से कुछ अलग, मेरे समाप्त होने से पहले उपयुक्त है क्योंकि इस तर्क का एक हिस्सा था कि यदि दोनों प्रक्रियाएं अपनी कठिन प्रक्रिया में काफी हद तक निष्पक्ष और समान थीं, तो प्रावधान संवैधानिक गुहा से परे था। वर्गीकरण संबंधी भेदभाव का अंक। बड़े सम्मान के साथ, यह विशेष बात है। यह समझ में आता है कि एक वैध वर्गीकरण को देखते हुए, एक या दूसरी वैकल्पिक प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए उपयुक्त योग्यता अच्छी है-एक ला चगनलाल मग्नलाल। उस मामले में, सार्वजनिक संपत्ति की त्वरित वसूली समूह का आधार थी और उस समूह के भीतर, दो वैकल्पिक प्रक्रियाओं में से एक, जो बोझ या सुविधा में कमोबेश समान थी, को सही माना गया था।

(1) चगनलाल मग्नलाल (पी) लिमिटेड बनाम। ग्रेटर बॉम्बे का नगर निगम

& ओआरएस। [1975] 1 एस. सी. आर. 1

आरई: विशेष अदालत बिल (कृष्णा अय्यर, जे.)

571

आसान निष्कासन के लक्ष्य से संबंधित तर्कसंगत आधार पर प्रारंभिक वर्गीकरण की अनुपस्थिति में, चगनलाल मग्नलाल (ऊपर) ने एक अंतर पैदा किया होगा।

किराए का कोर्स।

चगनलाल में एक संक्षिप्त भ्रमण यहाँ वांछनीय है। मैं पढ़ता नहीं हूँ।

चगनलाल इस तरह से कि इसके मूल को निरर्थक बना दे। उस मामले ने पहले इस आधार पर वर्गीकरण को उचित ठहराया कि सार्वजनिक संपत्ति अपने आप में एक वर्ग थी और यह अंतर

शीघ्र वसूली के लक्ष्य के लिए एक तर्कसंगत संबंध था। चगनलाल अनुपात का एक अन्य अंग यह है कि एक वैध वर्गीकरण दमनकारी या मनमाना प्रक्रिया के लिए कोई पासपोर्ट नहीं है। इसका ध्यान यह मानते हुए रखा जाता है कि निर्धारित विशेष प्रक्रिया भी बहुत अच्छी नहीं है।

और तीसरा, कक्षा के भीतर विशेष उपचार के लिए चुना गया

भारी है। क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि दोनों काफी हद तक निष्पक्ष और समान हैं। यह समझने के लिए कि इस अर्थ में निर्णय लेना कि एक बार प्रक्रिया काफी हद तक समान हो जाने के बाद, भेदभाव और वैध वर्गीकरण का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है, अधिकांश चर्चा को निरर्थक बनाना है। पूरी चर्चा को प्रासंगिक बनाने के लिए हमें इसके तीन अंगों को समग्र रूप से देखना होगा। इसलिए, प्रक्रिया की बुनियादी निष्पक्षता आवश्यक है। एक वैध वर्गीकरण

एक बोधगम्य अंतर और वस्तु के साथ बुद्धिमान संबंध की आवश्यकता होती है। त्रिभुज का तीसरा भाग यह है कि वर्ग के भीतर एक के लिए अधिक बोझिल प्रक्रिया और दूसरे के लिए काफी अलग प्रक्रिया का उपयोग करने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। इस क्षेत्र में मनमानी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करती है। 14 .

यहां तक कि हमारे वर्तमान कैस्क में, यह मानते हुए कि विधेयक के तहत सुविधाएं

और समान रूप से निष्पक्ष साधारण संहिता के तहत, क्या सरकार सामान्य अदालत या विशेष अदालत में एक या दूसरे को अभ्यारोपित कर सकती थी?

चित्रकारी के आधार पर या उनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर, उनकी खाल का रंग या गैर-इंद्रिय की तरह? नहीं। अनुच्छेद का ज्ञान। 14 इस तरह की सनक बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्गीकरण या नाश, संविधान के तहत लचीली समानता से वैध छूट की उत्कृष्ट परीक्षा है।

निष्कर्ष निकालने से पहले, मुझे शिन में तर्क की शक्ति को स्वीकार करना होगा

घल, नामित न्यायाधीशों के खिलाफ जे की शक्तिशाली याचिका। मेरा विचार है कि विधेयक के वर्तमान उद्देश्य के अनुरूप, संदर्भ द्वारा उठाई गई समस्याओं के उलझे हुए जाल का निश्चित समाधान उच्च न्यायालय को नए अधिकार क्षेत्र का संरक्षक बनाना है। यह सुझाव तब भी सामने आया जब बहस आगे बढ़ी लेकिन भारत संघ के वकील ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि पीठ द्वारा व्यक्त किए गए अस्थायी विचार पर सम्मानपूर्वक विचार किया जाएगा। त्वरित न्याय के उद्देश्य को विफल करने वाले संवैधानिक मुकदमे का जोखिम विचार किए गए सुझाव की अनदेखी करने की कीमत हो सकती है। यह संसद की समझदारी है कि वह उच्च न्यायालयों या उच्च न्यायालयों से चुने गए न्यायाधीशों पर भरोसा करे और संवैधानिक निर्णय का सामना करे।

आई [1979] 2 एस. सी. आर.

572

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और न कहें। जे. सिंघाल द्वारा व्यक्त की गई आशंका में, जो लोग न्यायिक स्वायत्तता को महत्व देते हैं, उनके लिए सोचने के लिए कुछ है कि इस साधन की स्वतंत्रता पर सूक्ष्म अतिक्रमण हो सकता है। एक मौलिक मूल्य के साथ अस्थायीकरण में घटनाएँ। जबकि मैं विद्वान न्यायाधीश के तर्क से असंतुष्ट हूँ, मैं इस बिंदु पर उच्चारण करने से बचता हूँ।

मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश से सहमत हूँ, हालांकि मैं थोड़ा अलग कहता हूँ।

सामान्य कारण।

जे. अंतवालिया-मैं विद्वानों द्वारा दी गई राय से पूरी तरह सहमत हूँ।

मुख्य न्यायाधीश एक मामले को छोड़कर, जो मेरे विचार में एक महत्वपूर्ण और मौलिक प्रकृति का है। इसलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ

उस प्रश्न पर अलग राय।

संदर्भ की सुनवाई के दौरान कुछ को हटाने के लिए

हस्तक्षेप करने वालों की ओर से उठाई गई तकनीकी आपत्तियाँ और अन्य चार सुझाव न्यायालय द्वारा दिए गए थे। तीन को भारत सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किया गया था, जिसका अर्थ सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति होगा। एक के बारे में, हमें बताया गया कि यह अभी भी सरकार के विचाराधीन है। मुझे ऐसा लगता है कि न्यायालय के जिन तीन सुझावों को स्वीकार किया गया था, वे किसी न किसी आधार पर विधेयक की संवैधानिक वैधता के लिए सभी संभावित चुनौतियों को दूर करने के लिए थे। चौथा काफी हद तक विधान के कुछ प्रावधानों के पीछे के ज्ञान से संबंधित है। मेरे विद्वान भाई जे. शिंगल ने एक मुद्दे पर अपनी अलग राय दर्ज की है, जिसके संबंध में चौथा सुझाव उन्होंने दिया था।

बस पारित करने में अदालत। मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूँ, और मैं इस संबंध में बहुत सम्मान के साथ कहता हूँ। मेरी राय में विधेयक उस कारण से किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं है। मुझे इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं उस संबंध में भी मेजोरी राय में कही गई सभी बातों से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ। संघीय न्यायालय या इस न्यायालय द्वारा उत्तर दिए गए पहले के किसी भी संदर्भ में एक पूर्ववर्ती इस विशेष संदर्भ में जो हुआ उससे मिलता-जुलता या समान नहीं पाया जाना चाहिए। मैं न्यायालय से कुछ सुझाव देने का तरीका अपनाने में

कोई हानि नहीं देखता जो किसी विधेयक के अधिकारों पर संभावित संवैधानिक हमले को मिटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सभी संदर्भों में इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाना आवश्यक या उचित भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कुछ लोगों में ऐसा करना समीचीन हो जाता है, जैसा कि मेरी राय में उस समय ऐसा ही था, तो मुझे लगता है कि अगर सरकार सोचती है कि वह ऐसा करने के लिए सहमत हो सकती है तो इससे विधेयक से किसी भी तकनीकी कमी को दूर करने के लिए जनता का बहुत समय और धन बचता है। बेशक यह विधेयक अपने आप में कोई कानून नहीं है। संसद द्वारा पारित होने पर यह एक कानून होगा। लेकिन विधेयक के स्तर पर भी जब इस न्यायालय की राय मांगी जाती है, तो मुझे लगता है कि यह आरई को काफी मंजूरी देता है:

विशेष अदालत बिल (शिंंगल, जे.)

573

किसी दिए गए मामले में कुछ सुझाव देने और फिर सरकार द्वारा स्वीकार किए गए सुझावों की स्वीकृति के आधार पर संदर्भ का जवाब देने का अधिकार है। अन्यथा, मेरे अनुसार, इस न्यायालय के लिए संदर्भ का उत्तर देना असंगत है क्योंकि यह सरकार की ओर से दी गई रियायतों और न्यायालय के सुझावों को ध्यान में रखे बिना है। यह स्पष्ट है कि तीनों अविश्वासियों ने बहुमत की राय में उत्तर नहीं में इंगित किया। 3 सरकार द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किए जाने के बाद गायब हो जाता है कि न्यायालय द्वारा कथित तीन दुर्बलताओं के संबंध में दिए गए तीन सुझाव, अर्थात्:

3 (ए), 3 (बी) और 3 (सी) को विधेयक से हटा दिया जाएगा।

हालाँकि, मैं विस्तृत रूप से विचार किए बिना जोड़ना चाहूंगा

यह इंगित करते हुए कि जहां तक उक्त दुर्बलताओं के गुण-दोषों का संबंध है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि 3 (सी), अर्थात्, किसी मामले को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में स्थानांतरित करने के प्रावधान का अभाव, प्रक्रिया को अन्यायपूर्ण या विरोधाभासी बनाता है। लेकिन, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कथित दुर्बलताएं 3 (ए) और (बी) प्रक्रिया को अन्यायपूर्ण या मनमाना बनाती हैं। मुझे गंभीर संदेह है कि क्या इस मामले में ऐसा है। किसी भी तरह से, मेरी राय में, संदर्भ की सुनवाई के दौरान न्यायालय से निकले सुझावों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति को देखते हुए उत्तर 3 में उल्लिखित तीन दुर्बलताओं (ए), (बी) और (सी) में से किसी के संबंध में प्रक्रिया के अन्यायपूर्ण या मनमाना होने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे यह मानने में कोई कठिनाई नहीं दिखती है कि उन

रियायतों को ध्यान में रखते हुए संदर्भ में संशोधन किया गया है और अब हमें संशोधित संदर्भ का जवाब देने की आवश्यकता है जिसका अर्थ है कि प्रस्ताव के रूप में विधेयक सरकार द्वारा दी गई तीन रियायतों को शामिल करता है। इस प्रकार प्रक्रिया

विधेयक में निर्धारित, निस्संदेह, न्यायसंगत और निष्पक्ष हो जाता है और अब नहीं किसी भी मायने में मनमाना रहता है।

शिंंगल जे।, — मुझे फैसले से गुजरने का फायदा हुआ

मेरे प्रभु के मुख्य न्यायाधीश और मैं इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि

उसके द्वारा संदर्भ के रखरखाव के संबंध में, विधायी

संसद की क्षमता और उठाए गए तर्क

संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में। मैं भी सहमत हूँ कि

विधेयक उप-पैरा के (ए) से (सी) में उल्लिखित तीन दोषों से ग्रस्त है। मेरे
प्रभु के निर्णय के समापन पैराग्राफ का ग्राफ (3)। यह.

हालाँकि मुझे लगता है कि सवाल यह है कि क्या विधेयक या कोई इसके
प्रावधान अन्यथा असंवैधानिक हैं, समान रूप से दायरे में हैं।

संदर्भ के तहत प्रश्न और प्रकाश में विचार की आवश्यकता है अन्य तर्क जो
हमारे सामने रखे गए हैं। वास्तव में

विधेयक के, किसी भी मामले में, संवैधानिक रूप से अमान्य हैं, भले ही तीनों
मुख्य न्यायाधीश द्वारा बताए गए उल्लंघनकारी प्रावधानों में संशोधन किया जाता है -

विद्वान महान्यायवादी द्वारा कही गई पंक्तियाँ।

आई।

[1979] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का संदर्भ

यह दर्शाता है कि इसका उद्देश्य "अतिरिक्त अदालतों" का निर्माण करना है जो इसमें उल्लिखित अपराधों के वर्ग के साथ "सक्रिय रूप से निपटेंगे"। इस तरह के विशेष न्यायालयों के निर्माण की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए, यह कहा गया है कि "अदालत कैलेंडर" "भीड़भाड़ वाले" हैं और "शक्तिशाली आरोपी" मामलों के निपटारे में बहुत देरी करने में सक्षम हैं और यह आवश्यक था कि जिन व्यक्तियों ने देश में उच्च राजनीतिक या सार्वजनिक पदों पर कार्य किया था और अपराध किए थे, उनके वास्तविक चरित्र के बारे में "मतदाताओं को जल्द से जल्द पता होना चाहिए यदि लोकतांत्रिक संस्थानों को जीवित रहना है और राजनीतिक जीवन को स्वच्छ रखना है"। विधेयक की प्रस्तावना मामलों के निपटारे में बहुत देरी करने के लिए "शक्तिशाली अभियुक्त" की क्षमता का उल्लेख नहीं करती है, लेकिन "काम की भीड़" का उल्लेख करती है और कहती है कि "अन्य कारण" थे जिनके लिए यह उचित रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि उच्च सार्वजनिक या राजनीतिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के अभियोजन को "त्वरित समाप्ति" पर लाया जाएगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि "साधारण आपराधिक अदालतें" काम से भरी नहीं होतीं, तो उन्हें प्रस्तावना के आठवें पाठ में संदर्भित "कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तनों" के साथ मामलों की सुनवाई करने की अनुमति दी जाती। उद्देश्यों और कारणों के कथन में "प्रक्रियात्मक परिवर्तनों" का कोई संदर्भ नहीं है, और वे उस कथन का आधार नहीं हैं। किसी भी मामले में साधारण आपराधिक न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर विधेयक में निर्दिष्ट अपराधों के वर्ग का मुकदमा चलाने से रोकने का कारण काम में भीड़ है, न कि उनकी निम्न स्थिति या उन मामलों से निपटने में असमर्थता। इसलिए विधेयक का उद्देश्य "साधारण आपराधिक न्यायालयों" के समान श्रेणी के अतिरिक्त न्यायालयों के निर्माण और किसी भी प्रक्रियात्मक परिवर्तन को पूरा करना होता, जिसे उस संदर्भ में परीक्षणों में टालने योग्य देरी को बाहर करने के लिए आवश्यक माना गया हो।

अगर ऐसी अतिरिक्त अदालतें होतीं तो कुछ भी असामान्य नहीं होता।

साधारण भीड़भाड़ वाले आपराधिक न्यायालयों को अधिक काम के बोझ से बचाने और विचारित अभियोजन लाने के लिए बनाया गया था

शीघ्र समाप्ति के लिए। यह मौजूदा कानून के तहत अनुज्ञेय था और वर्तमान विधेयक को संसद में पेश करना आवश्यक नहीं होता। और अगर कुछ "प्रक्रियात्मक परिवर्तनों" को आवश्यक माना जाता, तो भी उन्हें उस ढांचे के भीतर काम किया जा सकता था।

और उस सीमित उद्देश्य के लिए एक अलग विधेयक में शामिल किया गया।

लेकिन इसे संतोषजनक नहीं माना गया है, और विधेयक में "विशेष न्यायालयों" के निर्माण का प्रावधान है। खंड 2 और 7, जो विचाराधीन मुद्दे पर आधारित हैं, निम्नानुसार पढ़े जाते हैं।

आरई: विशेष अदालत बिल (शिंंगल, जे.)

575

" 2. केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा बनाएगी

पर्याप्त संख्या में न्यायालयों को विशेष न्यायालय कहा जाएगा।

7. एक विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक बैठक द्वारा की जाएगी।

भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या कोई व्यक्ति जिसने पद संभाला हो

भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और द्वारा नामित

केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से

भारत "।

इसलिए विधेयक में परिकल्पित विशेष अदालतें ऐसी अदालतें हैं जिनके बारे में दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून में प्रावधान नहीं किया गया है और वास्तव में देश के अपराधिक कानून से अनजान हैं। सवाल यह है कि क्या हमारा संविधान ऐसे न्यायालयों के निर्माण की परिकल्पना करता है।

संविधान का भाग 5 "संघ" से संबंधित है, जबकि अध्याय

इसका पहला अध्याय "कार्यपालिका" से संबंधित है, दूसरा अध्याय "संसद" से संबंधित है और चौथा अध्याय "केंद्रीय न्यायपालिका" से संबंधित है। अनुच्छेद 124 (1) में प्रावधान है कि "भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा", जिसके पास अनुच्छेद 32 में उल्लिखित निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति के अलावा, बाद के अनुच्छेदों में प्रदान की गई मूल, अपीलीय और अन्य अधिकारिता और शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 141 विशेष रूप से प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, और अनुच्छेद 144 यह स्पष्ट करता है कि सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। इसलिए वह न्यायालय संविधान की योजना

के तहत सर्वोच्च "संघ न्यायपालिका" है, और संविधान के भाग V के अध्याय IV में उस उद्देश्य के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान किया गया है।

भाग VI राज्यों से संबंधित है। इसका दूसरा अध्याय इस विषय से संबंधित है -

"राज्य विधानमंडल" के साथ अध्याय III और "राज्यों में उच्च न्यायालयों" के साथ अध्याय V। अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि "प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय" होगा, ताकि किसी भी राज्य में दो या दो से अधिक उच्च न्यायालय होने की अनुमति न हो, हालांकि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की अनुमति है (अनुच्छेद 239)। इस प्रकार किसी राज्य के उच्च न्यायालय को उस राज्य या राज्यों में एक अद्वितीय स्थिति का आश्वासन दिया गया है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 225 किसी भी मौजूदा उच्च न्यायालय में प्रशासित कानून की अधिकारिता और न्यायालय में न्याय के प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की संबंधित शक्तियों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 226 से संबंधित है

उच्च न्यायालय की शक्ति "के संबंध में सभी क्षेत्रों में जिसे वह किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

उचित मामलों में, किसी भी सरकार, उन क्षेत्रों के भीतर

खंड (1) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए निर्देश, आदेश या रिट।

अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय में अधीक्षण की शक्ति निहित करता है

[1979] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

576

अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी न्यायालयों पर। साथ की शक्ति सी. आई. आर. में उच्च न्यायालय को भी मामले दिए गए हैं।

अनुच्छेद 228 में उल्लिखित जटिलताएँ। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने सभी आवश्यक अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के साथ निहित है

संविधान द्वारा प्रतिरूपित कि किसी भी दीवानी या आपराधिक न्यायालय में राज्य को अपने नियंत्रण से बाहर होना चाहिए।

इसके बाद अध्याय VI आता है जो "अधीनस्थ न्यायालयों" से संबंधित है।

राज्यों को। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और अनुच्छेद 234 राज्य न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय में सभी जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निहित करता है। इस प्रकार संविधान में यह विचार किया गया है कि उच्च न्यायालय के अलावा किसी राज्य में सभी दीवानी और आपराधिक न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों के अलावा और कुछ नहीं होंगे, जिन पर उच्च न्यायालय पूर्ण अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेगा, और यह कि उन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी।

न्यायालय (अनुच्छेद 237 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेटों के अलावा) उच्च न्यायालय के नियंत्रण में होंगे और किसी अन्य प्राधिकरण के नियंत्रण में नहीं होंगे। वास्तव में दीवानी और आपराधिक मामलों से निपटने वाले प्रत्येक न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। किसी राज्य में अन्य पदनामों के साथ दीवानी और आपराधिक न्यायालयों का निर्माण या स्थापना करने की अनुमति हो सकती है।

उन लोगों की तुलना में जो अनुच्छेद 236 में व्यक्त किए गए हैं, अर्थात् वे जो पूर्व दबाव "जिला न्यायाधीश" द्वारा या सिविल और दंड प्रक्रिया संहिताओं में किसी भी मौजूदा पदनाम द्वारा कवर किए गए हैं, लेकिन यह कहने से बहुत दूर है कि संविधान में परिकल्पित न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालयों का पदानुक्रम स्थापित करना अनुमेय है।

इस प्रकार संविधान ने पर्याप्त और प्रभावी प्रावधान किए हैं -

दीवानी और आपराधिक न्यायालयों के आवश्यक पूरक के साथ देश में एक मजबूत, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक प्रशासन की स्थापना। संसद या राज्य विधानमंडल के लिए किसी राज्य में उच्च न्यायालय के समानांतर एक दीवानी या आपराधिक न्यायालय की स्थापना के लिए, या एक अतिरिक्त या अतिरिक्त या दूसरा उच्च न्यायालय, या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय के माध्यम से संविधान की उस योजना की अनदेखी करने या उसे दरकिनार करने की अनुमति नहीं है। इस तरह का कोई भी प्रयास असंवैधानिक होगा और इन पर हमला करेगा।

न्यायपालिका की निर्भरता जो संविधान में इतनी महानता से स्थापित की गई है और वर्षों से इतनी सावधानी से रखी गई है।

इस दृष्टिकोण का एक और कारण है। अनुच्छेद 233 और 235 प्रो

राज्यों में जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए। इन अनुच्छेदों के प्रावधानों की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य सहित कई मामलों में की गई है:

विशेष अदालत बिल (शिंंगल, जे.)

577

वी. नृपेंद्र नाथ बागची, (1) चंद्र मोहन और अन्य बनाम। की स्थिति

उत्तर प्रदेश और अन्य, (2) असम राज्य आदि। रंगू महूम मड और अन्य, (3) उड़ीसा राज्य बनाम। सुधांशु शेखर मिश्रा

और अन्य, (1) असम राज्य और एक अन्य v. एस. एन. सेन और एक अन्य, (3) शमशेर सिंह और एक अन्य बनाम। पंजाब राज्य, (*) उच्च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य।, (1) राज्य

बिहार का बनाम। मदन मोहन प्रसाद और अन्य, (\$) हरियाणा राज्य बनाम। इंदर प्रकाश आनंद (ओ) और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और

अन्य वी। एल. वी. ए. दीक्षितुलु और अन्य। (10)। इन निर्णयों में यह घोषित किया गया है कि यह उच्च न्यायालय है जो राज्य की न्यायपालिका पर नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक है। वास्तव में यह एक स्वतंत्र न्यायिक प्रशासन का जीवन रक्त है, और किसी भी वास्तविक न्यायिक भवन की नींव है। क्योंकि यदि उच्च न्यायालय के नियंत्रण या अधीनस्थ अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों को सिविल और आपराधिक न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की अनुमति थी, या दूसरे शब्दों में, यदि उच्च न्यायालय के नियंत्रण से बाहर न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेट व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करने की अनुमति थी, और राज्य कार्यपालिका को जवाबदेह था, तो यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करने के प्रशंसनीय और पोषित लक्ष्य के लिए संवैधानिक योजना के तहत विशेष रूप से उच्च न्यायालय के लिए आरक्षित क्षेत्र पर गंभीर अतिक्रमण के बराबर होगा। ऐसा हो सकता है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट ऐसा न करें।

वे किसी राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित हैं, लेकिन उनके न्यायालय "हीन" हैं, और सत्र न्यायालयों और उच्च न्यायालय के अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हैं। भले ही ऐसा है, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की ऐसी अदालतों के अस्तित्व को संविधान में पक्ष में नहीं

देखा गया है, और अनुच्छेद 50 विशेष रूप से निर्देश देता है कि राज्य न्यायपालिका को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। फिर अनुच्छेद 237 है जिसमें यह प्रावधान है कि राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकता है कि अध्याय VI (जो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है) के "पूर्वगामी" प्रावधान और उसके तहत बनाए गए कोई भी नियम किसी राज्य में मजिस्ट्रेटों के किसी भी वर्ग या वर्गों (यानी कार्यकारी मजिस्ट्रेट) के संबंध में लागू होंगे जैसा कि वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान ने इस पर विचार नहीं किया है

(1) [1966] 1 एससीआर 771। (2) [1967] 1 एस. सी. आर. 77 (3) [1967] 1 एस. सी. आर. 454 (4) [1968] 2 एस सी आर 154. (5) [1972] 2 एस सी आर 251. (6) [1975] 1 एस. सी. आर 814 (7) [1975] 3 एस. सी. आर 365 (8) [1976] 3 एस. सी. आर 110 (9) ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1841. (10) [1979] 1 एस. सी. आर. 26

[1979] 2 एस सी आर।

57 8

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति या निरंतरता जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण से बाहर हैं, वांछनीय है और उनकी निरंतरता को संबंधित लोगों के लिए श्रेय का विषय नहीं कहा जा सकता है। यह किसी भी संदेह या विवाद से परे है कि संविधान अनुच्छेद 235 में परिभाषित "जिला न्यायाधीश" की अध्यक्षता में एक आपराधिक न्यायालय की स्थिति की स्थापना की अनुमति नहीं देता है, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है, और जैसा कि दिखाया गया है, यह उच्च न्यायालय के समान न्यायालय या उच्च न्यायालय के समानांतर न्यायालय की स्थापना की अनुमति नहीं देता है। यह तर्क दिया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 उच्च न्यायालयों के अलावा अन्य आपराधिक न्यायालयों के गठन की अनुमति देती है

और अनुभाग में उल्लिखित वर्गों के न्यायालय। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 की धारा 6 पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है, ताकि यह दिखाया जा सके कि जब भी आवश्यकता हो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन ये दोनों प्रावधान इस तर्क को सही नहीं ठहराते हैं कि संविधान की योजना के तहत विधेयक में विचार किए गए प्रकृति के विशेष न्यायालय बनाए जा सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में कहा गया है कि

उच्च न्यायालय और "इस संहिता के अलावा किसी भी कानून के तहत गठित न्यायालयों" के अलावा, प्रत्येक राज्य में, इसमें उल्लिखित आपराधिक न्यायालयों के वर्ग होंगे, अर्थात् सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी भी महानगर क्षेत्र में, महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट। अतः इस धारा में केवल इतना कहा गया है कि इसमें वर्णित आपराधिक न्यायालयों के पाँच वर्ग उन उच्च न्यायालयों और न्यायालयों के अतिरिक्त होंगे जो किसी अन्य कानून के तहत गठित किए जा सकते हैं, और यह किसी भी औचित्य के साथ नहीं कहा जा सकता है कि यह उच्च न्यायालयों के समानांतर या उसी आधार पर न्यायालयों के गठन के लिए या आपराधिक न्यायालयों के गठन के लिए अनुकूल है जो उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ नहीं हैं। दूसरी ओर संहिता की धारा 4 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि भारतीय दंड संहिता के तहत सभी अपराधों की जांच की जाएगी, जांच की जाएगी, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। और उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि किसी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, जांच, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा "समान प्रावधानों" के अनुसार निपटा जाएगा, जो केवल उस समय लागू किसी अधिनियम के अधीन होगा जो ऐसे अपराधों की जांच, जांच, प्रयास या अन्यथा निपटने के तरीके या स्थान को विनियमित करता है। लेकिन यह धारा 2 के खंड (4) से सहसंबद्ध है जो "अपराध" को किसी ऐसे कार्य या चूक के रूप में परिभाषित करता है जो पशु-अतिक्रमण अधिनियम की धारा 20 के तहत शिकायत किए जाने वाले किसी भी कार्य को रोकने में तत्काल किसी भी कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया हो। अतः संहिता की धारा 6 प्रकृति के विशेष न्यायालयों के निर्माण को उचित नहीं ठहराती है:

विधेयक में प्रतिरूपित, और इसके विपरीत तर्क काफी है असमर्थनीय। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 6 का संदर्भ, 1952, समान रूप से व्यर्थ है। जबकि उस खंड में नियुक्ति का प्रावधान है कुछ अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, धारा 9 विनिर्दिष्ट वस्तुतः यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय प्रयोग कर सकता है, जहाँ तक वे कर सकते हैं अध्याय XXXI द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियाँ लागू होंगी और

उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 का XXXII "मानो विशेष का न्यायालय, न्यायाधीश एक सत्र न्यायालय है जो कोशिश कर रहा है के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर एक जूरी के बिना मामले उच्च न्यायालय"। धारा 6 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश हैं: इसलिए उच्च न्यायालय के अधीनस्थ और की योजना में फिट न्यायिक न्यायालयों और संविधान में निहित अधिकारियों की स्वतंत्रता ट्यूशन।

विधेयक में प्रावधान को उचित ठहराने का भी प्रयास किया गया है। के भाग XIV A के संदर्भ में विशेष न्यायालयों के निर्माण के लिए संविधान जो प्रशासनिक स्थापना का प्रावधान करता है न्यायाधिकरण। लेकिन ऐसे न्यायाधिकरण अपराधों की सुनवाई के लिए नहीं हैं।

भारतीय दंड संहिता में संदर्भित, और अच्छी तरह से कहा जा सकता है अर्ध-न्यायिक। इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि खंड द्वारा अनुध्यात विशेष न्यायालय 2 विधेयक का आधार उच्च न्यायालयों के समान नहीं होगा, और कम से कम कहने के लिए, कम या निम्न अदालतें होंगी।

विधेयक के खंड 7 में हालांकि यह प्रावधान है कि एक विशेष न्यायालय उच्च न्यायालय के एक "वर्तमान न्यायाधीश" की अध्यक्षता में और परीक्षा में यह मानते हुए कि मैंने अनुमान लगाया है कि विधेयक में इस तरह से संशोधन किया जाएगा कि

एक ऐसे व्यक्ति का नामांकन जिसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभाला हो। कभी भी, किसी उच्च न्यायालय के "वर्तमान" न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए अनुज्ञेय या उचित हो। विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायालय जो उससे कम या निम्नतर है उच्च न्यायालय। सभी संभावनाओं में, उच्च न्यायालयों के "वर्तमान" न्यायाधीश

विशेष न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीशों के रूप में सेवा करने से इनकार करेगा, और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत वे हो सकते हैं वहाँ सेवा करने के लिए मजबूर किया गया, या उनकी इच्छा के विरुद्ध आदेश दिया गया। वह भी वास्तविकता विधेयक के प्रावधानों को अव्यवहारिक बना देगी-भले ही वे थे

तर्क के लिए माना जाता है कि वे अन्यथा मान्य हैं और

संवैधानिक। किसी भी तरह से, यह संभावना है कि "वर्तमान" उच्च न्यायाधीश पीठासीन न्यायाधीश न्यायालयों के रूप में सेवा करने के लिए सहमत नहीं हो सकते हैं, विशेष के लिए वास्तविक है, और उनके इनकार से न्यायपालिका को शर्म आनी शुरू हो जाएगी और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी क्योंकि विधेयक में 7 खंड का प्रावधान है -

विशेष [1979] 2 एस. सी. आर. के पीठासीन न्यायाधीश का नामांकन।

न्यायालय के परामर्श से (या? की सहमति से) भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह भी एक ऐसा कारक है जिससे सावधान रहना चाहिए

विधेयक और इसके अधिनियमन से संबंधित, कि यह न केवल असंवैधानिक है, बल्कि इसके अच्छी तरह से काम करने की संभावना नहीं है और कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के निर्वहन के घोषित उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है

जिसका उल्लेख विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में किया गया है।

इस दृष्टिकोण का एक और कारण है। कानून के सामने समानता,

या, वर्तमान विवाद के संदर्भ में, आपराधिक मामले में समानता न्याय, सरकार के सभी लोकतांत्रिक रूपों का सार्वभौमिक लक्ष्य है, क्योंकि कोई भी कभी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि अपराध के लिए आरोपित सभी व्यक्तियों को, कानून में, बार ऑफ जस्टिस में एक ही पायदान पर खड़े हों। इस तरह की न केवल एक अभियुक्त और दूसरे अभियुक्त के बीच समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए लेकिन अभियोजन पक्ष और अभियुक्त के बीच भी। यह एक नहीं है एम. सी. आर. ई. "अधिकारों का विस्फोट" लेकिन, जैसा कि दिखाई देगा, यही हमारा संविधान है।

प्रत्येक नागरिक के लिए सावधानीपूर्वक, निश्चित रूप से और पूरी तरह से प्रदान किया गया है देश। संविधान का अनुच्छेद 21 अपने आप में इसे लागू करने के लिए पर्याप्त है। यह बाहर।

इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मैं यहाँ संविधान के अनुच्छेद 14 के किसी भी संदर्भ से बच रहा हूँ। कारण जो आवश्यक नहीं है जब लेख का दायरा और अर्थ 21 इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में परिभाषित किया गया है जिनमें शामिल हैं मेनका गांधी बनाम। भारत संघ। (1) यह मेरे लिए पर्याप्त होगा

जे. चंद्रचूड़ की निम्नलिखित राय का उल्लेख करें, जैसा कि वे तब थे।

" लेकिन केवल किसी प्रकार की प्रक्रिया का निर्देश अनुच्छेद 21 के अधिदेश को कभी पूरा नहीं कर सकते। प्रक्रिया.

कानून द्वारा निर्धारित निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होना चाहिए, नहीं काल्पनिक, दमनकारी या मनमाना। सवाल यह है कि क्या

कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया जो कम करती है या ले जाती है अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत व्यक्तिगत स्वतंत्रता उचित है या इसे अमूर्त या काल्पनिक रूप में नहीं माना जाना चाहिए पूरे कपड़े पहने सुनने के लिए प्रावधान जैसे विचार न्यायालय कक्ष विचारण के रूप में, लेकिन संदर्भ में, मुख्य रूप से, अधिनियम का उद्देश्य जिसे प्राप्त करना है और तत्काल स्थितियाँ जो उन लोगों को होती हैं जिन पर कर्तव्य का भार होता है अधिनियम के प्रशासन से निपटने के लिए बुलाया जा सकता है।" जे. भगवती ने अर्थ की विस्तृत जांच की और अनुच्छेद 21 में "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की सामग्री। उन्होंने यह दृष्टिकोण अपनाया है

अभिव्यक्ति सबसे व्यापक आयाम की है और यह एक प्रकार को शामिल करती हैवे अधिकार जो मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं। व्हिल। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का खनन उन्होंने अपने विचार और अन्य न्यायाधीशों के विचार इस प्रकार व्यक्त किए:

" क्या किसी प्रकार की प्रक्रिया का प्रिस्क्रिप्शन सही है या प्रक्रिया को किसी विशेष आवश्यकता का पालन करना चाहिए मन में? जाहिर है, प्रक्रिया मनमाना, अनुचित नहीं हो सकती है या अनुचित। यह वास्तव में विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया था महान्यायवादी जो अपनी सामान्य स्पष्टता के साथ स्पष्ट रूप से

प्रक्रिया कैसी भी मनमानी, दमनकारी या अन्यायपूर्ण हो सकती है कानून द्वारा निर्धारित। ए. के. में कुछ चर्चा हुई। प्रक्रिया की प्रकृति के संबंध में गोपालन का मामला अनुच्छेद 21 और कम से कम तीन के तहत निर्धारित किया जाना आवश्यक है

पाँच में से विद्वान न्यायाधीशों ने दृढ़ता से अपनी बात रखी इस दृष्टिकोण के पक्ष में कि प्रक्रिया कोई आरबी नहीं हो सकती है ट्रेरी, शानदार या दमनकारी प्रक्रिया। फजल अली, जे.

अल्पमत में था, टोपी कहने में सबसे दूर की सीमा तक गया प्रक्रिया में निर्धारित चार आवश्यक चीजें शामिल होनी चाहिए प्रो. संवैधानिक कानून पर विलिस की पुस्तक, अर्थात्, नोटिस, सुनवाई का अवसर, निष्पक्ष न्यायाधिकरण और सामान्य प्रक्रिया का क्रम। पतंजलि शास्त्री, जे., ज्यादा दूर नहीं गए। लेकिन उन्होंने कहा कि "कुछ बुनियादी सिद्धांत उभरे उन सभी प्रक्रियाओं के लिए ज्ञात निरंतर कारकों के रूप में और वे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के मूल थे।

महाजन, जे. ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 की आवश्यकता है कि

" किसी व्यक्ति के समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए। उसके जीवन या उसकी स्वतंत्रता के संबंध में निंदा की जा सकती है " और "यह शानदार, मनमाना और विरोध के विचार को नकारता है कार्यवाही के व्यापक रूप "। लेकिन इन सब के अलावा

ए. के. गोपालन के मामले में टिप्पणियाँ, जिनके पास महान हैं वजन, हम पाते हैं कि सिद्धांत रूप में भी तर्क की अवधारणा द्वारा विचार की गई प्रक्रिया में योग्यता का अनुमान लगाया जाना चाहिए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 21 "। अनुच्छेद 21 की गारंटी को पूरा करने के लिए, प्रक्रिया

इसलिए किसी आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए कानून द्वारा दोषी ठहराया जाना चाहिए उचित और उचित, और काल्पनिक दमनकारी या मनमाना नहीं। हालाँकि, विधेयक के खंड 5,7 और 8 में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

" 5. ऐसी घोषणा किए जाने पर कोई अभियोजन ऐसे अपराध के संबंध में केवल एक विशेष [1979] 2 एस. सी. में स्थापित किया जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा नामित न्यायालय और भारत के किसी भी न्यायालय में लंबित ऐसे अपराध के संबंध में कोई भी प्रतिभूति पक्ष एक निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा।

7. एक विशेष न्यायालय की अध्यक्षता भारत में उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश या एक व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसने भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया है। भारत का न्याय।

8. एक विशेष न्यायालय को उस अपराध में, जिसके संबंध में धारा 4 के तहत प्रधान, षड्यंत्रकारी या सहायक के रूप में घोषणा की जाती है, किसी भी प्रति पुत्र पर मुकदमा चलाने की अधिकारिता होगी और अन्य सभी अपराधों और अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 "।

कुल मिलाकर, खंड केवल केंद्र सरकार द्वारा नामित न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष न्यायालयों द्वारा अभियुक्त के मुकदमे के लिए प्रावधान करते हैं और खंड 4,5 और 7 विशेष न्यायालय को नामित करने की शक्ति निहित करते हैं जिसमें एक अभियुक्त पर विशेष रूप से उस सरकार में मुकदमा चलाया जाना है। व्यावहारिक रूप से यह विधेयक केंद्र सरकार को यह तय करने के लिए सक्षम बनाता है कि उसके कौन से नामित न्यायाधीश किस अभियुक्त पर मुकदमा चलाएंगे या दूसरे शब्दों में, किस अभियुक्त पर उसके किस नामित न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। वास्तव में श्री जेठमलानी ने बार में कहा है कि विधेयक में उल्लिखित अधिकांश विशेष अदालतें दिल्ली में स्थित होंगी। इसलिए यदि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा कई अदालतें बनाई जाती हैं, और उनकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नामित न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, तो दिल्ली में किसी भी विशेष मामले के लिए न्यायाधीश को नामित करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित होगी। जैसा कि प्रतीत होगा, इस तरह की प्रक्रिया को अनुच्छेद 21 के अर्थ के भीतर निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित नहीं कहा जा सकता है और यह संविधान की स्वतंत्रता पर गंभीर उल्लंघन के बराबर है।

न्यायपालिका। दीवानी और आपराधिक न्यायिक अदालतों के निर्माण के लिए संविधान में प्रदान की गई योजना का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है और पीठासीन न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की स्वतंत्रताउन अदालतों पर। जहाँ तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का संबंध है, केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा किसी विशेष मामले से निपटने वाले न्यायाधीश को नामित करने का प्रश्न नहीं उठता है और न ही उत्पन्न हो सकता है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालयों का संबंध है, धारा 9 (2)दंड प्रक्रिया संहिता का प्रावधान है कि प्रत्येक न्यायालयसत्र की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाएगी जिसे उच्च न्यायालय और धारा 11 (2) आरई के संबंध में एक समान प्रावधान करता है:

न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों और उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों को शक्तियां प्रदान करने के संबंध में भी यही ध्यान रखा गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कार्यपालिका के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी विशेष अभियुक्त के मुकदमे की अध्यक्षता करने के लिए किसी विशेष न्यायाधीश या न्यायाधीश को नियुक्त करने की अनुमति है। यह उचित, न्यायसंगत और उचित है और अभियुक्त को किसी भी संभावित उत्पीड़न से मुक्त करता है।

यह सराहना की जानी चाहिए कि समस्या बहुत बड़ी है। विशेष न्यायालयों के समक्ष विचारणों के मामले में महत्व

बिल। ए स्पष्ट है, एक उत्तराधिकारी सरकार के आदेश द्वारा एक परीक्षण, चाहे कितना भी उचित क्यों न हो, संदेह की मात्रा के साथ देखा जाता है। यदि किसी को ऐसा कहने की अनुमति दी जा सकती है, तो एक "उत्तराधिकारी परीक्षण", मोटे तौर पर, प्रतिद्वंद्वी को उसकी प्रारंभिक असुविधा और सत्ता या अधिकार से विस्थापन के बाद दूसरी बार मारने का प्रयास करता है।

अभियुक्त जो उच्च राजनीतिक स्थिति रखता है, उसके राजनीतिक भविष्य को नष्ट करने का प्रभाव हो सकता है। यह चीजों की प्रकृति से ही है, छिपे हुए सुस के ऐसे आरोपी के दिमाग को निष्क्रिय करना मुश्किल है यह धारणा कि मुकदमा राजनीतिक विचारों और इच्छा से प्रेरित है न्यायपूर्ण और निष्पक्ष नहीं होना, या उसे यह समझाना कि यह अंततः नेतृत्व करेगा न्याय। इसलिए यह उन लोगों का प्रयास होना चाहिए जो मुकदमे का आदेश दे रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं करना जो इस तरह के संदेह को दूर से भी उचित ठहरा सके। वे. क्या वास्तव में वे हर संबंधित को समझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिसमें शामिल हैं -

अभियुक्त को, कि उनका आदेश देने का सबसे अच्छा इरादा था मुकदमा चलाया और एक निष्पक्ष और सीधी प्रक्रिया प्रदान की थी, और मुकदमे के लिए सबसे स्वच्छ न्यायाधीश, खुले और निडर तरीके से। कि न केवल टालने योग्य आलोचना को रोकेंगे बल्कि इसकी महिमा को भी बनाए रखेंगे। अपने सही अर्थों में कानून का शासन। इसके अलावा, यदि मुकदमे के परिणाम को दोषसिद्धि के साथ लाना है एक पूरे के रूप में लोग, और उन्हें "सच" के साथ परिचित करने के लिए है

उन व्यक्तियों का चरित्र जिन्होंने अपराध किए हैं लोकतांत्रिक संस्थानों का अस्तित्व और राजनीतिक स्वच्छता यह उन लोगों के हित में है जो में निर्दिष्ट घोषणा करते हैं अभियुक्त सहित सभी को यह समझाने के लिए कि विधेयक का खंड 4

मुकदमा उद्देश्य में शानदार नहीं है और उन लोगों को उजागर नहीं करता है जिनका सामना करना पड़ रहा है किसी आदेश पर किसी अन्य अभियुक्त द्वारा लिए गए जोखिम से अधिक सामान्य कानून के तहत गैर-कानूनी मुकदमा। इस तरह का आश्वासन, कि यह कोई पूर्व

निर्धारित परिणाम नहीं है, और यह कि अभियुक्त को डरने की कोई बात नहीं है न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से, एक की मूल आवश्यकता है

" उत्तराधिकारी परीक्षण "। मानव गरिमा एक अवधारणा है जो पूर्व में निहित है हमारे संविधान में जो कुछ भी है और जो कुछ भी यह प्रदान करता है, उसके माध्यम से चलता है।

इसलिए यह आवश्यक है कि यह खजाना अमूल्य हो सायन और हमारे सभी साथी नागरिकों की ठोस आशा, जिनमें वे भी शामिल हैं उनके खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए मुकदमों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऊपर उल्लिखित विधेयक के खंड निम्न के अवमूल्यन में हैं - न्यायिक भवन की भव्यता इतनी शानदार और निश्चित रूप से बनाई गई थी संविधान द्वारा, और की स्वतंत्रता पर एक गंभीर प्रवेश है न्यायपालिका। इस संबंध में लियानगे और अन्य का उल्लेख किया जा सकता है।

वी. रेजिना (1)। उस मामले में, अपीलार्थियों पर एक द्वारा मुकदमा नहीं चलाया गया था सामान्य प्रक्रिया के अनुसार न्यायाधीश और जूरी, लेकिन तीन द्वारा मंत्री द्वारा नामित सीलोन के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्याय। एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी कि नामांकन और जिस धारा के तहत इसे बनाया गया था, वह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से ओ. बी. को बरकरार रखा इस आधार पर कि नामांकन की शक्ति को प्रदान किया गया मंत्री न्यायाधीशों द्वारा अभ्यास में हस्तक्षेप था राज्य की सख्त न्यायिक शक्ति का सर्वोच्च न्यायालय उनमें निहित है उनकी नियुक्ति के आधार पर या उसके अपमान में था, और था एक ऐसी शक्ति जिसे तब तक "हमेशा जूडी द्वारा बहिष्कृत किया गया था राज्य की न्यायिक शक्ति के प्रयोग के हिस्से के रूप में, और न्यायपालिका के बाहर किसी में भी स्थापित नहीं किया जा सकता था। द. इसके बाद कानून में संशोधन किया गया और इसके लिए अनुमति दी गई मुख्य न्यायाधीश तीन न्यायाधीशों को नामित करेंगे। लेकिन प्रिवी काउंसिल, संशोधित प्रावधान लेने के बाद दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर प्रभाव, सिद्धांत रूप में सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार रखा, और

अभिनिर्धारित किया कि न्यायपालिका की शक्ति को "हड़पा या हड़पा" नहीं जा सकता है कार्यपालिका या विधायिका द्वारा उल्लंघन किया गया। प्रिवी काउंसिल संशोधित अधिनियम के अन्य आपत्तिजनक प्रावधानों की जांच की और अभिनिर्धारित किया कि वे अमान्य थे। वे प्रावधान प्रासंगिक नहीं हैं वर्तमान मामले के उद्देश्य, लेकिन मैं निम्नलिखित निष्कर्ष निकालने में मदद नहीं कर सकता उनके लोरासिनिप्स द्वारा सावधानी बरतने के लिए,

" एक बार क्या किया जाता है, यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो फिर से किया जा सकता है कम संकट और कम गंभीर परिस्थितियों में; और इस प्रकार न्यायिक शक्ति का क्षरण हो सकता है।

एक महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति को हड़पने और इसे कार्यपालिका को सौंपने के लिए वर्तमान विधेयक में किए गए प्रयास की तरह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक गंभीर अतिक्रमण है और यह गंभीर साजिशों से भरा हुआ है। इसलिए इसे अनिवार्य रूप से शुरुआत में ही नीचे रखा जाना चाहिए क्योंकि यह अन्यथा एक ऐसी संभावना को जन्म दे सकता है जो बहुत ही भयावह है।

परिकल्पना की गई और मंजूरी लेने की अनुमति देने के लिए बहुत खतरनाक है कानून।

राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट प्रश्न का मेरा उत्तर इसलिए होगा।

बशर्ते कि मेरे प्रभु मुख्य न्यायाधीश द्वारा बताए गए तीन दोषों के अलावा, विधेयक के खंड 5 और 7 संवैधानिक रूप से अमान्य हैं, और मैं तदनुसार अपनी राय दूंगा।

पीबीआर.

19-978 एस. सी. आई./78